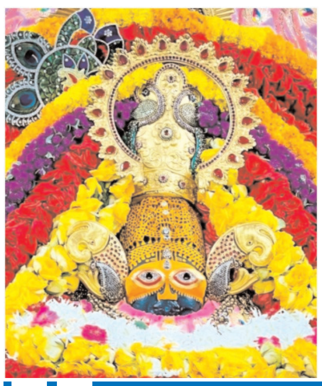

RNI No. GUJHIN/2010/35230

# महानगर मेट्रो

राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र

कार्यालय :- सी-8 रिची हाउस, स्वामी नारायण मंदिर के सामने मणिनगर अहमदाबाद गुजरात-380008

महानगर मेट्रो
राष्ट्रीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र, प्रेस नोट एवं विज्ञापन के लिए कार्यालय पर सम्पर्क करें
सरबजीत माकन
+91-9638877700
mahanagarmetro7@gmail.com

वर्ष :15 । अंक:361। पेज:।12 mahanagarmetro7@gmail.com || अहमदाबाद, 22 अगस्त 2026 (शनिवार) || सम्पादक - सरबजीत माकन (9638877700)।। मूल्य :- 1.50 रु.-/


### राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में घमासान

# ‘जब तक मैं पत्र नहीं देख लेता...’

## ● चंपत राय की चिट्ठी पर बोले नृपेंद्र मिश्रा- मीडिया विवाद खड़ा कर रहा

**गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद चंपत राय का 9 पन्नों का दूसरा लेटर सामने आया था। इसमें उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर कई दावे किए।**

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने हाल ही में राम मंदिर के संघर्ष से लेकर इसके निर्माण और व्यवस्था के विभिन्न आयामों को दर्शाते हुए कई पन्नों का एक पत्र जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर निर्माण के सारे कार्य मंदिर निर्माण समिति के निर्णय पर होते थे। कोई भी कार्य चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के निर्णय के बिना नहीं हुआ। अब नृपेंद्र मिश्रा ने इस पर जवाब

दिया है। चंपत राय द्वारा मनमाने फैसले लेने का आरोप लगाने वाले 9 पन्नों के पत्र की मीडिया रिपोर्टों पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, ‘मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है। जब तक मैं पत्र नहीं देख लेता, तब तक मैं यही कहूंगा कि यह सब आप मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। अगर ऐसा कोई पत्र है भी तो उसमें चंपत राय ने ऐसी कोई आलोचना नहीं की होगी। मीडिया इसे मेरे सामने सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए पेश कर रहे हैं। ‘

### नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर चंपत राय के दावे

चंपत राय ने अपने लेटर में आगे लिखा था, ‘कोई भी काम नहीं जो समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के निर्णय के बिना हुआ हो। अगर कोई अलग निर्णय हुआ तो वह मान्य नहीं हुआ और उसे हटा दिया गया। चंपत राय ने पत्र में आगे कहा कि मंदिर निर्माण के सभी निर्णयों में नृपेंद्र ने सदैव अपने को प्रमुख रखा। उन्होंने विस्तार से मंदिर निर्माण में नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका का जिक्र करते हुए उनके एकतरफा फैसलों का भी जिक्र किया।

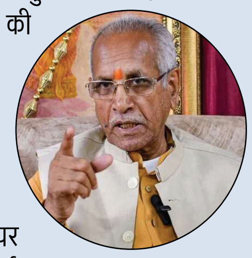

चंपत राय ने पत्र में कहा, ‘राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी थे और नृपेंद्र को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके सुझाव पर लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई।’ चंपत राय ने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण समिति में अपनी पसंद के लोगों को शामिल किया। इनमें से कुछ लोग 6 साल के दौरान केवल एक-दो बार ही अयोध्या आए।

# सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट की व्यवस्था पर उठाए सवाल

## ● दो वकीलों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द किया

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून ‘स्टिलबॉर्न’ यानी जन्म से ही दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें किसी नए अपराध को परिभाषित किए बिना सजा का प्रावधान कर दिया गया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि कानून में केवल ‘गैंग’ और ‘गैंगस्टर’ की परिभाषा दी गई है, जबकि जिन गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है, वे पहले से ही IPC और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत दंडनीय हैं। शीर्ष अदालत ने कहा किसी अलग अपराध का सृजन किए बिना सीधे सजा का प्रावधान करना कानून की गंभीर खामी है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि हिंसा रोकने के नाम पर बनाया गया यह कानून कई मामलों में निर्दोष और अनजान नागरिकों के खिलाफ हिंसा और दमन को बढ़ावा देता नजर आता है।

### शीर्ष अदालत ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, 1986 को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि इस कानून में जिन अपराधों का जिक्र है,वे पहले से ही भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य कानूनों के तहत दंडनीय हैं। ऐसे में यह कानून कोई नया अपराध परिभाषित नहीं करता, बल्कि केवल व्यक्ति को ‘गैंगस्टर’ का दर्जा देता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी समेत एक्ट में सूचीबद्ध सभी गतिविधियां पहले से ही दूसरे कानूनों के तहत अपराध हैं। यूपी गैंगस्टर एक्ट केवल इन अपराधों में शामिल व्यक्ति को ‘गैंगस्टर’ घोषित कर सजा का प्रावधान करता है।

## सार-समाचार

### रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द

**● केंद्र ने नहीं दी राजनीतिक मंजूरी**

**नई दिल्ली।** तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को केंद्र सरकार से अमेरिका जाने की इजाजत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रेड्डी फिलहाल लंदन में हैं। यहां से उनकी योजना अमेरिका जाने और 30 अगस्त को हैदराबाद वापस लौटने की थी। सीएमओ की एक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाले आधिकारिक ‘तेलंगाना-राइजिंग’ प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका का दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। मंत्रालय ने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई है।’ सीएमओ ने कहा कि रेड्डी अमेरिका के बोस्टन जाने के बजाय 23 अगस्त को लंदन से हैदराबाद लौटेंगे। राज्य सरकार ने नीति और प्रोटोकॉल के मुताबिक ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा के लिए केंद्र से अनुमति का अनुरोध किया था लेकिन केवल ब्रिटेन यात्रा की ही मंजूरी मिली।

### उपराष्ट्रपति ने जेपी नड्डा का जाना हालचाल

**नई दिल्ली।** उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर जाकर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने एक्स पोस्ट में लिखा, आज जेपी नड्डा के आवास पर उनसे भेंट की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। उनके शीघ्र स्वस्थ होने, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करता हूं।

### इंदौर में स्वाइन फ्लू से पीड़ित महिला की मौत

**इंदौर**: मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई है। वह उज्जैन की रहने वाली थी और कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल से छुट्टी के बाद उज्जैन गई तो वहां मौत हो गई। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी छुपाने को लेकर अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया है। स्वाइन फ्लू के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कोकिलाबेन अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती उज्जैन की 60 वर्षीय महिला की जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बावजूद इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई।

# ‘पी’ को पहले पिछड़ा फिर पंडित बताया

## ● किसी दिन पाकिस्तान भी कर देंगे | सपा के पीडीए नारे पर सीएम योगी का तंज

**एजेंसी**

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पांचवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कल्याण सिंह ने भारत के सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं...’पी’ की परिभाषा पहले ‘पिछड़ा’ बताया, फिर ‘पंडित’ कर दिया। किसी दिन ‘पी’ की परिभाषा ‘पाकिस्तान’ भी कर देंगे...। ‘

**सपा पर लगाया अपमान करने का आरोप**

सीएम योगी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में कल्याण सिंह की भूमिका को याद किया और सपा नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह के जीवन को ‘हिंदू गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाना चाहिए।सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘बाबूजी’ (कल्याण सिंह) दबाव में आकर काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। योगी ने कहा, ‘वे कहते थे कि कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता और उन्होंने जीवन भर अपने इस वचन को निभाया। ‘

योगी ने कहा कि कल्याण सिंह ने आरएसएस के मार्गदर्शन और संतों के समर्थन में विहिप के नेतृत्व वाले आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। योगी ने कहा कि कल्याण सिंह ने अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी लेकिन कहा कि राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई जाएगी।

### ‘ये वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर बैठेंगे सुखा डालेंगे’

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साक्षी जी महाराज ने ठीक कहा है, ये लोग कब क्या बोलें कोई भरोसा नहीं है। ये वैसे गिद्ध है, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे, उसको सुखा डालेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कन्नौज में बाबा साहेब के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन आंबेडकर का नाम हटा दिया। मंत्री असीम अरुण ने जानकारी दी तो दोबारा बाबा साहेब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया।

### केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, बोले-

# प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश से भी पीछे हुआ भारत

**एजेंसी**

**नई दिल्ली ।** आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने दावा किया कि वर्ष 2026 में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का सपना दिखाया गया था, आज वह प्रति व्यक्ति आय के मामले में अपने पड़ोसी देश से पीछे पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, वर्ष 2026 में भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,800 डॉलर है, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,900 डॉलर तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि यह स्थिति देश के लिए चिंता का विषय है। केजरीवाल ने वर्ष 2014 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,600 डॉलर थी, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय करीब 1,100 डॉलर थी। उनके अनुसार, उस समय भारत बांग्लादेश से काफी आगे था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है।

# सीमाएं सुरक्षित हुए बिना भारत सुरक्षित नहीं रह सकता : अमित शाह

**बोले-घुसपैठ रोकना जरूरी, बीएसएफ को जमीन देने में हुई देरी**

**एजेंसी**

**सिलीगुड़ी ।** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक न तो पश्चिम बंगाल और न ही भारत सुरक्षित रह सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनके कई बार अनुरोध करने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई।

**गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सीएम को दी बधाई**

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) या सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कार्यक्रमों में कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। शाह ने कहा कि एसएसबी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और सीमावर्ती बलों के समारोहों से पूर्व मुख्यमंत्रियों की दूरी ने गलत संदेश दिया। गृह मंत्री ने कहा कि वह आजादी के बाद देश में बनीं पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को उचित सम्मान नहीं दिए जाने से दुखी थे।

### ममता बनर्जी ने नहीं दी जमीन

गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी स्थित एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि मैंने बीएसएफ द्वारा सीमा पर बाड़ लगाए जाने के लिए जमीन देने की कई बार गुहार लगाई लेकिन (पूर्व मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी ने इसे अनसुना कर दिया। मैं सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए 1,129 एकड़ जमीन की मांग 2014 से कर रहा था। राज्य में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद ही हमें यह जमीन मिली।

# हंगामे के बीच राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल

### कांग्रेस विधायकों ने किया बहिष्कार

**एजेंसी**

**जयपुर ।** राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को हंगामे और नारेबाजी के बीच समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश किया गया। राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में यह बिल पेश किया, जिस पर बाद में चर्चा होगी और फिर इसे पास किया जाएगा। दिन की शुरुआत से ही सदन में बार-बार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाया कि कांग्रेस विधायकों को विधानसभा के गेट पर रोका गया और इस पर चर्चा की मांग की। उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा भी उठाना चाहा, जो स्कूलों का निरीक्षण करने गए थे। स्पीकर ने प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस विधायक वेल में आ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को ‘भगोड़ा’ बताते हुए पोस्टर दिखाए। जवाब में भाजपा विधायकों ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी

को ‘भगोड़ा’ और ‘चोर’ कहते हुए नारे लगाए। हंगामा बढ़ने पर विधानसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब सदन शुक्रवार दोपहर 1 बजे फिर शुरू हुआ, तब भी विरोध जारी रहा। इसी शोर-शराबे के बीच मंत्री जोगाराम पटेल ने यूसीसी बिल पेश कर दिया। बिल पर बाद में बहस होगी और फिर वोटिंग होगी। कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार करते हुए दोपहर 1:21 बजे वॉकआउट कर दिया। टीकाराम जूली ने कहा कि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की चिंताओं को नजरअंदाज कर अपना विधायी काम पूरा करने की कोशिश कर रही है। स्पीकर ने कांग्रेस सदस्यों से कहा था कि पहले वित्त विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों को पास होने दें। विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच तीखी बहस भी हुई। राज्य सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस को ‘लोकतंत्र का हत्यारा’ बताया और कहा कि कांग्रेस के पास उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आरोप लगाया कि गुरुवार को कांग्रेस विधायक अपने साथ बाहरी लोगों और ‘असामाजिक तत्वों’ को लेकर आए थे और उन्हें विधानसभा परिसर में लाने की कोशिश कर रहे थे।

# पैलेट गन विवाद : जेपी नड्डा का तीखा हमला, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बताया ‘कैमराजीवी’

**एजेंसी**

**नई दिल्ली:** लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। इस दौरान वह पैलेट गन पीड़ित के समर्थन में थाने में ही धरने पर बैठ गए। यहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राहुल गांधी के धरने पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश एक बार फिर उस सस्ती लोकप्रियता पाने वाली राजनीति को देख रहा है, जिसका प्रदर्शन आज राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर किया। राहुल गांधी का आज का धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया का ध्यान खींचने की भूख का प्रतीक है।

जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और एक पूर्व जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले की जांच कर रही है, तो राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के सामने बैठकर क्या साबित करना चाहते हैं।

## राहुल गांधी, बोले- पैलेट गन से दिल के पास लगे हैं छर्रे, आंख की रोशनी खतरे में


**एजेंसी**

**नई दिल्ली:** लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। इस दौरान वह पैलेट गन पीड़ित के समर्थन में थाने में ही धरने पर बैठ गए। यहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राहुल गांधी के धरने पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश एक बार फिर उस सस्ती लोकप्रियता पाने वाली राजनीति को देख रहा है, जिसका प्रदर्शन आज राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर किया। राहुल गांधी का आज का धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए। उन्होंने कहा

कि यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया का ध्यान खींचने की भूख का प्रतीक है। जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और एक पूर्व जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले की जांच कर रही है, तो राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के सामने बैठकर क्या साबित करना चाहते हैं।

## हदाद में कथित वर्ली मटका जुए के आरोप, पुलिस की परफॉर्मेंस पर सवाल

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**बनासकांठा।** इससे पहले, हदाद इलाके में वर्ली मटका जुए के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। हदाद इलाके में वर्ली मटका के वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस की परफॉर्मेंस पर सवाल उठे थे कि पुलिस ने वीडियो की जांच क्यों नहीं की या एक्शन क्यों नहीं लिया। ऐसे में, लोकल लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बार-बार जानकारी या शिकायतें आ रही हैं, तो अब तक कितनी असरदार कार्रवाई हुई है? क्या पहले वायरल हुए वीडियो की जांच का नतीजा पब्लिक किया गया है? और अगर ऐसी एक्टिविटी के आरोप फिर से लग रहे हैं, तो क्या पुलिस उस जगह की जांच करेगी और लीगल एक्शन लेगी? हदाद में वर्ली मटका के कथित बिजनेस की पुलिस और हायर अथॉरिटीज़ से बिना किसी भेदभाव के जांच करने और सच सामने लाने की मांग की जा रही है।

## गुजरात में शराबबंदी पर फिर उठे सवाल, भावनगर की घटना के बाद अहमदाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**अहमदाबाद।** गुजरात में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब के कारोबार और उससे जुड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर एक बार फिर पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भावनगर की दुखद घटना के बाद राज्य में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अहमदाबाद में पुलिस ने महज दो दिनों में शराब से जुड़े 215 मामले दर्ज किए हैं। अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई के साथ कई कथित बूटलेगरों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं। वहीं स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने भी शहर के कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध शराब जब्त की है।हालांकि, सवाल यह है कि ऐसी कार्रवाई कितने समय तक जारी रहती है। आरोप है कि बड़े हादसे या विवाद के बाद पुलिस कुछ दिनों के लिए विशेष अभियान चलाती है, लेकिन अभियान समाप्त होने के बाद अवैध शराब के नेटवर्क फिर सक्रिय हो जाते हैं। नागरिकों का कहना है कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए केवल अस्थायी ड्राइव पर्याप्त नहीं है। अवैध शराब की बिक्री, सप्लाई और पूरे नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि कानून का पालन निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के हो।

## कबाड़ से बोतलों में 'फ्लेवर' मिलाकर महंगी शराब बनाने का खतरनाक खेल पकड़ा गया

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**अहमदाबाद।** एक तरफ जहां गुजरात में पुलिस की तरफ से स्पेशल ड्राइव चलाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद के निकोल इलाके से सामने आए एक मामले ने नकली शराब के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है जो लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। निकोल पुलिस ने क्रिमिनल हिस्ट्री वाले एक युवक को नकली शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि नकली शराब बनाने का मास्टरमाइंड दिनेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। इस स्कैम में जो चौंकाने वाला तरीका सामने आया है, उसे देखकर कानून के रखवाले भी हैरान हैं। पुलिस जांच में सामने आई डिटेल्स के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी सुनील मखीजा नकली शराब के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को संभाल रहा था। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दिनेश इस खतरनाक खेल का मास्टरमाइंड है। दिनेश कबाड़ियों से महंगे ब्रांड की शराब की खाली बोतलें लेता था। फिर वह बहुत सस्ती और घटिया क्वालिटी की शराब में केमिकल फ्लेवर मिलाकर उसे महंगे ब्रांड का बताकर पैक कर देता था। लोगों की गद्दी हिला देने वाली यह मिलावटी शराब ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी और नशेड़ियों की जान से सीधे खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस ने सुनील मखीजा से नकली शराब की बोतल जब्त की है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जांच के दौरान यह भी साफ हो गया है कि गिरफ्तार सुनील और फरार आरोपी दिनेश दोनों पहले भी कई अपराधों में शामिल रहे हैं और उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। फिर भी, वे बिना किसी झिझक के शहर के बीचों-बीच इतना खतरनाक नेटवर्क चला रहे थे, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान लगाता है।

## तलोद से ट्रिप पर निकले 40 स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ी, बोटाद में अफरा-तफरी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**बोटाद।** एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां ट्रिप की खुशी पल भर में चिंता में बदल गई। साबरकांठा के तलोद से ट्रिप पर निकले 90 स्टूडेंट्स में से करीब 35 से 40 स्टूडेंट्स की तबीयत देर रात अचानक बिगड़ गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दो बसों में बोटाद पहुंचे इन बच्चों को बुखार, सर्दी और बेचैनी के लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज के लिए बोटाद के सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। देर रात सिविल हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में बच्चे मरीज पहुंचते ही सिस्टम की पोल खुल गई। गंभीर आरोप लगे हैं कि हॉस्पिटल में पर्याप्त बेड की सुविधा नहीं है। एक तरफ बीमार बच्चे इलाज के लिए भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जरूरी सुविधाओं की कमी थी। ऐसे संकट में, लोकल रिक्शा एसोसिएशन आगे आया और बच्चों के लिए चादरें और दूसरी बेसिक सुविधाओं का इंतज़ाम करके इंसानियत की एक बड़ी मिसाल पेश की। बीमार स्टूडेंट्स की उम्र और हालत को ध्यान में रखते हुए, सिविल हॉस्पिटल में तुरंत पीडियाट्रिशियन डॉक्टरों की एक टीम तैनात करने की ज़ोरदार मांग की गई है। मौसम में बदलाव या फ़ूड पॉइज़निंग की वजह से तबीयत बिगड़ी है, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिससे पेरेंट्स में चिंता की लहर है। जब स्कूल ट्रिप के दौरान बच्चों की सुरक्षा और सेहत पर इतना बड़ा सवाल उठता है, तो सिविल हॉस्पिटल का खराब परफॉर्मेंस सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। क्या सरकारी हॉस्पिटल ऐसे संकट से निपटने में काबिल नहीं हैं? पाक्को गुजरात न्यूज़ इन सभी बीमार स्टूडेंट्स की सेहत और हॉस्पिटल सिस्टम के काम करने के तरीके पर लगातार नज़र रखेगा।

# करजण में टेंडर का खेल!

## करजण में 8 करोड़ के VGL टेंडर पर बड़ा विवाद L-1 ठेकेदार को धमकी के बाद L-2 को काम देने के आरोप

# करजन में टेंडर माफिया और दलबदलू नेता की दबंगई! VGL गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में करोड़ों के घोटाले का आरोप

## L-1 ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देकरL-2 को 9% अधिक कमीशन पर सौंपा काम

महानगर मेट्रो ब्यूरो/पवन माकन

**करजण।** तालुका में वडोदरा गैस लिमिटेड की गैस लाइन बिछाने के काम से जुड़ा कथित टेंडर विवाद अब गंभीर आरोपों में बदलता नजर आ रहा है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में L1 ठेकेदार को काम शुरू करने से रोकने के लिए कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई और बाद में दोबारा टेंडर प्रक्रिया में L-2 ठेकेदार को अधिक दर पर काम दिए जाने से सरकारी धन पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक, गैस लाइन परियोजना के लिए ङ्कत्नरु की ओर से जारी टेंडर में तीन कंपनियों ने भाग लिया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4.5 प्रतिशत के आधार पर करीब 8 करोड़ रुपये का काम रु1 ठेकेदार को मंजूर किया गया था। आरोप है कि टेंडर मिलने के बाद रु1 कंपनी के मालिक को कथित तौर पर धमकी दी गई कि वह काम शुरू न करे, अन्यथा उसकी जान को खतरा हो सकता है। धमकी के कारण ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया और VGL को दोबारा टेंडर प्रक्रिया अपनानी पड़ी। दूसरी टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि प्रभावशाली राजनीतिक संपर्क रखने वाले कुछ लोगों और कथित टेंडर माफिया के दबाव में L-1 प्रक्रिया को दरकिनार कर L-2 पक्ष को करीब 9 प्रतिशत अधिक दर पर काम दिया गया। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सवाल यह है कि जब पात्र L-1 ठेकेदार उपलब्ध था, तो उसे हटाकर अधिक दर वाले ठेकेदार को काम देने का निर्णय किस आधार पर लिया गया और इससे सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ा। इस मामले में करजण नगर पालिका के वित्तीय नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक, परियोजना में नगर पालिका को पहले करीब 36 लाख रुपये का योगदान करना था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में कथित बदलाव के बाद यह बोझ बढ़कर करीब 72 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। परियोजना के लिए मुख्यमंत्री फंड से करीब 8 करोड़ रुपये मिलने की बात कही जा रही है, जबकि अतिरिक्त राशि नगर पालिका को वहन करनी है। ऐसे में नागरिकों का सवाल है कि यदि अधिक दर पर काम दिया गया है तो अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी किसकी होगी। सूत्रों के हवाले से यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि टेंडर से जुड़े प्रभावशाली लोगों में नगर पालिका के एक ताकतवर पार्षद का नाम सामने आ रहा है और कथित तौर पर उनके किसी करीबी के नाम से काम हासिल किया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यदि किसी निर्वाचित नगर पालिका सदस्य या उसके करीबी का इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित साबित होता है, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और हितों के टकराव के पहलू की भी जांच जरूरी होगी।

### उठ रहे हैं कई बड़े सवाल

इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल रु1 ठेकेदार को कथित धमकी दिए जाने का है। यदि किसी ठेकेदार को वास्तव में धमकाकर सरकारी काम से हटाया गया, तो यह केवल टेंडर प्रक्रिया का मामला नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था और आपराधिक दबाव का भी विषय बनता है। दूसरा सवाल यह है कि 4.5 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध L-1 ठेकेदार के रहते 9 प्रतिशत अधिक दर वाले L-2 को काम देने का निर्णय किन नियमों और परिस्थितियों में लिया गया। इसके अलावा यह भी जांच का विषय है कि दोबारा टेंडर की जरूरत क्यों पड़ी, पहली प्रक्रिया में रु1 की पात्रता क्या थी, काम न शुरू करने के पीछे वास्तविक कारण क्या था और दूसरी प्रक्रिया में किस अधिकारी या प्राधिकरण ने अंतिम मंजूरी दी। टेंडर की पूरी फाइल, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय बोली, वर्क ऑर्डर और संबंधित स्वीकृतियों की जांच से

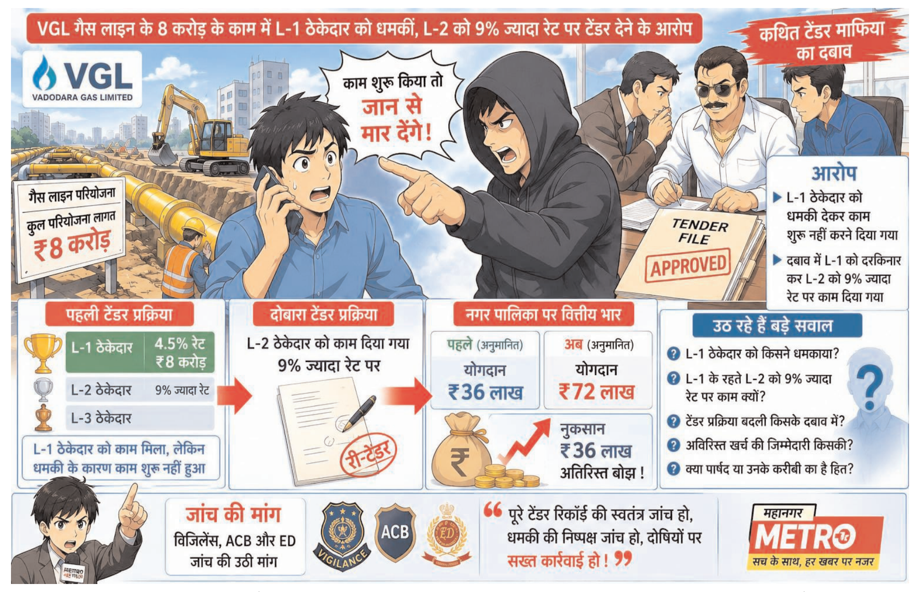


ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

### विजिलेंस, ACB और ED जांच की मांग

मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर हाई-लेवल जांच की मांग उठ रही है। मांग है कि ङ्कत्नरु और नगर पालिका से जुड़े पूरे टेंडर रिकॉर्ड की स्वतंत्र विजिलेंस जांच कराई जाए और कथित धमकी की शिकायत की पुलिस स्तर पर भी निष्पक्ष जांच हो। इसके साथ ही, यदि जांच में भ्रष्टाचार, रिश्वत, बेनामी संपत्ति या सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े ठोस साक्ष्य सामने आते हैं, तो संबंधित सक्षम एजेंसियों द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए।

जनता की ओर से यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि सरकारी परियोजनाओं में टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी है या प्रभावशाली लोगों के दबाव में नियम बदले जा रहे हैं। फिलहाल लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन 8 करोड़ रुपये की परियोजना और कथित तौर पर बढ़ी हुई दरों के कारण यह मामला गंभीर वित्तीय जांच की मांग करता है महानगर मेट्रो इस पूरे मामले में उठ रहे आरोपों, टेंडर प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल पर नजर बनाए रखेगा। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और संबंधित विभागों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही यह होगा कि टेंडर प्रक्रिया में वास्तव में कोई अनियमितता हुई या नहीं।

## गुजरात में एजुकेशन पर करोड़ों खर्च और ज़ीरो रिज़ल्ट

# गुजरात यूनिवर्सिटी टेंडर के नाम पर करप्शन में लिप्तः कांग्रेस का सनसनीखेज आरोप

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**अहमदाबाद।** गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्सपर्सन डॉ. पार्थिवराजसिंह कथवाडिया ने गुजरात यूनिवर्सिटी में करप्शन को सामने लाने के लिए एक सरप्राइज प्रोटेस्ट डेमोंस्ट्रेशन का नेतृत्व किया। हाल के दिनों में, ऐसा लगता है जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी ने पक्षियों की अलग-अलग प्रजातियों को खत्म करके करप्शन करने का बीड़ा उठा लिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्सपर्सन डॉ. पार्थिवराजसिंह कथवाडिया ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी का बॉटनिकल गार्डन, जिसे 1960 से बचाकर रखा गया था, गायब हो गया है, साथ ही तीन नेचुरल वेटलैंड भी गायब हो गए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने टेंडर के नाम पर करप्शन किया है। चांसलर बदलते हैं तो मकसद, कॉन्ट्रैक्टर और टेंडर सब बदल जाते हैं।गुजरात यूनिवर्सिटी के उस समय के वाइस चांसलर हिमांशुभाई पंड्या के राज में एक आर्बोरेटम बनाने का फैसला हुआ और 9.55 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया। काम 18 महीने में पूरा होना था। जिसमें जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसकी कंसल्टिंग एजेंसी ऑक्टर्स नाम की कंपनी को काम दिया गया। उस कंपनी ने आधे-अधूरे कचरे की तरह तीन डोम खड़े कर दिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी और कंसल्टेंसी एजेंसी ने करोड़ों का गबन कर लिया। फिर चांसलर बदले और नीरजा गुप्ता वाइस चांसलर बन गईं और वह एक अलग कॉन्ट्रैक्ट ले आईं। जो आर्बोरेटम बनना था, उसकी जगह 15.56 करोड़ रुपये का नक्षत्र वन प्रोजेक्ट आया। इसे छह महीने में पूरा होना था, जिसके बाद संरक्षित बॉटैनिकल गार्डन पर बुलडोजर चला दिया गया।

### नक्षत्र वन के नाम पर 'कला किसने की', यह सवाल

चांसलर नीरजा गुप्ता ने नक्षत्र वन के लिए 15.56 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करण कंस्ट्रक्शन को दिया था, जबकि टोरसन एजेंसी को कंसल्टेंसी के लिए रोक दिया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के बॉटनिकल गार्डन में 150 से ज़्यादा तरह के पौधे, पेड़ और झाड़ियाँ थीं, जिनमें से कुछ बहुत कम मिलती-जुलती थीं। जिस गार्डन में बॉटनी और जियोलॉजी के स्टूडेंट रिसर्च कर रहे थे, उस पर यूनिवर्सिटी ने बुलडोज़र चला दिया। यह गार्डन राष्ट्रीय पक्षी मोर का ब्रीडिंग ज़ोन भी था,

और मोर का घर भी तोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का ब्रीडिंग ज़ोन खत्म कर दिया गया। एक समय में गार्डन में 40 से ज़्यादा मोर, जिनमें कई दूसरी तरह के मोर भी शामिल थे, पाए जाते थे। जब बॉटनी के हेड से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बॉटनिकल गार्डन पर बुलडोज़र चलाए जाने की वजह से राष्ट्रीय पक्षी मोर का ब्रीडिंग ज़ोन खत्म हो गया, उसकी ब्रीडिंग कम हो गई है और कुत्ते भी उस पर हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से उसकी संख्या कम हो गई है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसे बचाना सबका कर्तव्य है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों को राष्ट्रीय पक्षी के प्रति कोई सम्मान नहीं है और अधिकारी इसे बचाने में विफल रहे हैं। यह छात्रों के लिए शोध के लिए बहुत उपयोगी था। सवाल यह है कि संरक्षित वनस्पति उद्यान पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया? वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख या कर्मचारी को वनस्पति उद्यान में किए जा रहे एक भी प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं है और यह चौंकाने वाला है कि उस प्रोजेक्ट में एक भी अधिकारी शामिल नहीं है। विकास के नाम पर, विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों कांग्रेस बिहाइंड द क्लासरूम नाम से दो किताबें प्रकाशित की थीं, जिसमें विश्वविद्यालय ने कॉफी टेबल बुक के प्रारूप में वनस्पतियों और जीवों की तस्वीरें प्रकाशित की थीं। गुजरात विश्वविद्यालय में, तिलकवाली बत्तख, लाल तोतवी, काला कांच, काले सिर वाला सफेद कांच, छोटा काजियो जैसी कई प्रजातियां विश्वविद्यालय के आर्द्रभूमि में देखी गईं, उनकी तस्वीरें विश्वविद्यालय की कॉफी बुक में प्रकाशित हुईं, तीन झीलें जो गायब थीं। डेवलपमेंट के नाम पर ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है और यह साफ है कि यूनिवर्सिटी में करप्शन और भ्रष्टाचार तमीज़ बन गया है। अलग-अलग नामों पर कुल 25.11 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट के बाद यह साफ नहीं है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसकी हाई-लेवल जांच होनी चाहिए और करप्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

# भद्रवी महाकुंभ 2026 भद्रवी महामेला 20 से 26 सितंबर तक भद्रवी पूनमिया सेवा संघ की मीटिंग हुई, कुल 1685 संघ रजिस्टर्ड

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**अंबाजी।** शक्ति, भक्ति और आस्था के केंद्र अंबाजी में 20 से 26 सितंबर 2026 तक होने वाले भद्रवी महाकुंभ से पहले, भद्रवी पूनमिया संघ सेवा ट्रस्ट की सालाना मीटिंग 21 सितंबर को अंबाजी के विजया रिसॉर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस अधिकारियों की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूरे गुजरात से बड़ी संख्या में संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंदिर एडमिनिस्ट्रेटर और प्रांतीय अधिकारी ने महामेले को लेकर सुझाव दिए, साथ ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ने भी सफाई को लेकर अच्छा मैसेज दिया। बनासकांठा पुलिस चीफ ने कहा कि मेले के दौरान करीब 7,000 पुलिस कर्मी माई के भक्तों की सुरक्षा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सभी मुख्य मांगें भी मान लीं

और भद्रवी पूनमिया सेवा संघ को भरोसा दिलाया कि मेला कामयाबी से होगा। अंबाजी मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिहिर पटेल ने कहा कि इस साल भद्रवी पूनमिया महा मेले के सही तरीके से आयोजन के लिए खास इंतज़ाम किए जाएंगे। मंदिर में साफ-सफाई के साथ-साथ माई

के भक्तों के लिए आसानी से दर्शन का इंतज़ाम किया जाएगा। भद्रवी पूनमिया सेवा संघ ने तीन मुख्य मांगें रखीं, जिन्हें ट्रस्ट की तरफ से हल करने का भी भरोसा दिया गया। इस बार भद्रवी पूनमिया संघ सेवा ट्रस्ट में पैदल यात्रियों के 1685 ग्रुप रजिस्टर किए गए हैं, पिछले साल 1585 ग्रुप रजिस्टर किए गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ से सभी इंतज़ाम किए जाएंगे ताकि पैदल आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। SP प्रशांत सुंबे कानून-व्यवस्था के लिए करीब 7,000 पुलिस के साथ मेले की कमान संभालेंगे। अंबाजी सिस्टम में खोड़ीवडली कंट्रोल पॉइंट पर 8 सेक्टर और 16 जोन के ज़रिए दिन-रात निगरानी की जाएगी। भद्रवी पूनमिया सेवा संघ के एग्जीक्यूटिव मेंबर नवनीतभाई पटेल ने अधिकारियों द्वारा परेशान करने और VIP कल्चर को लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म से बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2027 भद्रवी महाकुंभ की घोषणा से पहले, हम, पूरे गुजरात से संघ के प्रतिनिधि, गांव-गांव जाकर भक्तों से मिलेंगे, या अंबाजी मेले की घोषणा से पहले, हम यूनिट एक से सात तक अंबाजी जाएंगे, झंडा फहराएंगे और वापस आ जाएंगे, इस बयान से अधिकारियों में चिंता फैल गई।

# नंदनवन सोसायटी में आवारा मवेशियों को पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर चरवाहों ने हमला किया

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**वडोदरा।** शहर में आवारा मवेशियों की समस्या को खत्म करने गई नगर निगम की टीम की 'धोर डब्बा पार्टी' पर चरवाहों के हमले की एक और गंभीर घटना सामने आई है। शहर के नंदनवन सोसायटी इलाके में कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम और चरवाहों के बीच जमकर झड़प हुई। चरवाहों ने कानून अपने हाथ में लेकर नगर निगम कर्मचारियों पर हमला कर दिया, गालियां दीं, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। इंस्पेक्टर पर डंडे से हमला किया और घर आने पर जान से मारने की धमकी दी मिली जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की टीम नंदनवन सोसायटी में आवारा और बंधी गायों को पकड़ने का काम कर रही थी। इसी बीच गुस्साए चरवाहों की भीड़ ने नगर निगम की टीम को घेर लिया। आरोप है कि चरवाहों ने नगर निगम के इंस्पेक्टर पर डंडे से जानलेवा हमला किया और उनके साथ जमकर मारपीट की। बात यहीं नहीं रुकी, ऐसे भी गंभीर आरोप लगे हैं कि चरवाहों ने नगर निगम के कर्मचारियों को खुलेआम धमकी दी कि वे 'घर आकर उन्हें मार डालेंगे'। झड़प के दौरान, चरवाहों ने नगर निगम की टीम द्वारा पकड़ी गई बंधी हुई गायों को ज़बरदस्ती छोड़ दिया और वे दहशत में आ गए। नगर निगम प्रशासन ने सरकारी काम में रुकावट डालने और कर्मचारियों पर हमला करने के संबंध में पुलिस चौकी में आधिकारिक शिकायत दर्ज करने के लिए कदम उठाए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और हमला करने वाले पशु मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है।ह डोदरा में नगर निगम के पशु दल पर लगातार हो रहे हमलों से पता चलता है कि असामाजिक तत्वों को कानून या पुलिस का कोई डर नहीं है। जहां आवारा पशुओं के कारण बेगुनाह नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं काम पर जाने वाले कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या इस बार पुलिस चरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी

## नंदनवन सोसायटी में आवारा मवेशियों को पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर चरवाहों ने हमला किया

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**वडोदरा।** शहर में आवारा मवेशियों की समस्या को खत्म करने गई नगर निगम की टीम की 'धोर डब्बा पार्टी' पर चरवाहों के हमले की एक और गंभीर घटना सामने आई है। शहर के नंदनवन सोसायटी इलाके में कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम और चरवाहों के बीच जमकर झड़प हुई। चरवाहों ने कानून अपने हाथ में लेकर नगर निगम कर्मचारियों पर हमला कर दिया, गालियां दीं, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया।मिली जानकारी के मुताबिक,

नगर निगम की टीम नंदनवन सोसायटी में आवारा और बंधी गायों को पकड़ने का काम कर रही थी। इसी बीच गुस्साए चरवाहों की भीड़ ने नगर निगम की टीम को घेर लिया। आरोप है कि चरवाहों ने नगर निगम के इंस्पेक्टर पर डंडे से जानलेवा हमला किया और उनके साथ जमकर मारपीट की। बात यहीं नहीं रुकी, ऐसे भी गंभीर आरोप लगे हैं कि चरवाहों ने नगर निगम के कर्मचारियों को खुलेआम धमकी दी कि वे 'घर आकर उन्हें मार डालेंगे'। झड़प के दौरान, चरवाहों ने नगर निगम की टीम द्वारा पकड़ी गई बंधी हुई गायों को ज़बरदस्ती छोड़ दिया और वे दहशत में आ गए। नगर निगम प्रशासन ने सरकारी काम में रुकावट डालने और कर्मचारियों पर हमला करने के संबंध में पुलिस चौकी में आधिकारिक शिकायत दर्ज करने के लिए कदम उठाए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और हमला करने वाले पशु मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है।रूवडोदरा में नगर निगम के पशु दल पर लगातार हो रहे हमलों से पता चलता है कि असामाजिक तत्वों को कानून या पुलिस का कोई डर नहीं है। जहां आवारा पशुओं के कारण बेगुनाह नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं काम पर जाने वाले कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या इस बार पुलिस चरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी? पाको गुजरात न्यूज़ आपको इस मामले के सभी अपडेट से अपडेट रखेगा।

## चंद्राला गांव के पास एक बहुत ही दिल दहला देने वाली और दिल दहला देने वाली हिट एंड रन की घटना सामने आई है

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**गुजरात।** शराब बैन लागू करने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, BJP के सीनियर नेता और MLA जीतू वघानी ने साफ और कड़ा बयान दिया है। भावनगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के ऑफिस में हुई हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि गुजरात में शराब बैन हटाने का कोई सवाल ही नहीं है और राज्य में शराब बैन कानून को सख्ती से लागू

किया जाएगा। भावनगर में कानून-व्यवस्था की स्थिति का रिव्यू करने के लिए S.P. ऑफिस में एक खास मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जिले के टॉप पुलिस ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मौजूद थे। मीटिंग में असामाजिक तत्वों, गैर-कानूनी कामों और शराब में मिलावट के खिलाफ उठाए गए कदमों पर डिटेल में चर्चा हुई। 'शराब बैन हटाने की बात बेबुनियाद है मीटिंग के बाद जीतू वघानी ने कहा, 'गुजरात गांधी और सरदार का राज्य है। राज्य में शराब बैन हटाने का कोई प्लान नहीं है और भविष्य में शराब बैन कभी नहीं हटाया जाएगा।' उन्होंने आगे कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे एंटी-सोशल एक्टिविटी और बूटलेगर के खिलाफ और भी सख्ती से और सख्त एक्शन लें। किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा।

## खेड़ा जिले में फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की सख्त कार्रवाई: होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्टल में बड़े पैमाने पर छापे

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**खेड़ा।** जिले में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने आंखें मूंद ली हैं। फूड डिपार्टमेंट की टीमों ने नडियाद समेत जिले के अलग-अलग इलाकों में मौजूद जाने-माने होटलों, रेस्टोरेंट और स्टूडेंट हॉस्टल में सरप्राइज चेकिंग की और बड़े पैमाने पर छापे मारे। जांच के दौरान कई जगहों पर साफ-सफाई की भारी कमी और अनहेल्दी खाना मिला, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भारी जुर्माना और नोटिस लगाए हैं। जांच अधिकारियों द्वारा की गई इस कड़ी चेकिंग के दौरान, होटलों और रेस्टोरेंट के किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी देखी गई। इतना ही नहीं, यह भी पता चला है कि ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाने में घटिया क्वालिटी के मसाले और बासी खाने की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। हॉस्टल मेस, जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ भी साफ़-सफ़ाई का माहौल नहीं है, इसलिए फ़ूड डिपार्टमेंट ने मौके से खाने की अलग-अलग चीज़ों के सैंपल लेकर उन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया है फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के नियमों को तोड़ने और साफ़-सफ़ाई के स्टैंडर्ड बनाए रखने में नाकाम रहने वाले ऑपरेटरों को सख़्त चेतावनी दी गई है। कई खराब यूनिट्स पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि कुछ यूनिट्स को लाइसेंस कैंसिल करने तक के नोटिस जारी किए गए हैं।

## पॉश इलाके अलकापुरी में सारथी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट से भारी मात्रा में विदेशी शराब ज़ब्त की गई

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**वडोदरा।** शहर के बेहद पॉश और हलचल वाले अलकापुरी इलाके में अवैध शराब के धंधे को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक टिप-ऑफ के आधार पर, लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक टीम ने अलकापुरी में मौजूद 'सारथी कॉम्प्लेक्स' के बेसमेंट में अचानक रेड मारकर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब ज़ब्त की है। शहर के बीचों-बीच मौजूद एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर रखे जाने की घटना से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है।

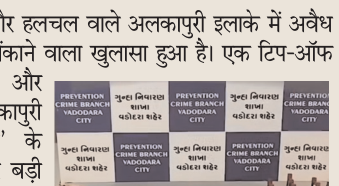


### कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट को 'सेफ हाउस' बनाया गया था

पुलिस सूत्रों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सुरक्षित माने जाने वाले इस बेसमेंट का इस्तेमाल बूटलेगर पुलिस की नज़र से बचने के लिए गोदाम के तौर पर कर रहे थे। रेड के दौरान पुलिस ने महंगे ब्रांड की विदेशी शराब की बोतलें ज़ब्त कीं। पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि इतने लंबे समय से इस हाई-प्रोफाइल इलाके में विदेशी शराब का नेटवर्क किसके अंडर चल रहा था और इतनी मात्रा में शराब कहां से लाई गई थी।

### बूटलेगरों और ऑपरेटरों के खिलाफ कानूनी हथियार उठाए गए हैं।

पुलिस ने मौके से शराब की मात्रा जब्त कर ली है और केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस स्कैम में शामिल मुख्य साजिशकर्ताओं, माल पहुंचाने वाले सप्लायरों और कॉम्प्लेक्स के किस हिस्से का इस्तेमाल किया गया, इस बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस जल्द ही जब्त माल की कुल कीमत और आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में ऑफिशियल बयान देगी। अलकापुरी जैस VIP इलाकों में कॉम्प्लेक्स से शराब की जब्ती से यह साफ है कि बूटलेगर अब कानून से पूरी तरह अनजान पॉश इलाकों को अपना अड्डा बना रहे हैं। क्या यह सब लोकल पुलिस की आंखों के सामने हो रहा था? पक्को गुजरात न्यूज़ आपको इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच के बारे में अपडेट रखेगा।

## वारका में बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद: 'द्वारका जिले को तुरंत सूखाग्रस्त घोषित करो ', गुस्साए धरतीपुत्रों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**वारका।** दुनिया भर में मशहूर देवभूमि द्वारका जिला आज काली समस्याओं के जाल में फंस गया है। कुदरत के कहर और बारिश में लंबे समय तक देरी की वजह से पूरे जिले में फसलें सूख गई हैं। महंगे बीज, खाद और दिन-रात मेहनत के बाद भी खेतों में फसलें जलकर राख हो रही हैं। ऐसे मुश्किल हालात में, कर्ज के पहाड़ तले दबे देवभूमि द्वारका के हर कोने से किसानों की एक ही आवाज और जोरदार मांग उठ रही है– 'द्वारका जिले को तुरंत सूखाग्रस्त घोषित करो! ' द्वारका जिले के खंभालिया, कल्याणपुर, भंवड़ और द्वारका तालुका के ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। मौसमी बारिश कम होने की वजह से सिंचाई के सोर्स सूख गए हैं और कुओं के तल दिखने लगे हैं। मूंगफली, कपास, तिल और दाल जैसी बड़ी फसलें पानी के बिना सूखकर पापड़

जैसी हो गई हैं। किसानों ने ब्याज पर पैसे लेकर जो खेती की थी, वह फेल हो गई है, इसलिए अब परिवार का गुज़ारा करना और जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम करना नामुमकिन हो गया है। हर बार जब कोई कुदरती आफ़त आती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन खोखले भरोसे देता है कि 'सर्वे करवाया जाएगा', लेकिन जब तक कागजी सर्वे पूरा होता है, तब तक किसान बर्बाद हो चुका होता है। किसान नेताओं और द्वारका के धरतीपुत्रों का सीधा आरोप है कि सरकार सिर्फ़ बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करती है, लेकिन जब किसानों को सच में मदद की ज़रूरत होती है, तो सरकारी बाबू नियमों की हदें दिखाकर हाथ खड़े कर देते हैं। जब खेतों में फसल ही नहीं बची, तो ज़िले को सूखाग्रस्त घोषित करने में देरी क्यों? किसानों के बिजली बिल, खेती के लोन के ब्याज और जानवरों के चारे के लिए तुरंत स्पेशल पैकेज का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर राज्य सरकार और खेती विभाग द्वारका जिले के किसानों का यह दर्द नहीं सुनते और तुरंत पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करके मुआवजा देने का प्रोसेस शुरू नहीं करते, तो आने वाले दिनों में द्वारका के किसान सड़कों पर उतरेंगे और गांधी चिंध्या मार्ग पर जमकर विरोध करेंगे। 'पाको गुजरात न्यूज़' अपने हक की इस लड़ाई में धरतीपुत्रों के साथ मजबूती से खड़ा है और किसान की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करता रहेगा।

## कागज़ पर शराबबंदी और अपने राज्य में लट्ठा कांड की परंपरा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**भावनगर।** लट्ठा कांड की दुखद घटना ने एक बार फिर पूरे गुजरात को झकझोर कर रख दिया है। गांधी और सरदार के इस राज्य में 'कागज़ पर शराबबंदी' के दावों के बीच, ज़हरीली शराब के धंधे ने कई बेगुनाह लोगों की जान ले ली है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार और पुलिस सिस्टम इस घटना के बाद एक बार फिर ठप हो गया है। लट्ठा कांड में जले बेगुनाह लोगों के परिजनों की चीख-

पुकार ने न सिर्फ़ भावनगर बल्कि पूरे गुजरात में ज़बरदस्त जनाक्रोश और अफ़रा-तफ़री फैला दी है। भावनगर की घटना के बाद राज्य की राजनीति भी गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के राज्य नेता गोपाल इटालिया ने सरकार की पॉलिसी और पुलिस सिस्टम की नाकामी पर सीधे और ज़बरदस्त हमले किए हैं। विपक्ष ने साफ आरोप लगाया है कि लोकल पुलिस और पॉलिटिकल आकाओं की मेहरबानी के बिना ज़हरीली शराब का हर कोने तक पहुंचना नामुमकिन है।

## गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गढेथड गायत्री आश्रम के महंत पूज्य लालबापू से उनके स्वास्थ्य और हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में पूछा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**गुजरात।** गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सौराष्ट्र की सांस्कृतिक और महान संत परंपरा के वाहक और उपलेटा के पास मशहूर गढेथड गायत्री आश्रम के गादीपति पूज्य श्री लालबापू से खुद जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हर्ष संघवी ने पूज्य बापू के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ली और भगवान के चरणों में उनके जल्दी ठीक होने और लंबी और हमेशा स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। उपलेटा के पास गढेथड में मौजूद गायत्री आश्रम और पूज्य लालबापू लाखों भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र हैं। जीवन भर सनातन धर्म और मानव सेवा के लिए समर्पित पूज्य लालबापू को सौराष्ट्र की संत परंपरा का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के कई जाने-माने लोग अक्सर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने उनसे मिलने आते हैं। इस दौरे के दौरान, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पूज्य लालबापू से अच्छी बातचीत की।

इसके साथ ही, उन्होंने उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों और आश्रम परिवार से बात करके उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि सभी भक्त उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि पूज्य बापू की मौजूदगी और आशीर्वाद हमेशा गुजरात के लोगों पर बना रहे। र्थना है कि सौराष्ट्र के इस महान संत और तपस्वी पूज्य लालबापू जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएं और भक्तों को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दें। महानगर मेट्रो न्यूज़' आपको पूज्य बापू की बिगड़ती सेहत के बारे में पल-पल की जानकारी और अपडेट देता रहेगा।

## गुजरात में शराब जैसे 'एनालॉग चीज़' का गैर-कानूनी नेटवर्क AMC ने राजस्थान से तस्करी करके लाई गई 408 kg नकली चीज़ ज़ब्त की

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**गुजरात।** शराब बैन और चेकिंग के सख्ती से लागू होने के बीच, काले कारोबारियों ने अब लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। राज्य सरकार के बैन लगाने के बाद भी, राजस्थान से गुजरात में नकली 'एनालॉग चीज़' की तस्करी करने वाला एक बड़ा नेटवर्क एक्टिव हो गया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ़ूड डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लेते हुए राजस्थान से लाई गई 408 द्मद्द संदिग्ध एनालॉग चीज़ ज़ब्त करके एक बड़े स्कैम का पर्दाफ़ाश किया है।

### यह 'एनालॉग चीज़' क्या है और यह जानलेवा क्यों है?

एनालॉग चीज़ असली दूध से बना असली चीज़ नहीं है, बल्कि वेजिटेबल ऑयल (पाम ऑयल), स्टार्च, केमिकल और एसेंस मिलाकर बनाया गया एक नकली चीज़ है। दिखने में असली चीज़ जैसा दिखने वाला यह मिलावटी चीज़ शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसे खाने से लंबे समय में दिल की बीमारी, पाचन तंत्र की गंभीर बीमारियां और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा रहता है। क्योंकि यह कम कीमत पर मिलता है, इसलिए होटलों, रेस्टोरेंट और डेयरियों में असली चीज़ के नाम पर लोगों को यह ज़हर परोसा जा रहा था।

### AMC फ़ूड डिपार्टमेंट का रेड ऑपरेशन

खास जानकारी के आधार पर, AMC की फ़ूड सैनिटेशन टीम ने शहर के एंट्री गेट और संदिग्ध जगहों पर सरप्राइज़ चेकिंग की थी। इस दौरान, राजस्थान से आने वाले ट्रांसपोर्ट और गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 408 द्मद्द एनालॉग चीज़ मिला। फ़ूड अधिकारियों ने मौके से यह पूरी क्वांटिटी ज़ब्त कर ली है और इसके सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। अहमदाबाद में यह क्वांटिटी किन ट्रेडर्स या होटल ऑपरेटरों को सप्लाई की जानी थी, इसकी गहरी जांच शुरू कर दी गई है। यह बात कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में नकली चीज़ राजस्थान से गुजरात बॉर्डर पार करके अहमदाबाद पहुंचता है, राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट की खराब कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या राजस्थान कनेक्शन अब खाने-पीने की चीज़ों के साथ-साथ शराब पर भी हावी हो रहा है? शामिल मुख्य आरोपियों और ट्रेडर्स पर तब तक नज़र रखेगा जब तक उनका पर्दाफ़ाश नहीं हो जाता।

## अहमदाबाद में शराब तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई: दो दिन की शराबबंदी ड्राइव में 215 केस दर्ज, 244 आरोपी गिरफ्तार

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**भावनगर।** लता की घटना के बाद अहमदाबाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने और अवैध शराब के धंधे पर नकेल कसने के लिए एक खास शराबबंदी ड्राइव शुरू की थी। सिर्फ दो दिनों के इस बड़े अभियान के दौरान, शहर की पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करके शराब तस्करों और असामाजिक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कंट्रोल रूम और सभी लोकल पुलिस स्टेशनों द्वारा की गई इस गहन चेकिंग के दौरान दो दिनों में शराबबंदी के कुल 215 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शहर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में चल रहे शराब के अड्डों पर छापेमारी करके मौके से 244 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। स्क्ष्ट और लोकल पुलिस का मेगा ऑपरेशन अहमदाबाद शहर की पुलिस के साथ-साथ स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम भी इस ड्राइव में शामिल हुई। शहर में क्रिमिनल हिस्ट्री वाले बदनाम बूटलेगर और रिटेलर के खिलाफ कानून का हथियार इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के इस सख्त रुख की वजह से शहर में गैर-कानूनी शराब का नेटवर्क टूट गया है और बूटलेगर अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस की यह तुरंत और सख्त कार्रवाई वेलकम है, लेकिन लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या यह कैंपेन सिर्फ दो दिन तक ही लिमिटेड रहेगा? अगर पुलिस लगातार ऐसे ही सख्त कदम उठाएगी, तो ही शहर को इस शराब की बुराई से छुटकारा मिल सकता है। पक्को गुजरात न्यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन के इस ऑपरेशन और आगे के अपडेट्स पर लगातार नज़र रखेगा।

## राजकोट सिविल हॉस्पिटल में शर्मनाक घटना: सीनियर मेडिकल ऑफिसर पर महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारने का आरोप, वायरल वीडियो से विवाद, रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**राजकोट।** का सरकारी सिविल हॉस्पिटल एक बार फिर गंभीर विवाद में फंस गया है। हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. अश्विन रमानी पर एक महिला डॉक्टर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने और उसे सरेआम थप्पड़ मारने का आरोप लगा है, जिससे पूरे मेडिकल जगत में हड़कंप मच गया है। इस शर्मनाक घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बेरहमी की पोल खुल गई।

### सिविल में वायरल वीडियो से हंगामा: रेजिडेंट डॉक्टरों का हंगामा

महिला डॉक्टर पर हमले और बदनामी का वीडियो सामने आने के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों में भारी गुस्सा है। डॉक्टरों की सुविधाओं और सुरक्षा पर

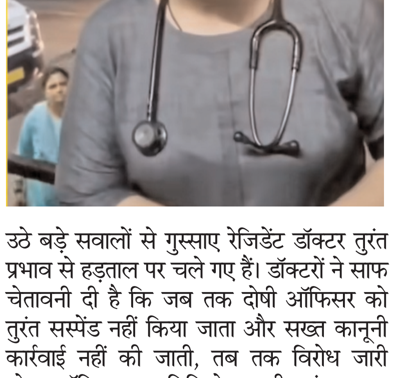

उठे बड़े सवालों से गुस्साए रेजिडेंट डॉक्टर तुरंत प्रभाव से हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक दोषी ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड नहीं किया जाता और सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जांच घटना की गंभीरता को देखते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट और अधिकारियों ने तुरंत एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई है। वायरल वीडियो की सच्चाई वेरिफाई करने और पीड़ित महिला डॉक्टर और चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हड़ताल की वजह से हॉस्पिटल आने वाले मरीजों के इलाज पर भी थोड़ा असर पड़ रहा है। अगर सीनियर अधिकारी ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टरों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी के बड़े-बड़े दावों का क्या? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में सख्त एक्शन लेगा और महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाएगा या जांच के नाम पर मामले को निपटाने की कोशिश होगी? पाक्को गुजरात न्यूज़ इस चौंकाने वाले मामले की लेटेस्ट डिटेल्स आप तक पहुंचाता रहेगा।

## गुजरात में कांग्रेस को संभालने के लिए दिल्ली से नया ब्लू प्रिंट तैयार

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**गुजरात।** लंबे समय से सत्ता से बाहर और संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने के लिए दिल्ली हाईकमान ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। राज्य में पार्टी के जमीनी स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव करने और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए दिल्ली से एक नया 'ब्लू प्रिंट' तैयार किया गया है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत देश के जाने-माने और सफल चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट (रणनीतिकार) सुनील कनुगोलू को गुजरात कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। हाईकमान के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गुजरात कांग्रेस के मौजूदा स्टेट स्ट्रक्चर में बहुत जल्द एक बड़ा सर्जिकल जैसा बदलाव देखने को मिलेगा। इनैक्टिव पदाधिकारियों को उनके पदों से मुक्त किया जाएगा और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले युवा नेताओं को ऑर्गेनाइजेशन में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जिला और तालुका लेवल तक संगठन को फिर से बनाने और उसे आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुनील कनुगोलू की रणनीति ने कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब वह गुजरात में भी इसी पैटर्न पर काम करेंगे। कनुगोलू की टीम ने गुजरात के हर इलाके, जातिगत समीकरणों, लोगों के ज्वलंत मुद्दों और पार्टी की कमजोरियों पर गहन ग्राउंड सर्वे शुरू कर दिया है। इसी सर्वे के आधार पर आने वाले समय में उम्मीदवार और रणनीति तय की जाएगी। गुजरात में बीजेपी के मजबूत किले को तोड़ना कांग्रेस के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है।

## रेड करने पहुंचे अधिकारियों पर लोडर लादकर जान से मारने की गंभीर कोशिश

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**अमरेली।** शेत्रुंजी नदी के किनारे के इलाके में गैर-कानूनी मिनरल चोरी करने वाले माफिया इतने बेरहम हो गए हैं कि उन्हें अब कानून या सिस्टम का कोई डर नहीं रहा। अमरेली के छोटे और बड़े मांडवाड़ा गांवों के नदी के किनारे गैर-कानूनी माइनिंग पर जियोलॉजी डिपार्टमेंट (माइन्स एंड मिनरल्स) ने अचानक रेड मारी। इस कार्रवाई

के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि मिनरल माफियाओं ने कानून अपने हाथ में ले लिया और रेड करने पहुंचे सरकारी अधिकारियों पर सीधे लोडर लादकर जान से मारने की कोशिश की। मिली जानकारी के मुताबिक, जियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम ने रेड के दौरान मौके से मिनरल चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे दो बिना लाइसेंस वाले डंपर जब्त किए। कार्रवाई से गुस्साए लोडर मालिक और उसके साथियों ने अधिकारियों के साथ गाली-गलौज, हाथापाई और धमकी दी। इतने पर ही नहीं रुके, अधिकारियों को कुचलने के इरादे से लोडर चढ़ाने की सीधी कोशिश की गई। इस झड़प के दौरान, अवैध माइनिंग में शामिल लोग लोडर और ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए, 112 इमरजेंसी टीम और अमरेली तालुका पुलिस का काफिला तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मौके से जब्त गाड़ियों को जब्त कर लिया है। फरार लोडर मालिक/ड्राइवर और उसके दूसरे साथियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी के काम में गंभीर रुकावट डालने, अधिकारियों के साथ गाली-गलौज करने और जानलेवा हमले की कोशिश करने जैसी सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। अगर अमरेली में नदी के किनारे से प्राकृतिक संसाधनों को लूटने वाले माफिया खुलेआम सरकारी अधिकारियों पर गाड़ियां चढ़ाने की हिम्मत करेंगे, तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या? क्या वे सिर्फ़ एक या दो गाड़ियां ज़ब्त करके संतुष्ट हो जाएंगे या माइनिंग माफियाओं के पूरे गैंग को जेल में डाल दिया जाएगा? पक्को गुजरात न्यूज़ इस केस के सभी अपडेट्स और आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगातार नज़र रखेगा।

## इथेनॉल के पागलपन में मिडिल क्लास की रसोई पर सरकार की लूट के खिलाफ 'महानगर मेट्रो' में गुस्सा है

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**अहमदाबाद।** जब देश का आम नागरिक और गृहणियां सुबह उठकर चाय का कप हाथ में लेती हैं, तो उन्हें स्वाद के बजाय महंगाई की कड़वी गोली निगलनी पड़ती है। आज भारतीय मिडिल क्लास परिवारों की रसोई पर सरकारी नीतियों की ऐसी जानलेवा कुल्हाड़ी लगी है जिसने गरीबों और मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। पूरे देश में चीनी की कीमत में 13 परसेंट की तेज और बर्दाश्त न होने वाली बढ़ोतरी हुई है। जो चीनी पहले 40 रुपये प्रति किलो मिलती थी, वह अब गुजरात के बाजारों में 60 से 65 रुपये में बिक रही है। अगर सरकार अपनी नींद से नहीं जागी, तो आने वाले त्योहारों के मौसम में चीनी 70 से 75 रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी। यह कोई प्राकृतिक आपदा या फसल खराब होने से होने वाली महंगाई नहीं है, यह तो सरकार की खुद बनाई हुई बनावटी कमी है! केंद्र सरकार पर्यावरण और 'इथेनॉल ब्लेंडिंग' के नाम पर जो तारीफ़ कर रही है, उसके पीछे कड़वा सच यह है कि देश की चीनी मिलों को गन्ने के रस और चीनी के स्टॉक को गाड़ियों के लिए 'इथेनॉल' बनाने की इजाज़त दे दी गई। गाड़ियों के लिए फ्यूल बनाने की होड़ में सरकार ने यह सोचना भी ठीक नहीं समझा कि लोग क्या खाएंगे? गाड़ियों में इथेनॉल मिलाकर पेट्रोलियम कंपनियों के खजाने भरे जा रहे हैं, जबकि आम नागरिक की थाली से 'मिठास' छीनी जा रही है। चीनी सिर्फ़ चाय तक ही सीमित नहीं है। चीनी के दाम बढ़ते ही दूध, बिस्कुट, बेकरी प्रोडक्ट, मिठाई और रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने वाली कंपनियों ने दाम बढ़ने का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाल दिया है। एक तरफ़ चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ तेल, आटा, गैस सिलेंडर और हरी सब्ज़ियों के दाम पहले से ही आसमान छू रहे हैं। जैसे-जैसे त्योहार पास आ रहे हैं, गरीब और मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को मिठाई खिलाने के बारे में भी सौ बार सोचने पर मजबूर हो रहे हैं।

# कब तक जारी रहेगा जहरीली शराब का जानलेवा कहर?

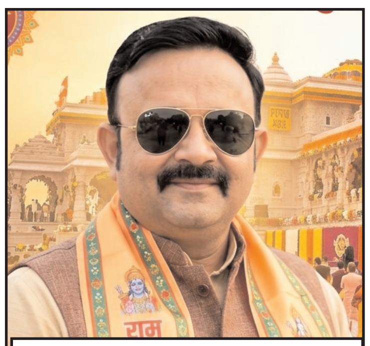

पवन माकन
ग्रुप एडिटर, महानगर मेट्रो

**जहरीली शराब का यह जानलेवा सिलसिला देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर देखने को मिलता है एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती बना हुआ है। ट्रांसनेशनल अलायंस टू कॉम्बैट इलिसिट ट्रेड जैसी संस्थाओं के अनुसार, भारत में अवैध शराब की खपत दुनिया के सबसे बड़े अवैध बाजारों में से एक है। यह न केवल सरकारी राजस्व को भारी चोट पहुँचाता है, बल्कि इसके कारण हर साल सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।**

भारत में जहरीली शराब से होने वाली मौतें एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बनी हुई हैं, जिसमें ड्राई स्टेट शराबबंदी वाले राज्यों से लेकर अन्य राज्यों तक लगातार दुखद घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला अगस्त 2026 में गुजरात के भावनगर का है, जहां नकली विदेशी शराब के नाम पर बेची गई जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

जहरीली शराब का यह जानलेवा सिलसिला देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर देखने को मिलता है एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती बना हुआ है। ट्रांसनेशनल अलायंस टू कॉम्बैट इलिसिट ट्रेड जैसी संस्थाओं के अनुसार, भारत में अवैध शराब की खपत दुनिया के सबसे बड़े अवैध बाजारों में से एक है। यह न केवल सरकारी राजस्व को भारी चोट पहुँचाता है, बल्कि इसके कारण हर साल सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।देश भर में आए दिन जहरीली और नकली शराब से होने वाली मौतें अब केवल दुर्घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि ये घटनाएं हमारी व्यवस्था, कानून और समाज के सामने एक गंभीर सवाल हैं । कुछ दिन सप्ताह माह के अन्तराल पर देश के किसी न किसी हिस्से से खबर आती है कि नकली शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी, कई अस्पताल पहुंचे और कुछ ने दम तोड़ दिया। प्रशासन सक्रिय होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, जांच बैठती है, मुआवजे की घोषणा होती है और कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है। फिर किसी दूसरे शहर, गांव या राज्य में वही कहानी दोहराई जाती है। सवाल यही है, आखिर यह सिलसिला कब थमेगा ?

आपको बता दें कि ताजा मामला गुजरात के भावनगर जिले का है। गुजरात उन राज्यों में है जहां लंबे समय से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद भावनगर में कथित नकली शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की घटना सामने आई है। स्थानीय प्रशासन ने चार लोगों की मौत की जानकारी दी थी, जबकि अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा था। शुरूआती रिपोटों में मौतों की संख्या कम थी, जो बाद में बढ़ी। यह घटना इसलिए भी अधिक गंभीर है, क्योंकि जिस राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर कानूनी प्रतिबंध है, वहां नकली शराब लोगों तक पहुंच कैसे रही है? पुलिस की शुरूआती जांच में एक लोकप्रिय ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट शराब बेचे जाने और इसके मध्य प्रदेश से लाए जाने की आशंका सामने आई है। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन भावनगर कोई पहली घटना नहीं है।हाल ही में मई माह में महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ त्रासदी इलाकों में जहरीली शराब पीने से 14 से 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस जांच के अनुसार, अवैध रूप से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड का घातक मेथनॉल मिक्स किया गया था।मई माह में ही पंजाब के अमृतसर के पांच गांवों में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात ने जुलाई 2022 में भी भयावह शराब त्रासदी देखी थी। बोटाद और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस समय भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अधिकारियों का तबादला हुआ और अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने के दावे किए गए थे। सवाल है कि चार वर्ष बाद भी यदि नकली शराब लोगों तक पहुंच रही है तो पिछली कार्रवाई से हमने आखिर सीखा क्या? यह समस्या केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्य समय-समय पर ऐसी त्रासदियों के गवाह बने हैं। तमिलनाडु के कालाकुरिची में जून 2024 में मेथेनॉल मिली अवैध शराब ने दर्जनों परिवारों को उजाड़ दिया था। आधिकारिक कार्रवाई के दौरान अवैध शराब जब्त हुई, गिरफ्तारियां हुई और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में भी अवैध एवं नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। उपलब्ध एनसीआरबी आधारित डेटा 2012 से 2024 तक राज्य वार ऐसी मौतों का हवाला देता है। इससे इतना तो साफ है कि यह किसी एक राज्य या एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही एक खतरनाक चुनौती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अक्सर इन घटनाओं में मरने वाले लोग समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल कमजोर वर्ग से आते हैं। सस्ती शराब की तलाश उन्हें ऐसे अवैध कारोबारियों तक पहुंचा देती है जिन्हें न गुणवत्ता की चिंता होती है, न कानून का भय और न इंसानी जीवन की कीमत का एहसास। अधिक नशा पैदा करने या लागत कम रखने के लिए शराब में मेथेनॉल जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। कल्लाकुरिची मामले में भी मेथेनॉल मिश्रित शराब की पुष्टि सामने आई थी। अधिकरत देखा जाता है कि हर बड़ी आसदी के बाद प्रशासन की एक परिचित तस्वीर सामने आती है। छापेमारी शुरू होती है, अवैध ठिकाने बंद किए जाते हैं, संदिग्ध गिरफ्तार होते हैं और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है। लेकिन असली चुनौती घटना के बाद कार्रवाई करने की नहीं, घटना होने से पहले नेटवर्क को समाप्त करने की है। अवैध शराब का कारोबार अकेले किसी गली या गांव में बैठा व्यक्ति नहीं चला सकता। कच्चा माल कहां से आता है? बोतलें कहां बनती हैं? लोकप्रिय कंपनियों के नाम और लेबल की नकल कैसे होती है? माल एक जिले से दूसरे जिले और कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे पहुंचता है? परिवहन, भंडारण और बिक्री की जानकारी स्थानीय स्तर पर किसी को क्यों नहीं मिलती? यदि वर्षों तक कारोबार चलता रहता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही, स्थानीय संरक्षण या भ्रष्ट तंत्र भी इसका रास्ता आसान कर रहा है। शराबबंदी वाले राज्यों के लिए यह समस्या और बड़ी चुनौती है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता। यदि वैध बिक्री बंद होने के बाद अवैध बाजार पैदा हो जाए और उसकी निगरानी कमजोर रहे तो तस्करों को अधिक मुनाफे का अवसर मिलता है। शराबबंदी का उद्देश्य समाज को नशे से बचाना है, लेकिन यदि उसी व्यवस्था के भीतर जहरीली शराब का संगठित बाजार फलने लगे तो नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन दोनों जरूरी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शराबबंदी गलत है या शराब की खुली बिक्री समाधान है। असली प्रश्न नीति से अधिक उसके प्रभावी क्रियान्वयन का है। जहां प्रतिबंध है वहां अवैध सप्लाई पर कठोर निगरानी होनी चाहिए और जहां शराब की कानूनी बिक्री है वहां नकली उत्पादों की पहचान और वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत होना चाहिए। सरकारों को अब प्रत्येक त्रासदी के बाद केवल मुआवजा देने और कुछ लोगों को निलंबित करने से आगे बढ़ना होगा। अवैध शराब के मामलों में सप्लाई चेन की तह तक जांच, औद्योगिक मेथेनॉल की बिक्री और परिवहन की निगरानी, नकली ब्रांड और पैकेजिंग बनाने वालों पर कार्रवाई तथा बार-बार अवैध कारोबार में पकड़े जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है।यह सारा अवैध कारोबार बिना सरकारी तंत्र की मिलीभगत के सम्भव नहीं है स्थानीय पुलिस और आबकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण और गरीब बस्तियों में जागरूकता बढ़ानी होगी। लोगों को बताया जाना चाहिए कि अनजान स्त्रोत से खरीदी गई शराब जानलेवा हो सकती है। संदिग्ध शराब पीने के बाद उल्टी, चक्कर, दृष्टि धुंधली होने वा अन्य परेशानी के मामलों में तुरंत अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है। कई बार इलाज में देर भी मौतों की संख्या बढ़ा देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहरीली शराब से हुई हर मौत को महज एक आंकड़ा समझने की मानसिकता बदलनी होगी। मरने वाला किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य, बेटा, पिता या भाई होता है। उसके जाने के बाद परिवार केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक संकट में भी डूब जाता है। देश में तकनीक बड़ी है, पुलिस के पास आधुनिक संसाधन हैं, राज्यों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान पहले से आसान हुआ है। ऐसे में यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अवैध शराब की पेटियां एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचे और व्यवस्था को भनक तक न लगे। भावनगर की घटना फिर चेतावनी दे रही है कि नकली शराब केवल कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है। कार्रवाई तब सार्थक होगी जब अगली त्रासदी होने से पहले अपराधी नेटवर्क खत्म किया जाए। हर घटना के बाद वही सवाल पूछने की मजबूरी आखिर कब समाप्त होगी, कब थमेगा जहरीली शराब का कहर और कब बंद होगा बेगुनाहों की मौतों का यह सिलसिला। एक मौत पूरे परिवार को मार देती है कई बार परिवार के एक मात्र कमाने वाले सदस्य की मौत से पूरा परिवार प्रभावित होता है। सरकार को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए।

## संपादकीय

### हेल्थकेयर की चुनौतियां

यह विडंबना ही है कि देश में कभी भी सत्ताधीशों की प्राथमिकता सरकारी चिकित्सा-तंत्र को सक्षम बनाने की नहीं रही है। किसी भी चुनाव में स्वास्थ्य सुविधाओं को समृद्ध बनाना राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं रहा। जनता भी हर आम परिवार से जुड़े सेहत के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने में चूकती रही है। यही वजह है कि आज भी कुल मिलाकर देश के करोड़ों लोगों के लिये सस्ती व पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच से बाहर हैं। अपने परिजनों के गंभीर रोगों के उपचार के लिये क्षमता से अधिक पैसा जुटाने के फेर में हजारों परिवार हर साल गरीबी की दलदल में धंस जाते हैं। यह गंभीर स्थिति सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में हेल्थकेयर पर बनी संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर दशार्ती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के 2025 के सर्वे का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने पाया है कि सरकारी सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज का औसत खर्च 6,631 रुपये है, जबकि प्राइवेट में यह खर्च 50,508 रुपये है। निजी अस्पताल में होने वाला यह औसत खर्च सरकारी अस्पताल में होने वाले खर्च के मुकाबले सात गुना से भी अधिक है। जो चिकित्सा सुविधाओं में व्याप्त व्यापक विसंगतियों को ही दशार्ता है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है कि निजी अस्पताल अब साठ फीसदी से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करते हैं और 70 फीसदी आउट पेशेंट की देखभाल करते हैं। विडंबना यह है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव लगातार बना रहता है। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी मरीज महसूस करते हैं। सरकारी अस्पताल की सुविधाओं में बेड, उपकरण, दवाइयां और कुशल स्टाफ की कमी देखी जाती है। मरीज को भरोसा नहीं होता है कि उसे जरूरी इलाज सरकारी अस्पताल में मिल भी पायेगा। एक संकट यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है। उसके मुकाबले चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों में चिकित्सकों की अच्छी आय और निजी प्रैक्टिस का सम्मोहन भी योग्य डाक्टरों को सरकारी अस्पतालों से विमुख बनाता है। यही वजह है कि पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिये बाध्य होना पड़ता है। दरअसल, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, अब चाहे उनकी पैसा देने की क्षमता हो या न हो। लोगों की चिकित्सा इमरजेंसी की चिंता की वजह से स्वास्थ्य बीमा का बड़ा कारोबार देश में फल-फूल रहा है।

## चिंतन-मनन

### चैन से सोना है तो सोने को कहें ना

सोने की चमक सभी को आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण लोग अधिक से अधिक सोना खरीदने चाहते हैं। यह चाहत तब और भी बढ़ जाती है जब सोने की कीमत में अचानक थोड़ी गिरावट आती है। लोग इस मौका का लाभ उठाना चाहते हैं। आज कल बाजार में यही स्थिति है क्योंकि सोने की कीमत कमी आयी है। आइए जानें सोने के बारे में हमारे शास्त्रों क्या कहा गया है। ज्यादातर पौराणिक ग्रंथों में इस बात को कई तरह से कहा गया है कि सोने की खरीदारी से जितनी खुशी नहीं होती है उससे अधिक चिंता बढ़ जाती है। हमेशा यह चिंता सताती है कि सोना चोरी न हो जाए। इसे कैसा संभालकर रखें। पड़ोसी की नजर सोने के गहनों पर नहीं जाए, क्योंकि नजर लग जाएगी।यह भी कहा जाता है कि किसी अवसर पर सोने के गहने पहन लें तो हमेशा इसी पर ध्यान रहता है कि कहीं गिर न जाए, कोई खींच न ले। इस चिंता के कारण उत्सव का पूरा आनंद भी नहीं उठा पाते हैं। सोना सिर्फ आपको चिंतित ही नहीं करता है बल्कि आपकी सोच और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इससे अभिमान भी जन्म लेता है। यही कारण है कि रहीम ने लिखा है कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। वा खाये बौराय नर, वा पाये बौराय।। इस दोहे में रहीम ने दो बार कनक शब्द का प्रयोग किया है। एक कनक धतूरे के लिए और दूसरा सोना के लिए। रहीम ने कहा है कि सोने का नशा धतूरे भी ज्यादा होता है। धतूरा खाने के बाद आदमी बौरा जाता है लेकिन सोने का नशा इतना तेज होता है कि इसे प्राप्त कर लेने मात्र से इंसान बौरा जाता है। पुराणों में कथा है कि कलियुग का प्रवेश भी सोने के माध्यम से हुआ था। कलियुग सोने में निवास करता है इसलिए सोने के कारण विवाद और रिश्तों में दूरियां तक आ जाती है। साधु पुरूष कहते हैं कि सोना चिंता का बड़ा कारण है। जब आप इसे पाने की सोचने लगते

# स्कूलों के दरवाजे बंद, सवालों से क्यों डर रहीं हैं सरकारें?

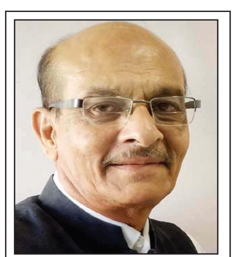

सनत जैन

जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कार्यकताओं के साथ ग्रामीणों की झड़प और मारपीट की घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सीजेपी का आरोप है, इस विरोध के पीछे भाजपा समर्थक थे। उपलब्ध रिपोर्ट में भाजपा ने दावा किया है, ग्रामीणों ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकताओं का विरोध करते हुए उनके साथ मारपीट कर उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। मुद्दा केवल यह नहीं है, जयपुर में किसने किसे पीटा। असली प्रश्न यह है, सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति देखने, उसकी तस्वीर लेने और उसे जनता के सामने रखने से किसे डर लग रहा है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी के लिए प्रधानाचार्य की अनुमति अनिवार्य करने का आदेश क्यों सामने आया है? छात्रों से बातचीत करने पर क्यों रोक लगाई जा रही है? आदेश पर सरकार का तर्क बच्चों की सुरक्षा, निजता और विद्यालय में अनावश्यक व्यवधान को रोकने की बात कही जा रही है। यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब जेन-अल्फा के स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी मांग को लेकर कई राज्यों के कई स्थानों पर सड़क पर उतरे हैं। जब सीजेपी एवं अन्य राजनीतिक दल सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर अभियान चला रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता और सच को छुपाने को लेकर सवाल उठते हैं।

उत्तर प्रदेश में भी बिना अनुमति सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स के प्रवेश पर रोक की खबर है। वहां भी प्रशासन का तर्क सुरक्षा और पढ़ाई में व्यवधान बताया गया है। यह कहना कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें अपनी कमियां छिपाना चाहती हैं। पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, यह सवाल जरूर महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठनों की सक्रियता को इसी व्यापक राजनीति से जोड़ा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा से जुड़े हुए अनुवांशिक संगठन लंबे समय से विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कर-के वहां हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन पर इस तरीके की कोई रोक-टोक नहीं है। यदि कोई संगठन स्कूल-कॉलेजों की समसस्यों को देखकर और सुनकर समाधान के लिए प्रशासन और सरकार के सामने लाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में उसका स्वागत होना चाहिए। यही अधिकार विपक्षी दलों और स्वतंत्र सामाजिक संगठनों को भी मिलना चाहिए। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिक्षा संस्थान किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं हैं। वे जनता के पैसे से चलते हैं। वहां पढ़ने वाले बच्चे समाज के भविष्य हैं। स्कूल की टूटी छत, जर्जर भवन, शिक्षक की कमी, शौचालय, पेयजल, प्रयोगशाला या पाठ्यपुस्तकों की कमी की किसी भी समस्या को उजागर करने वाला व्यक्ति राजनीतिक विरोधी हो सकता है। कम उम्र के छात्रों की समस्या को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। ऐसी स्थिति में कम उम्र के छात्रों के अधिकार को कैसे छीना जा सकता है।

जयपुर की घटना इसलिए गंभीर है, क्योंकि सीजेपी शिक्षा एवं परीक्षा संबंधी मुहिम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है। राजस्थान में प्रशासन, पुलिस और भाजपा कार्यकताओं से टकराव की खबरें सामने आना चिंता का कारण है। कुछ दिन पहले अलवर में जर्जर स्कूल को लेकर सीजेपी अभियान के बाद सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने की रिपोर्ट आई थी। इसका अर्थ यह है कि दबाव बनाने वाली सक्रियता से व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। राजनीति का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग मुद्दों पर नहीं, बल्कि एक-दूसरे को मैदान से हटाने के लिए होने लगे। भाजपा कार्यकताओं ने किसी संगठन के कार्यकताओं पर हमला किया है? तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यदि सीजेपी के कार्यकताओं ने बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश किया या स्थानीय लोगों को आपत्ति थी, उसके लिए कानून के तहत शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। भीड़ को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहे जेन जेड और जेन अल्फा से जुड़े आंदोलनों को लेकर भी राजनीतिक दलों में नई रणनीतियां बनना शुरू कर दी हैं। छात्र एवं युवा अब आश्वासन राजनीतिक भाषण नहीं सुनता है। वह अपनी समस्याओं का समाधान निश्चित समय सीमा पर चाहता है। वह सवाल का जवाब भी तुरंत चाहता है। आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, फीस, डिजिटल अधिकार और सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता बड़े राजनीतिक मुद्दे बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा और संघ परिवार यदि युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सक्रियता बढ़ाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विपक्षी दल भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष को समान अधिकार प्राप्त हैं। मुकाबला होना चाहिए,विचारों मे हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सरकार के लिए सबसे अच्छा रास्ता स्कूलों के दरवाजे बंद करना नहीं, स्कूलों की समस्याओं को जवाबदेही के साथ सुलझाना और पारदर्शी बनाना है। कोई भी कैमरा वहां की व्यवस्था की सच्चाई को दिखाएगा, तो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जवाबदेह होंगे। सरकार को इसमें शर्मिंदा होने के स्थान पर, जिन अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि व्यवस्थाओं में सुधार हो। बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए नियम बनाना उचित हो सकता है, मगर स्वतंत्र निरीक्षण, पत्रकारिता और जनप्रतिनिधियों की निगरानी के लिए स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। जयपुर मैं जो घटना हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच से सच सामने आना चाहिए। इसमें भाजपा कार्यकताओं की भूमिका है, तो उन पर कार्रवाई हो, यदि किसी पक्ष ने कानून तोड़ा है, उसके खिलाफ समान कार्रवाई हो। लोकतंत्र में सत्ता की असली ताकत विरोधी आवाज को दबाने में नहीं, बल्कि विरोधी आवाज सुनकर व्यवस्था को बेहतर बनाने में है। सरकारी स्कूलों के दरवाजे बच्चों के लिए खुले रहने चाहिए। उनकी समस्याओं पर सवाल पूछने वालों के लिए भी लोकतांत्रिक रास्ते भी खुले रहने चाहिए। सवाल स्कूल का नहीं छात्रों के मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। यदि 16 साल से कम उम्र के छात्र सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यह सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण है। वर्तमान का बच्चा अपनी जरूरत के लिए इसी तरह का प्रदर्शन अपने घर पर भी करता है और अब वह स्कूल में उसकी जो जरूरत है उन मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतर रहा है तो इस मामले को दबाया नहीं जा सकता है। बच्चे तो बच्चे हैं, जिद करेंगे, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। उनका प्रदर्शन आक्रामक ही होता जाएगा।

# सड़क पर पैदल चलना भी मौलिक अधिकार, फिर फुटपाथ क्यों बेहाल?

सुनील कुमार महला

सड़क पर पैदल चलना मौलिक अधिकार है, लेकिन आज भारत के कई शहरों में पैदल चलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल, आज भी बहुत से शहरों में फुटपाथ या तो बने ही नहीं हैं, या उन पर अतिक्रमण, पार्किंग और निर्माण सामग्री के कारण लोगों के चलने की जगह नहीं बचती। ऐसे में यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब किसी व्यक्ति के पास सड़क पर सुरक्षित रूप से पैदल चलने की जगह ही नहीं है, तो उसे वास्तव में आवागमन की आजादी कैसे मिल सकती है?

उक्त संदर्भ में यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ही यानी कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा है कि सुरक्षित और निर्धारित पैदल मार्ग पर चलना भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत आवागमन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। वास्तव में, यह मामला उस दुखद घटना से जुड़ा हुआ था, जिसमें पांच साल के एक बच्चे की सड़क पर टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहां न फुटपाथ था और न ही सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था। कहना गलत नहीं होगा कि आज कई भारतीय शहरों में फुटपाथ पर अतिक्रमण, टूटे या गायब फुटपाथ, सड़क पार करने के लिए अपर्याप्त क्रॉसिंग, तेज रफ्तार वाहन और यातायात नियमों का उल्लंघन पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ाते हैं और हमारे देश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती है। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में 35,221 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, जो कुल सड़क दुर्घटना मौतों का 20.4% थी।सच तो यह है कि आज पर्याप्त पैदल यात्री बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है?। यहां पाठकों को बताता चलूं कि फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव मुख्यतः राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के दायरे में आता है, इसलिए सरकारों और संबंधित निकायों को इन पर ध्यान देना चाहिए। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वैसे विश्व में सड़क की गुणवत्ता, फुटपाथ, पैदल पार-पथ, ट्रैफिक नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मामलों में नीदरलैंड को दुनिया के सबसे अच्छे उदाहरणों में गिना जाता है। सच तो यह है कि नींदरलैंड पैदल चलने के लिए दुनिया में एक अग्रणी देश है, जहां पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए अलग एवं सुरक्षित मार्ग, कम गति वाले क्षेत्र और बेहतर सड़क डिजाइन उपलब्ध हैं। नींदरलैंड के बाद डेनमार्क विशेषकर कोपेनहेगन में पैदल यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित फुटपाथ, क्रॉसिंग और ट्रैफिक-शांत क्षेत्र हैं। वहीं पर स्वीडन विश्व में कम पैदल मृत्यु दर और मजबूत सड़क-सुरक्षा व्यवस्था के कारण अग्रणी देशों में शामिल है।नॉर्वे(यूरोप में) तथा फिनलैंड भी पैदल मार्गों और सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था के मामले में विश्व में अहम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

हाल फिलहाल, यहां यह कहना चाहूंगा कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क पर पैदल चलने के संदर्भ में जो फैसला दिया है,इस फैसले का सीधा सा संदेश यही है कि सरकार और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि ये लोगों को सुरक्षित फुटपाथ और सड़क पार करने की उचित सुविधा उपलब्ध कराएं। वास्तव में,सच तो यह है कि नगर निगम, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण और पंचायतों को आगे आकर इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करना होगा।बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो, आंकड़े हमारी चिंताएं बढ़ाते हैं। यह बहुत ही दुखद है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक लोग पैदल यात्री होते हैं। कई शहरों में फुटपाथ टूटे हुए, संकरे, असुरक्षित या लगातार बाधित पाए गए हैं। यानी समस्या केवल फुटपाथ बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, चौड़ा, समतल और सभी के लिए सुगम बनाने की है। वास्तव में,इसके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग न हो, वहां पर पर्याप्त रोशनी हो, सड़क पार करने के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग बने और दिव्यांगजनों के लिए रैंप तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। सड़क की खुदाई या निर्माण कार्य के दौरान भी पैदल यात्रियों के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः यह बात कही जा सकती है कि सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं हैं। पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांगजन सभी सड़क के बराबर अधिकार रखते हैं। सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है।

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार।)

# सीएम मोहन यादव ने एफआईआर के बाद डीजीपी को दिए निर्देश, पुलिसिया धौंस दिखाकर जमीन खरीदने का आरोप

## एफआईआर दर्ज होने के बाद सीएम मोहन यादव ने डीजीपी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**भोपाल।** वसूली केस के आरोपों में कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया घिर गई हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीएम मोहन यादव ने उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नेहा पच्चीसिया ने अपने ऊपर चल रहे मामले को लेकर हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। लेकिन वहां से राहत नहीं मिली है। सीएम के निर्देश पर नेहा पच्चीसिया को सस्पेंड कर दिया गया है।

### सीएम ने दिए सस्पेंड करने के निर्देश

सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक्स पर लिखा गया है कि कटनी में सामने आए गंभीर प्रकरण को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को संबंधित CSP के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, दबाव या पद के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

### कौड़ियों के दाम में जमीन खरीदने के आरोप

नेहा पच्चीसियादरअसल, नेहा पच्चीसिया तेजतर्रार सीएसपी रही हैं। कटनी में पोस्टिंग के दौरान वह विवादों में घिर गई हैं। आरोप है कि हत्या के एक मामले में आरोपी की 80 लाख रुपए की जमीन पुलिसिया धौंस दिखाते हुए 18 लाख रुपए में अपने एजेंट के जरिए खरीद लीं। इसके बाद एक ट्रांसपोर्टर ने भी वसूली का आरोप लगाया था।

### कटनी एसपी ने की थी कार्रवाई

ये मामले सामने आने के बाद कटनी एसपी ने तात्कालिक कार्रवाई की थी। उनके सरकारी ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ ही उनसे थानों का प्रभार ले लिया गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो जबलपुर जोन के आईजी ने एएसपी अनु बेनीवाल को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं, एएसपी अनु बेनीवाल ने इस मामले की जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन लोगों पर कटनी में एफआईआर हुई है। आगे की पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।

# सगाई टूटी, 19 साल की मारिया तनाव में थी जहरीली चीज खाने के बाद मौत, पुलिस कर रही जांच

## मामला एमआईजी थाना क्षेत्र की स्वर्ण बाग कॉलोनी का है. यहां रहने वाली मारिया शेख ने जहरीली चीज खा ली. हालत बिगड़ी तो परिवार अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**इंदौर।** एमआईजी थाना क्षेत्र में 19 साल की युवती की जहरीली वस्तु खाने के बाद अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, युवती की कुछ समय पहले सगाई हुई थी, लेकिन बाद में मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया था. इसके बाद से वह तनाव में थी. परिजनों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामला स्वर्ण बाग कॉलोनी का है. यहां रहने वाली 19 वर्षीय मारिया शेख ने घर पर जहरीली चीज खा ली थी. तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो वे उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही. आखिरकार उपचार के दौरान मारिया ने दम तोड़ दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मारिया की कुछ समय पहले सगाई हुई थी. बाद में किसी वजह से उसके मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया. परिजनों के मुताबिक, इसके बाद से मारिया परेशान रहने लगी थी. पुलिस को शुरुआती तौर पर आशंका है कि सगाई टूटने के बाद चल रहे मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया. हालांकि पुलिस ने अभी इसे अंतिम वजह नहीं माना है. सगाई क्यों टूटी, मंगेतर के साथ उसके रिश्ते कैसे थे और घटना से पहले क्या हुआ था- इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद एमआईजी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है. साथ ही सगाई टूटने के कारणों समेत मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस की शुरुआती जांच में सगाई टूटने के बाद युवती के तनाव में होने की बात सामने आई है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी. अगर जांच में कोई दूसरा तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

# 'चोर भाइयों... चोरी मत करो, सीधे कैश ले जाओ' शामली में क्यों किसानों ने की ये अनोखी अपील?

## पुलिस की नाकामी से तंग आकर किसानों ने अनोखा कदम उठाया है. लाचार होकर एक किसान ने अपने ट्यूबवेल के गेट पर लिखा कि चोर भाइयों चोरी मत करो, जितने का सामान बेचते हो उतने रुपये यहीं से ले जाओ

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**यूपी।** शामली जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में नलकूपों से सबमर्सिबल पंप, केबल और स्टार्टर चोरी होने की घटनाओं से परेशान किसानों ने चोरों से अजब अपील की है. उन्होंने अब ट्यूबवेल के दरवाजों पर चोरों के नाम अनोखी अपील लिखना शुरू कर दिया है. पुलिस की नाकामी और ढुलमुल रवैये के कारण गांव कुड़ाना, लाक, लिसाढ़, बहावड़ी, बंतीखेड़ा, आदमपुर और एलम सहित कई गांवों में 70 से अधिक नलकूपों पर चोरी हो चुकी है. रात के अंधेरे में सुनसान खेतों का फायदा उठाकर चोर हजारों का सामान उखाड़ ले जाते हैं. इससे सिंचाई ठप हो जाती है और फसलें सूखने का खतरा मंडराने लगता है.

### 'चोरी मत करो, सीधे पैसे ले जाओ'

गांव कुड़ाना के एक पीड़ित किसान ने नलकूप के गेट पर लिखा, 'चोर भाइयों, चोरी मत करो. जितने रुपये का सामान चोरी करके बेचते हो, उतने रुपये ले जाया करो.' किसान का कहना है कि केबल या पंप चोरी होने से हजारों रुपये के नुकसान के साथ-साथ कई दिनों तक सिंचाई पूरी तरह प्रभावित हो जाती है. नया सामान लगवाने में समय और भारी पैसा दोनों बर्बाद होता है. जिले में अब तक 70 से अधिक ट्यूबवेल पर चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं. 15 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हुई. किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक का आरोप है कि पुलिस सिर्फ झूठा आश्वासन देती है, इसलिए अब किसान खुद रात में नलकूपों पर पहरा देने को मजबूर हैं. मामले पर एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि नलकूपों पर हो रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोर गिरोह का राजफाश कर उन्हें जेल भेजा जाएगा. हालांकि, किसान अब भी लगातार हो रही वारदातों से सहमे हुए हैं और रात में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं

# 16 साल का छात्र और 38 साल की ट्यूशन टीचर घंटों फोन पर होती थी बात; एक दिन अचानक दोनों हो गए लापता

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**आगरा।** 16 साल के छात्र और 38 वर्षीय ट्यूशन टीचर के एक साथ लापता होने से हड़कंप मच गया. छात्र स्कूल प्रोजेक्ट के लिए घर से निकला था, जबकि शिक्षिका भी घर पर नहीं मिलीं. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज से दोनों की तलाश शुरू की. कई शहरों में सुराग मिलने के बाद छात्र नोएडा और शिक्षिका मथुरा में सुरक्षित मिलीं. दोनों को परिजनों को सौंप दिया गया आगरा में 16 साल के छात्र और उसकी 38 वर्षीय ट्यूशन टीचर के एक साथ अचानक लापता होने की कहानी ने पुलिस को भी कई दिनों तक उलझाए रखा. चार अगस्त को छात्र घर से निकला तो वापस नहीं लौटा. इसी बीच पता चला कि उसे ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका भी अपने घर पर नहीं हैं. एक नाबालिग छात्र और उससे करीब 22 साल बड़ी शिक्षिका के एक साथ लापता होने से मामला गंभीर हो गया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो मोबाइल कॉल डिटेल से दोनों के बीच लंबे समय तक बातचीत का पता चला. इसके बाद रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को पहली बड़ी कड़ी दी. दोनों आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन में बैठते दिखाई दिए. इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग शहरों में तलाश शुरू की और आखिरकार छात्र को नोएडा, जबकि शिक्षिका को मथुरा से बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक, दोनों को सुरक्षित बरामद करने के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. परिजनों ने फिलहाल किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है. पूरा मामला आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र का है. 16 वर्षीय छात्र शहर के एक पब्लिक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता है. परिवार के मुताबिक, पढ़ाई को लेकर घर में उसे डांट पड़ती थी और वह इससे परेशान रहता था. छात्र धांधूपुरा इलाके में 38 वर्षीय शिक्षिका से ट्यूशन पढ़ता था. चार अगस्त को छात्र स्कूल प्रोजेक्ट से जुड़े काम के लिए करीब तीन हजार रुपये लेकर घर से निकला था. उसने अपनी साइकिल एक दोस्त के घर पर खड़ी कर दी. इसके बाद परिवार को लगा कि वह स्कूल या किसी काम से गया होगा, लेकिन देर तक घर नहीं लौटा. जब काफी समय बीत गया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारों और दोस्तों से जानकारी ली गई, लेकिन छात्र का कोई पता नहीं चला.

## अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे से 50000000 रुपये की जमीन कब्जामुक्त, नगर निगम ने की कार्रवाई

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**अलीगढ़।** उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जिला प्रशासन और नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिट के कब्जे वाली 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। 3.863 हेक्टेयर सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 500 करोड़ रुपये बताई जा रही है। 500 करोड़ रुपये कीमत की भूमि पर रू ने कई वर्षों से अपना कब्जा कर रखा था।

गुरुवार को एसडीएम गजेंद्र पाल सिंह और नगर निगम आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश कराई। वहीं, रू के कब्जे वाली सरकारी भूमि राजस्व अभिलेखों में बंजर और ऊसर दर्ज है। इस बेशकीमती जमीन को लेकर पूर्व में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से दावा किया गया था और यूनिवर्सिटी के अभिलेखों में भी इस भूमि का उल्लेख किया गया था। करीब 500 करोड़ की जमीन पर कोई स्थायी निर्माण कार्य नहीं होने और खाली पड़ी होने के कारण सरकारी नियमों के अनुसार, पहले ही इसे हस्तांतरित किया जा चुका था। बेशकीमती जमीन को कब्जामुक्त कराने के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जमीन पर बुलडोजर चलवाकर प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारियों ने इस भूमि पर अपने स्वामित्व होने का बोर्ड लगा दिया है। हालांकि, नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर रू प्रशासन की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। अलीगढ़ नगर निगम आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि गुरुवार को इस बेशक़ीमती ज़मीन को खाली कराया गया है। इस भूमि का सदुपयोग नगर निगम द्वारा जनहित व शहरहित में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। भूमि की उपयोगिता को देखते हुए नगरीय क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाने की स्थापना, बच्चों के विद्यालय, इंटर कालेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स जैसे महत्वपूर्ण और जन उपयोगी प्रोजेक्ट को प्रभावी रूप देने के लिए इस संपत्ति का भविष्य में इस्तेमाल किया जाएगा। इस भूमि की अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ आंकी गई है

## कुशीनगर के पडरौना राजदरबार की 1503 एकड़ जमीन पर अब सरकार का कब्जा, खत्म हुआ 44 साल पुराना विवाद

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**कुशीनगर।** यूपी के कुशीनगर जिले के पडरौना राजदरबार की 1503.57 एकड़ सीलिंग भूमि अब राज्य सरकार कब्जा हो गया है। करीब 44 वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद के बाद अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कुशीनगर ने 14 अगस्त 2026 को मामले में अंतिम आदेश पारित किया। आदेश के तहत विधिक उत्तराधिकारियों के उपयोग के लिए 18.04 एकड़ सिंचित भूमि छोड़ते हुए शेष 1503.57 एकड़ भूमि को अतिरिक्त घोषित कर राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया।

डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर मामले की प्रभावी पैरवी और लगातार निगरानी की गई। प्रशासन के मुताबिक, अब इस जमीन का इस्तेमाल भूमिहीन और गरीब परिवारों को नियमानुसार कृषि एवं आवासीय पट्टा देने के साथ ही स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल मैदान, पंचायत भवन सहित अन्य जनकल्याणकारी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। पडरौना राजदरबार की मृतक खातेदार रानी रेवती देवी पत्नी स्वर्गीय रवि प्रताप नरायन सिंह की पडरौना, खड्डा, कसया और कप्तानगंज तहसील में स्थित भूमि पर उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के तहत सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई थी। 30 नवंबर 1978 को नियत प्राधिकारी ने पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत 359.61 एकड़ और संशोधित अधिनियम के तहत 66.75 एकड़ सिंचित भूमि को अतिरिक्त घोषित किया था। इस आदेश के खिलाफ खातेदार ने तत्कालीन जिला जज, देवरिया के यहां अपील की। 3 फरवरी 1982 को अपीलीय न्यायालय ने आदेश निरस्त करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया। इसके बाद रानी रेवती देवी और अन्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।

## घाट की सीढ़ियां जलमग्न, गंगा आरती के प्लेटफॉर्म डूबे... काशी की खूबसूरती पर बाढ़ का ग्रहण

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**वाराणसी।** गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. गंगा के किनारे बसे पूर्वी यूपी के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. वहीं, इसका असर अब वाराणसी में भी दिखने लगा है. गंगा घाट और गंगा आरती वाराणसी की खूबसूरती का पर्याय माने जाते हैं और इन दोनों पर ही गंगा नदी के जलस्तर में आए उफान ने ग्रहण लगा दिया है., हालात ऐसे हैं कि स्थानीय नागरिकों और सैलानियों से गुलजार रहने

वाली गंगा घाट की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं और घाटों का संपर्क एक-दूसरे से कट गया है. वाराणसी की चौपाटी कहे जाने वाले अस्सी घाट की बात करें तो यो पहले पूरे वक्त गुलजार रहा करता था. आज यहां चारों तरफ बाढ़ की विभीषिका ही दिख रही है., अस्सी घाट पर गंगा आरती के लिए बने सभी सात प्लेटफॉर्म्स गंगा नदी के पानी में डूब चुके हैं. हवन कुंड तक बाढ़ के पानी में समा चुका है तो वही रोज होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच सुबह बनारस तक बाढ़ का पानी आ पहुंचा है. गंगा नदी उफान पर हैं, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं दिख रही जो खतरा मोल लेकर, अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा स्नान कर रहे हैं.

## सात फीट गहरे में पानी में फंसा ट्रक, घनघोर अंधेरे के बीच तैरते हुए पहुंचे थाना प्रभारी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**मैहर।** मध्यप्रदेश के मैहर जिले में भारी बारिश के बीच जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने का दुस्साहस सीधी के एक ट्रक चालक और क्लीनर को भारी पड़ गया। गुरुवार की देर रात ताला थाना क्षेत्र के मर्जुआ नाले के भीषण बहाव में ट्रक अनियंत्रित होकर सात फीट गहरे पानी के बीच जा फंसा। चारों तरफ से सैलाब से घिरे दोनों युवक मौत के मुहाने पर पहुंच गए थे। ऐसे संकट के समय मुकुंदपुर चौकी प्रभारी ने अदम्य साहस दिखाते हुए करीब 300 मीटर तक उफनती धारा में तैरकर दोनों की जान सुरक्षित बचा ली। जानकारी के अनुसार, सीधी जिले से सतना की ओर जा रहा ट्रक (क्रमांकMP 19 ZR 7976) जैसे ही ताला क्षेत्र के मर्जुआ नाले के पास पहुंचा, नाला पूरे उफान पर था। पुलिस ने खतरे को देखते हुए इस रास्ते पर पहले ही आवाजाही रोक दी थी। इसके बावजूद चालक राकेश शाहू (34 वर्ष, निवासी बहरी, सीधी) और क्लीनर इन्द्रकमल द्विवेदी (28 वर्ष, निवासी सिहोलिया बहरी, सीधी) ने लापरवाही बरतते हुए वाहन को तेज बहाव में आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दूरी पर ट्रक करीब 7 फीट गहरे पानी में बंद होकर फंस गया और पानी का स्तर लगातार बढ़ने लगा। हादसे की खबर मिलते ही ताला थाना पुलिस और मुकुंदपुर चौकी पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुकुंदपुर चौकी प्रभारी नागेश्वर मिश्रा खुद पानी में कूद पड़े।

## फ्रीजर में वेज और नॉनवेज एक साथ, किचन में कॉकरोच और चूहों की लीद

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**इंदौर।** फाइव स्टार होटल के किचन में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। गुरुवार रात खाद्य विभाग और एफएसएसएआई की टीम ने होटल और क्लब में संचालित किचन का निरीक्षण किया। करीब रात 10.00 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सामग्री के रखरखाव, स्टोरेज, तापमान, साफ-सफाई और लाइसेंस की जांच की गई। जांच के दौरान टीम को कई अनियमितताएं मिलीं है। निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में वेज और नॉनवेज एक साथ रखी मिली। करीब 66 किलो नॉनवेज सामग्री बिना पैकिंग के मिली। इस पर निर्माण तारीख से जुड़ा लेबल भी नहीं था। सी-फूड, चिकन और मटन को अलग-अलग रखने के बजाय एक ही स्टोरेज में रखा गया था। खाद्य सामग्री को जिस निर्धारित तापमान पर रखा जाना चाहिए उसका भी उचित पालन नहीं किया जा रहा था। जांच दल में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी, एफएसएसएआई पश्चिम रीजन के अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर रितु जाट, तहसीलदार सपना शर्मा सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। होटल के स्टोर और किचन की जांच के दौरान मूंगफली में फंगस मिली। इसके अलावा सब्जियों के स्टोर में सड़े हुए आलू और टमाटर भी रखे मिले। कई खाद्य उत्पाद बिना उचित लेबल के पाए गए। कुछ टॉपिंग के टेट्रापैक लीक मिले। इससे खाद्य सामग्री के खराब होने या दूषित होने की आशंका सामने आई। किचन और होटल परिसर में कॉकरोच के साथ चूहों की लीद भी मिली। जांच के दौरान किचन में चूहे दिखाई देने की बात भी सामने आई। पैलेट के नीचे चूहों की मौजूदगी के संकेत मिले। ड्राय स्टोरेज वाले कमरे की दीवार और फर्श में दरारें मिलीं। प्लेट्स के नीचे भी गंदगी पाई गई। किचन में खाद्य सामग्री रखने वाले कुछ कंटेनर और नॉनवेज स्टोरेज के बर्तन जंग लगे हुए मिले। भोजन तैयार करने वाले प्लेटफार्म पर भी जंग पाया गया। जांच के दौरान फ्रिज में रखी पैक्ड कुल्फी पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर दर्ज नहीं मिले।

## जिंदगी बचाने वाली कैंसर दवाओं का 'काला कारोबार', क्राइम ब्रांच ने 17 को पकड़ा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**नई दिल्ली।** कैंसर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर नकली दवाओं का कारोबार करने वाले एक इंटर स्टेट सिंडिकेट का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। नकली और सरकारी अस्पतालों से अवैध तरीके से डायवर्ट की गई महंगी एंटी-कैंसर दवाओं की खरीद, स्टोरेज, पैकिंग, सप्लाई और बिक्री में शामिल गैंग के 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 9 करोड़ रुपये कीमत की 588 गरी एंटी-कैंसर दवा की शीशियों, 6 खाली वायल, खाली दवा के 7 बॉक्स और अन्य 3.021 यूनिट दवाएं बरामद की है। इसके अलावा 50 लाख रुपये कैश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डायरी और पैकिंग का सामान भी जब्त किया गया है। डीसीपी (क्राइम) आदित्य गौतम के मुताबिक, जांच में गैंग का नेटवर्क दिल्ली-ह्ष्ट्क्र मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, हरियाण, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैला मिला। दवाओं की खरीद, स्टोरेज और सप्लाई में कई लेवल पर बिचौलियों की भूमिका सामने आई है। एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में इंस्पेक्टर कमल कुमार की टीम ने इंस्ट दिल्ली, रोहिणी और मुंबई के कई संदिग्ध ठिकानों की पहचान की। इसके बाद 11 जुलाई को इन जगहों पर रेड की गई। कई एंटी-कैंसर दवाएं बरामद होने के बाद 12 जुलाई को केस दर्ज किया गया। जांच के मुताबिक, गैंग 3 प्रमुख तरीकों से काम करता था। सबसे पहले नकली एंटी-कैंसर दवाएं खरीदी जाती थीं। फिर अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं को कर्मचारियों की मदद से निकलवाकर बाजार में पहुंचती थी। फिर सरकारी संस्थानों और गोदामों से दवाओं को अवैध तरीके से बिचौलियों के जरिए बाजार में सप्लाई किया जाता था। पुलिस के मुताबिक, हैदराबाद के नामी हॉस्पिटल से जुड़े रामदास सतीश कुमार अस्पताल से दवाए निकालने वाले नेटवर्क का हिस्सा था। फार्मासिस्ट मलुगारी श्रीनाथ रेड्डी दवाएं मुहैया करवाता था। ऑन्कोलॉजी विभाग में नर्सिंग इंचार्ज जसवंत शर्मा वायल देता था।

## किन्नरों से नेग को लेकर विवाद, चाकू मारकर मासूम के पिता की हत्या; बेटे के जन्म की खुशी मातम में बदली

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**नई दिल्ली।** ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बेटे के जन्म की पार्टी मनाने के दौरान कुछ किन्नर नेग मांगने आ गए। इस दौरान हुए झगड़ा में किन्नरों के साथी सोनू ने जय सिंह, उनके ससुर बिट्टू सिंह और चचेरा ससुर गुड्डू सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। घायलों को एलबीएस अस्पताल ले गए, जहां जय सिंह की मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद गुरुवार सुबह जय सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। ईस्ट जिले के DCP राजीव कुमार ने बताया कि जय सिंह अपने परिवार के साथ 11 ब्लॉक में रहते थे। परिवार में मां गीता कौर, दो बहनें, एक छोटा भाई अजय सिंह (17) और पत्नी गुरप्रीत कौर सहित अन्य सदस्य हैं। जय सिंह गुरुग्राम में सरिया बांधने का काम करते थे। थे। 13 दिन पहले जय सिंह और गुरप्रीत के यहां बेटे का जन्म हुआ था। बुधवार रात को जय सिंह के ससुर बिट्टू सिंह ने ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। रात करीब 9-10 बजे जय सिंह यहां पहुंचे। आरोप है कि 4-5 किन्नर नेग लेने पहुंचे। पैसों को लेकर झगड़ा हुआ तो जय सिंह की ओर से किसी ने एक किन्नर को थप्पड़ मार दिया। किन्नरों के साथ आए ड्राइवर सोनू ने चाकू निकालकर जय सिंह को मार दिया। बचाने आए बिट्टू और गुड्डू को भी चाकू मारा गया। सोनू को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सोनू को छुड़ाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस की कई बाइक और एक गाड़ी को तोड़ दिया। घायल सोनू को जीटीबी में भर्ती कराया, जबकि एक किन्नर से पूछताछ की जा रही है। कल्याणपुरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जय सिंह के मामा जसवंत सिंह ने बताया कि जय सिंह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। कई साल पहले अचानक इसके पिता राजू गायब हो गए थे। घर में मा गीता कौर के अलावा एक छोटा भाई, दो छोटी बहनें और पत्नी है। उनकी कमाई से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था।

## महाराष्ट्र में किसानों की तरह ही मछुआरों को मिल सकता है कर्जमाफी का लाभ, नितेश राणे को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**मुंबई।** किसानों की तरह ही राज्य के मछुआरों को कर्जमाफी का लाभ दिलाने की दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है। मत्स्यपालन करने वाले किसानों, व्यावसायिक मछुआरों और कर्ज की राशि से जुड़ी जानकारी एकत्र करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। मत्स्यव्यवसाय एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस संबंध में चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने मछुआरों और उनके कर्ज से संबंधित जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में करीब 19 हजार मत्स्य किसानों और व्यावसायिक मछुआरों पर लगभग 80.87 करोड़ रुपये तक का कर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से करीब 9,900 मछुआरों ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मत्स्य व्यवसायियों को कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। इस कर्ज को माफ करने की मांग मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी राणे को दी है। मत्स्य व्यवसाय विभाग को कर्ज की राशि आदि की जानकारी संकलित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सहकार विभाग के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। विभाग द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में मछुआरों की कर्जमाफी का प्रस्ताव रखा जाएगा ।

### मछुआरों को 20 हजार रुपये की मदद:

दूसरी ओर, बारिश के मौसम में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान राज्य सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मछुआरों को आर्थिक सहायता देने की योजना पर भी विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य के 8,829 मछुआरा परिवारों को प्रत्येक 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है। इसके लिए करीब 17 करोड़ 65 लाख 40 हजार रुपये की आवश्यकता होगी। वर्तमान योजना के तहत पात्र मछुआरों को केंद्र और राज्य के हिस्से से सालाना 4,500 रुपये की सहायता दी जाती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस सहायता राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है।

# वई में किन्नर बनकर घर में घुसा शख्स, महिला से दुष्कर्म, गर्भ धारण का दावा कर 2 हजार ठग लिए

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**मुंबई।** पवई इलाके में एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति किन्नर के रूप में महिला का वेश धारण कर पीड़िता के घर में दाखिल हुआ और संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने का झांसा देकर उसके साथ कथित दुष्कर्म किया। साथ ही, घटना के बाद आरोपी महिला से 2 हजार रुपये लेकर फरार हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने नकली किन्नर बने आरोपी अनिल शिंदे को ठाणे के कालवा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, घटना 19 अगस्त की है। पीड़िता अपने घर पर थी, जबकि उसका पति काम पर गया हुआ था। घर में मौजूद बुजुर्ग रिश्तेदार ने दरवाजा खोला तो अनिल नामक व्यक्ति ने खुद को किन्नर बताते हुए महिला को आशीर्वाद देने का नाटक किया। किन्नर मानकर बुजुर्ग ने उसको घर के अंदर आने दिया। बातचीत के दौरान अनिल (आरोपी) को बुजुर्ग से पता चला कि उसकी बहु यानी पीड़िता की शादी को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसे कोई संतान नहीं है। इसके बाद आरोपी ने संतान प्राप्ति के लिए विशेष

अनुष्ठान करने की बुजुर्ग से बात कही।

### अनुष्ठान के बहाने किया कथित दुष्कर्मः

FIR के अनुसार, आरोपी ने अनुष्ठान के बहाने बुजुर्ग को कहीं और भेजकर उसकी बहु को कुछ देर जमीन पर बिठाया और फिर बिस्तर पर लेटने को कहकर कथित तौर पर उसके शरीर को गलत तरीके से छूने लगा। इसके बाद उसने महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाया। हालांकि, शुरुआत में पीड़िता को तुरंत घटना की गंभीरता का अहसास नहीं हुआ। लेकिन, आरोपी ने जाते समय जल्द गर्भधारण होने का दावा किया और पैसे मांगे। पीड़िता ने उसे 2 हजार रुपये दे दिए। पुलिस का कहना है कि आरोपी के जाने के एक घंटे बाद महिला को अपने साथ हुई यौन उत्पीडन की घटना का अहसास हुआ। उसने पति को फोन कर पूरी जानकारी दी। इसके बाद दंपती ने पुलिस से संपर्क किया और मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस ने इमारत और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली। एक फुटेज में आरोपी एक ऑटोरिक्शा में जाते दिखाई दिया। पुलिस ने ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर चालक का पता लगाया और आरोपी के उतरने की जगह की जानकारी हासिल की। तकनीकी जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को कलवा से गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय अदालत ने आरोपी को 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इसी मोड्स ऑपरेंडी अपनाकर पहले भी किसी अन्य महिला को निशाना बनाया है। डीसीपी दत्ता नलावडे के नेतृत्व में केस की जांच जारी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच रोजमर्रा के विवाद और एक-दूसरे के व्यवहार को लेकर असंतोष अपने आप में ऐसा आचरण नहीं है, जिसके आधार पर विवाह को तोड़ा जा सके। यह टिप्पणी कर कोर्ट ने पति की तलाक की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के की बेंच ने माना कि शादीशुदा जीवन में मतभेद, बहस और कभी-कभार होने वाली नाराजगी स्वाभाविक हो सकती है। इन्हें मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, जब तक व्यवहार इतना गंभीर न हो कि वैवाहिक जीवन जारी रखना असहनीय हो जाए। बेंच ने कहा कि क्रूरता इस बात पर निर्भर करती है कि पति-पत्नी किस तरह का जीवन जी रहे है। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कैसी है। वैसे हर वैवाहिक जीवन में सामान्य झगड़े होते रहते है,इसलिए मानसिक क्रूरता को इन झगड़ो से अलग करके देखना चाहिए। मामले से जुड़े दंपती का विवाह 2003 में हुआ था। पति के मुताबिक, पत्नी उसके माता पिता को परेशान करती थी। साल 2011 में घर छोड़ कर चली गई थी। पत्नी गुस्सैल स्वभाव की थी। वह मां से झगड़ा करती थी। बच्चा न होने के लिए भी उसे दोषी ठहरती थी। वहीं पत्नी ने दावा किया था कि वह ससुराल के घर में रहने आई थी मगर उसे रहने नहीं दिया गया। ससुराल वाले उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे।

# महाराष्ट्र में 1200 से ज्यादा ऑटो-टैक्सी चालकों को नोटिस, मराठी न आने पर एक्शन

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**महाराष्ट्र।** सरकार ने राज्य में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले व्यावसायिक चालकों के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य चालकों और यात्रियों के बीच संवाद को बेहतर और सुगम बनाना है. नियम के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की ओर से गुरुवार से पूरे राज्य में एक विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है. अभियान के पहले ही चरण में कुल 1,268 चालकों को मराठी भाषा का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण नोटिस जारी किया गया है.मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में परिवहन विभाग की टीमों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया 3,995 चालकों की चेकिंग की गई. केवल मुंबई महानगर क्षेत्र (स्र्ब्क्र) में कुल 3,995 वाहन चालकों की जांच की गई. इनमें से 604 चालक ऐसे पाए गए जिन्हें दैनिक कामकाज के लायक व्यावहारिक मराठी का ज्ञान नहीं था. इन सभी को तुरंत नोटिस थमाया गया है.

### शेष महाराष्ट्र का हाल

मुंबई महानगर क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में 4,222 चालकों की जांच की गई, जिनमें से 664 चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रशासन चालकों के प्रति सहानभूतिपूर्ण रुख अपना रहा है. चालकों को भाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया जा रहा है. यह जांच अभियान 30 सितंबर 2026 तक निरंतर जारी रहेगा. मंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद भी यदि कोई चालक नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. नियम से बचने या इसे टालने की कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी.

# दिल्ली में भाऊ गैंग के दो शूटरों का एनकाउंटर, मशहूर डॉक्टर की हत्या की साजिश में शामिल आरोपी गिरफ्तार

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**दिल्ली।** पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बक्करवाला इलाके में भाऊ गैंग के दो कथित शूटरों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी मशहूर डॉक्टर की हत्या की साजिश में शामिल थे. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बक्करवाला इलाके में मुठभेड़ के दौरान भाऊ गैंग के दो कथित शूटरों गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी एक मशहूर डॉक्टर की हत्या की साजिश में शामिल थे. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम को बक्करवाला इलाके में भाऊ गैंग के दो कथित शूटरों के मौजूद होने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-8 और हरियाणा की सीआईए-2 रोहतक की सयुंक्त टीम ने मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

इसके पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लग गई. इसके बाद दोनों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान समीर निवासी रिठाल फोगाट और कुश पुत्र राजवीर निवासी धुभाना के रूप में हुई है जो हाल ही में विजय नगर रोहतक में रह रहा था. पुलिस के मुताबिक, ये दोनों आरोपी एक मशहूर डॉक्टर की हत्या की साजिश में शामिल थे. एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

# दिल्ली वालों की बल्ले-बल्ले, अनधिकृत कॉलोनियों का होगा कायाकल्प; 350 FAR के साथ बनेंगे घर

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**दिल्ली।** अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मास्टर प्लान 2047 में एरिया-बेस्ड रीजेनरेशन का प्रस्ताव है, जिससे पूरे इलाके का नियोजित पुनर्विकास संभव होगा। इसके तहत आसपास की कॉलोनियों के एकीकृत विकास के माध्यम से सड़कें, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप अवैध कॉलोनियों का कायाकल्प तेजी से होगा।

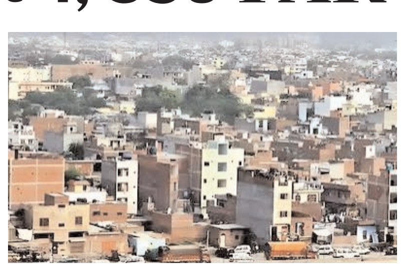

भी कायाकल्प तेजी से होगा।

### दिल्ली की अवैध कॉलिनियों को पक्का करने की तैयारी

नई दिल्लीः अनधिकृत कॉलोनियो में अब अलग अलग प्लॉटों पर बेतरतीब निर्माण के बजाय पूरे इलाके का एक साथ नियोजित पुनर्विकास हो सकेगा। मास्टर प्लान 2047 में ऐसी कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए एरिया-बेस्ड रीजेनरेशन का ढांचा प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत आसपास की कॉलोनियों या उनके हिस्सों को मिलाकर सड़क, खुले स्थान, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ एकीकृत विकास किया जा सकेगा। इससे इन अवैध कॉलोनियों का

### FAR 350 की अनुमति

इसके तहत FAR 350 की अनुमति होगी। यानी डिवेलपमेंट स्कीम के तहत अधिकतम एक ही जमीन पर मौजूदा व्यवस्था की तुलना में अधिक निर्मित क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा। इसके बदले डिवेलपर या निवासी समूह को सड़क, सार्वजनिक स्थान और जरूरी सामाजिक सुविधाओं के लिए जमीन और व्यवस्था करनी होगी। किसी कॉलोनी या कॉलोनियों के हिस्से के पुनर्विकास की योजना कम से कम 2,000 वर्गमीटर क्षेत्र में लाई जा सकेगी। इसे डिवेलपर, आरडब्ल्यूए या कॉलोनी का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकृत समूह प्रस्तावित कर सकेगा। आसपास की कॉलोनियों को एक साथ शामिल करने के साथ ग्रुप हाउसिंग के लिए अलग-अलग प्लॉटों को भी मिलाया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर कॉलोनी के बाहर की जमीन भी मालिक की सहमति से योजना में शामिल की जा सकेगी, लेकिन यह अतिरिक्त जमीन चिह्नित क्षेत्र के 25' से अधिक नहीं होगी। री-डिवेलपमेंट साइट की सीधी कनेक्टिविटी कम से कम 9 मीटर राइट ऑफ वे वाली सड़क से होनी जरूरी होगी। ऐसी सड़क नहीं होने पर जमीन मालिकों को आवश्यक जमीन उपलब्ध कराकर सड़क बनानी होगी। यह सड़क कम से कम 12 मीटर चौड़ी मौजूदा सड़क से जुड़नी होगी। री-डिवेलपमेंट में सिर्फ ज्यादा मकान या फ्लैट बनाने पर जोर नही होगा। स्कूल, हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हॉल, पुलिस पोस्ट और चाइल्ड केयर सेंटर जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भी जगह रखनी होगी। इससे घनी बस्तियों के पुनर्विकास के साथ सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित करने का रास्ता खुलेगा। योजना लागू करने वाले डिवेलपर और निवासी समूहो को इन्फ्रास्ट्रक्चर और रीजेनरेशन चार्ज देना होगा। यह राशि अलग रीजेनरेशन फंड में रखी जाएगी और उसी इलाके के इन्फ्रास्ट्रक्चर व पुनर्विकास पर खर्च होगी। MPD-2047 के मुताबिक दिल्ली की करीब 85' आबादी लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप से आती है।

## दो साल पहले बनी गर्लफ्रेंड, दोस्त उसके नजदीक आने लगा फिर पार्टी वाली बात से बदल गई लव ट्रायंगल की कहानी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**नागपुर।** लव ट्रायंगल में सनसनीखेज वारदात हो गई. यहां 27 साल के गौरव पंकज रागड़े नाम के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई. गौरव का एक लड़की से करीब दो साल से अफेयर था, जबकि उसका दोस्त गौरव राउत भी उसी लड़की के संपर्क में था. लड़की के साथ राउत की पार्टी की खबर मिलने के बाद गौरव उसके घर पहुंचा और विवाद के दौरान दोनों में हाथापाई हो गई. पुलिस ने हत्या के आरोप में गौरव राउत और अभिषेक वासनिक को गिरफ्तार किया है. नागपुर में लव ट्रायंगल के मामले में एक युवक की जान चली गई. मामला नरेंद्रनगर का है. यहां 27 साल के गौरव पंकज रागड़े की चाकू से हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, गौरव का करीब दो साल से एक युवती के साथ प्रेम संबंध था. इसी युवती के संपर्क में उसका दोस्त गौरव रामभाऊ राउत भी था. जब रागड़े को दोनों के साथ पार्टी करने की खबर मिली तो वह भड़क गया. फिर शुरू हुआ विवाद, पीछा और मारपीट का सिलसिला. आखिर में गौरव की चाकू लगने से मौत हो गई. मामले में पुलिस ने गौरव राउत और अभिषेक वासनिक को गिरफ्तार किया है. वारदात का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, गौरव रागड़े का एक युवती के साथ करीब दो साल से प्रेम संबंध था. वहीं उसका दोस्त गौरव राउत भी उसी युवती के संपर्क में था. राउत ने नरेंद्रनगर में युवती के साथ मिलकर क्लाउड किचन शुरू किया था और वह इलाके में किराए के मकान में रहता था. गुरुवार को रागड़े को पता चला कि युवती ने राउत के साथ पार्टी की है. ये बात उसे नागवार गुजरी. वह गुस्से में राउत के घर पहुंच गया. लव ट्रायंगल में काजल किन्नर की हत्या? अभी भी इंस्टा पर अपडेट हो रहे स्टेटस, प्रेमी की तलाश पुलिस के मुताबिक, रागड़े और उसके साथियों ने राउत के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद कथित तौर पर दरवाजे पर पत्थर फेंके गए और गाली-गलौज हुई. राउत और उसके दोस्त घबरा गए. वे घर के पिछले दरवाजे से निकलकर भागने लगे. लेकिन रागड़े ने उनका पीछा किया. नरेंद्रनगर के सुंदरवन नाले के पास दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. कहासुनी बढ़ी तो हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान अभिषेक वासनिक भी वहां पहुंच गया. पुलिस के मुताबिक, हाथापाई के दौरान राउत और वासनिक ने रागड़े के हाथ से चाकू छीन लिया. आरोप है कि इसके बाद उसी चाकू से रागड़े पर कई वार किए गए. हमले में रागड़े गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. इस वारदात से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. चाकू लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल रागड़े को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

## दिल्ली वालों के लिए आसान होगा सरकारी काम, 18 महीने के भीतर सरकार का प्रोजेक्ट हो जाएगा पूरा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

**नई दिल्ली।** श्रमिक कार्ड बनाना हो, बुजुर्ग पेशन का आवेदन करना हो या फिर जमीन की रजिस्ट्री। अब इन अलग-अलग विभागों के काम के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार अपने सभी विभागों के जिला कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए हर जिले में मिनी सचिवालय बनाने जा रही है। द्वारका सेक्टर-10 में बनने वाले पहले मिनी सचिवालय के लिए कंसलटेंट नियुक्त किया जा चुका है। यह काम 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले 25 महीने का था। सीएम रेखा गुप्ता इसके लिए 212 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। जोन और जिले की सीमा में उलझे प्रशासनिक ढांचे में सुधार को लेकर सरकार ने सबसे पहले एमसीडी जोन और जिले की सीमाओं को एक करके दिल्ली में 13 जिले बनाए है। अब इन जिला कार्यालयों (डीएम ऑफिस) में पुलिस को छोड़कर एमसीडी जोन, समाज कल्याण विभाग, पीडब्ल्यूडी, श्रम विभाग, जल बोर्ड, आरटीओ समेत सभी कार्यालय एक ही जगह स्थित होंगे, जिसे जिले का मिनी सचिवालय कहा जाएगा।ठु आधिकारिक सूत्रों की मानें तो पहले मिनी सचिवालय के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति हो चुकी 35,535 वर्ग मीटर में विकसित किया जाएगा। एक प्रस्तावित डिजाइन अंतिम चरण में है। इसमें वेटिंग रूम, हेल्पडेस्क, डिजिटल सुविधा और शिकायतों के लिए कियोस्क के साथ सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की योजना है। इससे आवेदक एक ही जगह आवेदन कर सकेगा। फिर उसे संबंधित विभाग में 212 करोड़ की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। इसे सामान्य सरकारी भवन के बजाय सस्टेनेबल और नेट-जीरो कॉम्प्लेक्स के तौर पर विकसित करने की योजना है। इसमें सोलर पावर सिस्टम, STP, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से जुड़ी व्यवस्था और मिस्ट स्प्रिंकलर जैसी सुविधाएं भी होगी। सोलर सिस्टम से इमारत की बिजली जरूरतों को पूरा किया जाएगा। यानी यहां सिर्फ प्रशासनिक सुविधा ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और पानी की खपत को कम करने वाला आधुनिक सरकारी परिसर तैयार करने की कोशिश होगी। इस परियोजना को पूरा होने में 18 महीने लगेंगे। हेल्पडेस्क पर कर्मी तैनात होंगे, जो आवेदन और प्रक्रिया को लेकर मदद भी करेंगे। मिनी सचिवालय में हेल्पडेस्क बनाया जाएगा, जहां कर्मचारी तैनात होंगे।

## डॉ. कुमुद मोहबे मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा 'चाचा पोहा मिल' में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित

**महानगर मेट्रो ब्यूरो**

**राजनांदगांव।** सावन के पावन अवसर पर सामाजिक सरोकार की दिशा में पहल करते हुए डॉ. कुमुद मोहबे मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा पनेका रोड, बसंतपुर स्थित प्रसिद्ध 'चाचा पोहा मिल' में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मिल में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को सुलभ व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। शिविर में मुख्य रूप से अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. चिन्मय डाकलिया (एम.डी., मेडिसिन) उपस्थित रहे, जिन्होंने शिविर में आए सभी हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दिया। इसके साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट भारती साहू द्वारा सभी का निःशुल्क बीएमआई परीक्षण किया गया तथा उन्हें संतुलित आहार, वजन नियंत्रण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मिल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की संपूर्ण शारीरिक जांच रू ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर की निःशुल्क जांचविशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण व परामर्श दैनिक दिनचर्या और पोषण सुधार के लिए वेलनेस गाइडेंस डॉ. कुमुद मोहबे मेमोरियल हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट मार्केटिंग मैनेजर दीपेश शेंडे ने शिविर की संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि कामकाजी वर्ग और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी बेहद आवश्यक है।

## दिग्विजय क्लब को शासन द्वारा खेल-कूद एवं मनोरंजन हेतु आंबटित जगह में व्यवसायिक निर्माण कैसे हो गया है

**महानगर मेट्रो ब्यूरो**

**राजनांदगांव।** पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज राजनांदगांव अजय यादव सर द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस राजनांदगांव द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति नाबालिग वाहन चालकों एवं स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा नाबालिग वाहन चालकों को वाहन नहीं चलाने की समझाइश दी गई। उन्हें बताया गया कि निर्धारित आयु पूर्ण किए बिना एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता है। नाबालिग अवस्था में वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है तथा दुर्घटना होने की स्थिति में गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। इसी क्रम में स्कूली विद्यार्थियों के बीच यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन नहीं चलाने, यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा सड़क पर सुरक्षित व्यवहार अपनाने के संबंध में जानकारी दी गई।विद्यार्थियों को समझाइश दी गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने माता-पिता, परिजनों एवं आसपास के लोगों को भी यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें। साथ ही, नाबालिग अवस्था में वाहन चलाने से होने वाले संभावित सड़क हादसों एवं उनके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। ??यातायात पुलिस द्वारा सभी पालकों से विशेष अपील की गई है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया अथवा अन्य वाहन चलाने के लिए न दें। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें निर्धारित आयु पूर्ण होने एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही वाहन चलाने दें।

## पूर्व शिकायत के बावजूद हत्या, पुलिस कार्रवाई और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर उठे सवाल

**महानगर मेट्रो ब्यूरो**

**राजनांदगांव।** देशमुख चौक के पास 16 अगस्त की रात पुराने विवाद को लेकर सत्यजीत देशमुख की घर में घुसकर हत्या किए जाने की घटना ने शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद जहां पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सत्यजीत देशमुख ने घटना से पहले चिखली थाना क्षेत्र में विवाद को लेकर शिकायत की थी। इसके बावजूद यदि समय रहते शिकायत को गंभीरता से लिया जाता और आवश्यक कार्रवाई की जाती तो क्या इस वारदात को टाला जा सकता था यह सवाल अब शहरवासियों के बीच उठ रहा है। शिकायतों पर पुलिस अधिकारियों की निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बावजूद कांग्रेस नेताओं की ओर से कानून-व्यवस्था को लेकर कोई मुखर प्रतिक्रिया सामने नहीं आने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस शहर अध्यक्ष जीतू मुदलियार की चुप्पी को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा है।

# युवाओं से संवाद बढ़ाएं और साइलो तोड़ें, पीएम मोदी ने दिए अधिकारियों को खास निर्देश

**-तीसरी उच्चस्तरीय सचिव बैठक में दीर्घकालिक सोच, एआई-मानव समन्वय, डेटा साझाकरण और पोर्ट-लेड विकास पर दिया जोर**

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडे की समीक्षा की। बैठक में बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी, सुरक्षा एवं विदेश मामलों तथा सुशासन से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर समन्वित कार्य संस्कृति विकसित करने और युवाओं के साथ सरकार का संवाद मजबूत बनाने का आह्वान किया।

बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बुधवार को हुई इस हाईलेबल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों को केवल मौजूदा चुनौतियों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ नीति निर्माण और क्रियान्वयन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में दूरदर्शी सोच अत्यंत आवश्यक है।

विभागों के बीच तालमेल की कमी को 'साइलो' की समस्या बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक ढांचे की नहीं, बल्कि कार्यशैली और सोच की चुनौती भी है। उन्होंने अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का स्वामित्व लेने तथा अपनापन और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ काम करने को कहा। कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय मंत्रालयों ने जिस प्रभावी समन्वय का प्रदर्शन किया था, उसे सरकार की स्थायी कार्य संस्कृति बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि एआई का अधिकतम उपयोग किया जाए, लेकिन मानवीय निर्णय क्षमता और विशेषज्ञता को उसके साथ जोड़े रखना आवश्यक है। इसी प्रकार उन्होंने डेटा को देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए विभागों के बीच डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और बेहतर साझाकरण की जरूरत रेखांकित की, ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके।

बैठक में विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और युवाओं के साथ सरकारी विभागों के संवाद को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की भागीदारी से नीति निर्माण में नवाचार और अपरंपरागत विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। रक्षा अनुसंधान, जहाज निर्माण, पोर्ट-लेड डेवलपमेंट तथा विनिर्माण एवं निर्यात उद्योगों की बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर भी उन्होंने मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अधिक अनौपचारिक संवाद स्थापित करने, विभिन्न कैडरों और विभागों के बीच मजबूत नेटवर्क विकसित करने तथा पूरी सरकार में टीम भावना और समन्वित दृष्टिकोण को और सुदृढ़ बनाने का आग्रह किया।

## सड़कों पर तड़तड़ाने लगी गोलियां और लहराने लगे हथियार, देहरादून में छात्र गुटों का खूनी तांडव

देहरादून (एजेंसी)। शिक्षा और शांति के लिए विख्यात देहरादून की पहचान को गुरुवार को छात्र गुटों के खूनी संघर्ष ने झकझोर दिया। पलनगर इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर करीब तीन किलोमीटर तक फैल गया, जिसमें पिस्टल और लाठी-डंडों का जमकर इस्तेमाल हुआ। दिनदहाड़े हुए इस तांडव में छह राउंड फायरिंग हुई और एक युवक घायल हो गया, जिससे शांत शहर में दहशत फैल गई। यह घटना देहरादून के बदलते मिजाज की एक खतरनाक तस्वीर पेश करती है, जिसे अब तक सुकून और शिक्षा के केंद्र के तौर पर जाना जाता रहा है। सबसे गंभीर बात यह रही कि यह हिंसा किसी सुनसान कोने में नहीं, बल्कि शहर की मुख्य सड़कों पर हुई, जहाँ एक पक्ष कार में तो दूसरा बाइकों से पीछा कर रहा था। रास्ते में चार पुलिस पिकेट होने के बावजूद यह विवाद एक स्थान पर नहीं रुका, बल्कि शहर के भीतर दौड़ता हुआ दूसरी जगह पहुंचा। यह सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं है, यह उस गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है जब छात्र गुटों की रंजिश कैंपस की सीमाओं को लांघकर सड़क पर उतर आती है और विवाद का जवाब तर्क से नहीं, बल्कि हथियारों से दिया जाता है। देहरादून में छात्र गुटों के बीच हिंसा का यह पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले हुए दिव्यांशु जटराणा हत्याकांड ने भी छात्र विवादों के खूनी अंजाम की भयावहता दिखाई थी। उस घटना के बाद छात्र गतिविधियों पर निगरानी और संस्थानों के साथ समन्वय की बातें कही गईं थीं, लेकिन गुरुवार की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का असर सिर्फ घटना के बाद ही दिखाई देता है। हजारों बाहरी छात्र देहरादून में किराये के मकानों और छात्रावासों में रहते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों पर पुलिस सत्यापन और निगरानी का तंत्र कमजोर दिखता है।

## जयपुर में भाजपा और सीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव, रांका को ग्रामीणों ने खदेड़ा

**-सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे थे सीजेपी कार्यकर्ता**

**जयपुर, एजेंसी।**
राजस्थान की राजधानी जयपुर के गांव रामपुरा-कंवरपुरा में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर भाजपा समर्थक ग्रामीणों और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं के बीच खासा विवाद हो गया। दरअसल सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ एक सरकारी स्कूल की असल स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने उनके स्कूल में प्रवेश का विरोध कर दिया। कहा-सुनी हुई और देखते ही देखते विवाद हाथापाई तक पहुंच गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्रामीणों के विरोध के बाद रांका और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को मौके से लौटना पड़ा। रिपोर्टों में वाहनों के शीशे टूटने और पथराव की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, घटना को लेकर दोनों पक्षों के आरोप अलग-अलग हैं। रांका ने आरोप लगाया कि उनके साथियों के साथ मारपीट भाजपा समर्थकों ने की, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वे गांव के सरकारी स्कूल में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते।

मौजूदा विवाद की जड़ स्कूल भवन की खराब हालत बताई जा रही है। सीजेपी का दावा है कि बच्चे जर्जर भवन के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन के लिए सरकारी बजट स्वीकृत हो चुका है और वे स्वयं इसके निर्माण को लेकर प्रयास कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर भी नजर है।

## डिग्गीपुरी में कल चढ़ेगा शाही केसरिया निशान, लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद

**महानगर मेट्रो ब्यूरो/पीयूष गौत्तम**

**टोंक/डिग्गी।** छोटी काशी डिग्गीपुरी में श्री कल्याणजी महाराज की 61वीं लक्खी पदयात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर से रवाना हुई विशाल पदयात्रा 22 अगस्त को डिग्गी पहुंचेगी। दिन में विश्राम के बाद शाम 5 बजे रोडवेज बस स्टैंड से शाही केसरिया निशान ध्वज के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा संघ के अध्यक्ष एवं संचालक श्रीजी शर्मा लोहे वालों ने बताया कि मुख्य अतिथि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, आध्यात्मिक कथा व्यास कृष्णेश्वरी देवी श्रीधाम वृंदावन, ठाकुर रामप्रताप सिंह, निर्मला चौधरी, समाजसेवी मनोज टाक, प्रिया मोदी सहित अन्य गणमान्य अतिथि शाही निशान ध्वज को रवाना करेंगे। श्रद्धालु नाचते-गाते मुख्य मार्ग से श्री कल्याणजी महाराज के निज मंदिर पहुंचेंगे, जहां शाही केसरिया निशान ध्वज चढ़ाया जाएगा। इसके बाद गंगोत्री से लाए गए गंगाजल से भगवान श्री कल्याणजी महाराज का अभिषेक किया जाएगा। लक्खी पदयात्रा में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। आस्था ऐसी कि श्रद्धालु तेज धूप, बारिश, कीचड़ और नंगे पांव पड़ने वाले छालों की भी परवाह किए बिना श्रीजी के दरबार की ओर बढ़ते हैं मेले को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को पुख्ता किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एसपी रोशन मीणा, एएसपी पुष्पेंद्र सिंह, डीएसपी आशीष प्रजापत, एसडीएम मालपुरा, नायब तहसीलदार हंसराज चौधरी, नगर पालिका ईओ रामकेश जाट और डिग्गी थानाधिकारी गोपाल चौधरी व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। हीं नगर पालिका प्रशासन कंट्रोल रूम पर अतिथियों का स्वागत करेगा, जबकि चौपड़ चौराहे पर रामदास ट्रस्ट की ओर से स्वागत किया जाएगा।

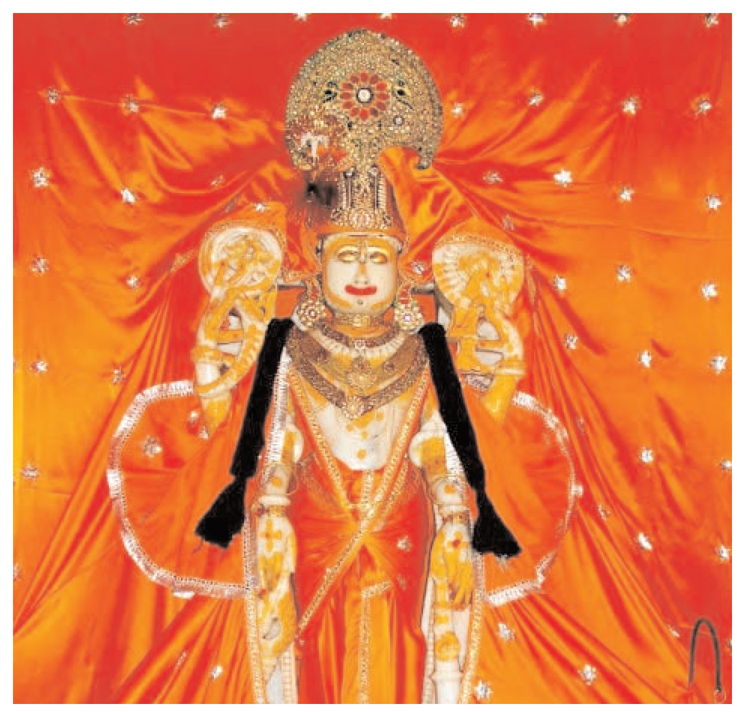

## पुलिस महानिरीक्षक द्वारा थाना मोहला, थाना खड़गांव, पुलिस कैंप परवींडीह एवं ITBP 40वीं बटालियन कैंप का किया निरीक्षण

**महानगर मेट्रो ब्यूरो**

**राजनांदगांव।** पुलिस महानिरीक्षक, रेंज राजनांदगांव अजय कुमार यादव (भा.पु.से.) द्वारा जिला मोहला-मानपुर अंबागढ चौकी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मोहला में जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों, प्रशिक्षु उप निरीक्षकों एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में जिले में लंबित अपराध, मर्ग, साइबर अपराध, शिकायतों एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए त्वरित निराकरण, विवेचना की गुणवत्ता में सुधार एवं अपराध नियंत्रण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही साइबर अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी निराकरण के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देते हुए साइबर फ्रॉड के मामलों में त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों को तत्काल सहायता तथा संबंधित बैंकों एवं संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर फ्रॉड की राशि को होल्ड/फ्रीज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात पुलिस महानिरीक्षक द्वारा थाना मोहला एवं थाना खड़गांव का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना परिसर, कार्यालयीन व्यवस्था, अभिलेखों एवं विभिन्न शाखाओं के कार्यों का जायजा लिया गया तथा थाना प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं बेहतर पुलिसिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस कैंप परवींडीह का निरीक्षण किया गया। कैंप में तैनात पुलिस जवानों से मुलाकात कर उनकी ड्यूटी एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली गई तथा विषम परिस्थितियों में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे जवानों का उत्साह एवं मनोबल बढ़ाया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्राथमिक शाला परवींडीह पहुंचकर विद्यालय के बच्चों से मुलाकात एवं संवाद किया गया। उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई एवं विद्यालय संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली तथा बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इसके पश्चात पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा ITBP 40वीं बटालियन कैंप पहुंचकर वहां तैनात जवानों से मुलाकात की गई। उन्होंने जवानों से ड्यूटी एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर उनका हालचाल जाना तथा कठिन एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की समस्त शाखाओं का निरीक्षण कर कार्यालयीन कार्यप्रणाली एवं अभिलेखों का जायजा लिया गया तथा विभिन्न शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की गई। इसके पश्चात पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित परिसर का संदेश दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह (भा.पु.से.), मुख्यालय उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पवार, रक्षित निरीक्षक भुवनेश्वर कश्यप सहित जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। ुलिस महानिरीक्षक के आकस्मिक निरीक्षण से जिले के पुलिस अधिकारियों एवं जवानों में उत्साह का संचार हुआ तथा बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा के प्रति और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने का संकल्प मजबूत हुआ।

# पानी समुद्र में बहे और किसान बूंद-बूंद को तरसे ये ठीक नहीं : शाह

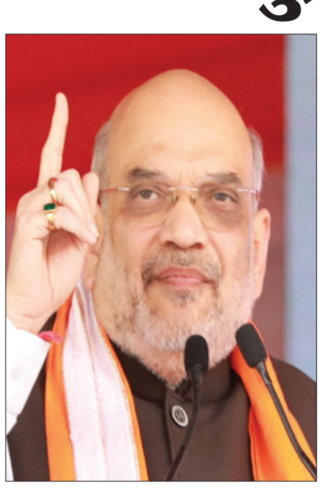

**- दो राज्यों के जल विवाद पर अमित शाह ने दी प्रतिक्रिया**

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतरराज्यीय जल विवादों को बातचीत से सुलझाने के सुझाव को दक्षिण भारत के राज्यों ने समर्थन दिया है। गुरुवार को दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा, जहाँ लोकसभा सीटों के परिसीमन पर भी गहन चर्चा हुई। अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अपने राज्य के हितों की रक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर पानी की कमी के कारण किसी राज्य को वर्षों तक वंचित रहना पड़े और पानी समुद्र में बहता रहे, तो यह किसी के हित में नहीं है।

शाह ने भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी से बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र से कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे कई जलमार्ग भी विकसित हो सकते हैं। उन्होंने उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे के आठ में से पांच ब्रिटिश-पूर्व विवादों के सफल समाधान का उदाहरण दिया, जहां पांच महीने पहले अंतिम समझौता हुआ था।

हालांकि, बैठक में लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा विवाद का विषय बन गया। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान की आशंका जताई। कर्नाटक और तमिलनाडु ने मांग की कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें अगले 25 वर्षों तक बनी रहें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने परिषद से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 1971 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाए रखने और महिलाओं के आरक्षण को मौजूदा सीटों के भीतर ही लागू करने की मांग की।

अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी चिंताओं के साथ सामने आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु को मेकेदातु बांध परियोजना से उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दिया, हालांकि तमिलनाडु के मंत्री ने स्पष्ट किया कि कावेरी जल विवाद पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम के रास्ते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और अमरावती-बेंगलुरु-चेन्नई ट्रांजिट नेटवर्क का प्रस्ताव रखा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे के मामलों को गृह मंत्रालय के साथ सुलझाने पर सहमति जताई। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहकारी संघवाद पर जोर दिया। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमरका ने कृष्णा नदी के पानी पर राज्य के अधिकारों की सुरक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहयोग मांगा, जबकि पुडुचेरी ने सालभर पानी की उपलब्धता के लिए केंद्र और तमिलनाडु से सहयोग की अपील की।

## वैश्विक अस्थिरता और महंगाई चिंताओं के बीच सोना-चांदी फिर चमके

**सोना 1,205 रुपए मजबूत, चांदी में 1,745 रुपए की तेजी**

**नई दिल्ली।**

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती महंगाई की चिंताओं के बीच शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। निवेशक मुद्रा और बॉन्ड बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के कारण सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पर व्यापक प्रतिबंधों की आशंका से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई की चिंताएं बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही, केंद्रीय बैंकों, विशेषकर चीन की लगातार खरीदारी ने भी बहुमूल्य धातुओं को मजबूत समर्थन प्रदान किया है। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर भी बहुमूल्य धातुओं की चमक बरकरार रही। खबर लिखे जाने के समय एमसीएक्स पर सोने का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 256 रुपये की तेजी के साथ 1,59,681 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,367 रुपये की बढ़त के साथ 2,44,610 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर था। सुबह के सत्र में सोने का बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट 1,205 रुपये की तेजी के साथ 1,60,630 रुपये पर और चांदी का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,745 रुपये की बढ़त के साथ 2,44,988 रुपये पर खुला था। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर भी सोना और चांदी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 4,592.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर था, जो पिछले बंद भाव 4,571.40 डॉलर से 21.10 डॉलर की बढ़त दर्शाता है। इसी तरह, चांदी भी 0.96 डॉलर की तेजी के साथ 69.06 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी, जबकि इसका पिछला बंद भाव 68.10 डॉलर था। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाएं, भू-राजनीतिक तनाव और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही ढीली मौद्रिक नीतियां सोने-चांदी को आगे भी समर्थन देती रहेंगी। निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब पारंपरिक वित्तीय बाजार अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने भंडार में सोने की खरीदारी जारी रखना भी कीमतों को उच्च स्तर पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## महंगी चीनी से कड़वा हुआ त्योहारों का स्वाद, बंगाल में कीमतें 70 रुपए के पार

**केंद्र ने 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात की दी अनुमति; कारोबारी बोले- आयात नाकाफी**

**कोलकाता**

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सहित आगामी त्योहारी सीज़न से ठीक पहले चीनी की कीमतें आसमान छू गई हैं। खुदरा बाजार में चीनी 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जिससे उपभोक्ताओं का बजट बिगड़ गया है। पिछले एक महीने में ही यह 20 रुपये महंगी हुई है। व्यापारियों के अनुसार बीते कुछ दिनों में ही कीमतों में अचानक 10 प्रतिशत का उछाल आया है। चीनी से बने गुड़, बताशा और नकुलदाना जैसे उत्पादों के दाम भी इसी तरह बढ़े हैं। कन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन (सीडब्ल्यूबीटीए) के एक अ धिकारी ने चीनी मिलों पर नियंत्रण न होने और एथनॉल उत्पादन के लिए चीनी के बढ़ते उपयोग को इसका मुख्य कारण बताया है। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक दशक बाद 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात करने की अनुमति दी है। साथ ही, थोक खरीदारों पर भी भंडार सीमा (15 दिन की खपत) लगाई है। हालांकि, कारोबारियों का कहना है कि आयात की यह मात्रा देश की केवल दो सप्ताह की मांग को पूरा करेगी और फिलहाल इसका खुदरा बाजार पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। उनका मानना है कि अधिक हस्तक्षेप की जरूरत है। वहीं पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने चीनी की कीमत वृद्धि के लिए एथनॉल मिश्रण को नहीं बल्कि जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, एक चीनी मिल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मिलों में पेराई अप्रैल में ही खत्म हो चुकी है और अब वे केवल अपने मौजूदा भंडार से चीनी जारी कर रही हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकतीं।

# शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद

**मुंबई।**

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को हल्की बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच ही उतार-चढ़ा हावी रहने से बाजार पर अंकुश लगा रहा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण से भी बाजार पर दबाव आया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से भी घरेलू बाजार पर दबाव बना। दिनभर के कारोबार के बाद दोनों प्रमुख सूचकांक सपाट बंद हुए।

इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स केवल 3.11 अंक की हल्की बढ़त के साथ ही 77,540.83 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी केवल 20.15 अंक बढ़कर 24,252.00 के स्तर पर बंद हुआ। आज बड़े शेयरों में कमजोरी रही पर छोटे और मध्यम शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.1 फीसदी की बढ़त रही। वहीं निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.69 फीसदी बढ़कर बंद हुआ।

इससे साफ है कि खुदरा निवेशकों का भरोसा छोटे शेयरों में बना हुआ है।

आज के कारोबार में धातु और निजी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा चमक रही। इन दोनों सेक्टरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया जबकि , एफएमसीजी, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा और इन्होंने बाजार के

मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया। आज सबसे अधिक गिरावट मारुति सुजुकी और इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में रही।

वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार हल्की बढ़त के साथ खुला। सुबह सेंसेक्स 82.30 अंक बढ़कर 77,620.02 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी भी 18.65 अंक की बढ़त के साथ 24,250.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। ब्रॉडर मार्केट में मिलाजुला रुख दिखा।

निफ्टी मिडकैप में 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 0.44 फीसदी की अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।

## अपस्टॉक्स आईपीओ की तैयारी में, 40 करोड़ डॉलर जुटाने का लक्ष्य

**निवेश बैंकों से प्रारंभिक चर्चा शुरू, 2 करोड़ ग्राहक का आंकड़ा पार कर कंपनी का विस्तार पर जोर**

**मुंबई।**

प्रमुख निवेश मंच अपस्टॉक्स ने अपने महत्वाकांक्षी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए निवेश बैंकों के साथ शुरुआती चर्चा शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 35-40 करोड़ डॉलर (लगभग 3,351-3,829 करोड़ रुपये) जुटाने की योजना बना रही है, ऐसे समय में जब इसने अपने केवाईसी पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित आईपीओ में नए शेयर जारी करने के साथ ही मौजूदा निवेशकों की ओर से बिक्री पेशकश (ओएफएस) भी शामिल होगी। अपस्टॉक्स ने अब तक छह वित्त पोषण दौरों के माध्यम से करीब 22 करोड़ डॉलर जुटाए हैं और 2021 में 3.5 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था। इस बीच कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि उसके केवाईसी पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। अपस्टॉक्स का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में अपने उपयोगकर्ता आधार को बढ़ाकर 10 करोड़ तक पहुंचाना है। कंपनी के एक व रिष्ठ अ धिकारी ने इस उपलब्धि पर कहा कि उनका ध्यान ग्राहकों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और वित्तीय बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित है। यह आईपीओ कंपनी को अपने विस्तार योजनाओं को गति देने में मदद करेगा।

## पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल फिर महंगा

**इस्लामाबाद।**

पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ा है। सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद नए दाम 21 अगस्त से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल 337.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीजल 364.70 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार पेट्रोल पर 114 रुपये और डीजल पर 100 रुपये प्रति लीटर तक का भारी टैक्स और ड्यूटी वसूल रही है, जो ईंधन की उच्च कीमतों का एक प्रमुख कारण है। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये नई कीमतें 21 अगस्त से प्रभावी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव के चलते, अब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी दैनिक आधार पर ईंधन की कीमतें तय करेगी। तुलनात्मक रूप से, भारतीय मुद्रा में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत लगभग 114.85 रुपये प्रति लीटर बैठती है, जो भारत के बड़े शहरों, जैसे दिल्ली (102.12 रुपये) और चंडीगढ़ (101.54 रुपये), की तुलना में काफी अधिक है, जिससे पाकिस्तानी उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ रहा है।

# पीएनबी की चेतावनी, निष्क्रिय खाते बंद होने का खतरा, तुरंत करें केवायसी अपडेट

**बैंक ने ग्राहकों को सितंबर तक केवायसी अपडेट करने या लेनदेन करने की चेतावनी दी**

**मुंबई।**

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने लाखों ग्राहकों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। बैंक ने ऐसे निष्क्रिय खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है जिनमें लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनका बैलेंस शून्य है। ग्राहकों को सितंबर तक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है, ताकि उनके खाते बंद होने से बच सकें। पीएनबी के अनुसार, ऐसे बैंक खाते जिनमें पिछले तीन साल से कोई लेनदेन दर्ज नहीं हुआ है और खाते में कोई राशि भी नहीं है, उन्हें बंद किया जा सकता है। बैंक ने यह कदम खातों के गलत इस्तेमाल और उनसे जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए उठाया है। पीएनबी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया माध्यमों पर भी यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें खाताधारकों को सचेत किया गया है। निष्क्रिय खाताधारक अपने खाते को बंद होने से बचाने के लिए सितंबर तक संबंधित बैंक शाखा में अपने केवायसी दस्तावेज जमा कराकर इसे दोबारा सक्रिय करवा सकते हैं। केवायसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राहक बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे।

बैंक ने यह भी सलाह दी है कि कोई भी ग्राहक अपना खाता बंद करने का निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह पेंशन, सब्सिडी, लोन, बीमा या किसी अन्य महत्वपूर्ण भुगतान से जुड़ा न हो। पीएनबी ने ग्राहकों से समय-समय पर अपने खाते में लेनदेन करने और अपनी केवायसी जानकारी अपडेट रखने का आग्रह किया है।

किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए ग्राहक पीएनबी के आधिकारिक हेल्पलाइन माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं।

# भारतीय प्राइवेट क्रेडिट बाजार गुलजार, रियल एस्टेट सबसे आगे

**अगले 1–2 वर्षों में बाजार की मजबूती बरकरार रहने का अनुमान**

**नई दिल्ली।**

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार अगले एक से दो वर्षों में भी मजबूत बना रह सकता है। एच1 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर ने इसमें अहम भूमिका निभाई, जबकि घरेलू निवेशकों ने वैश्विक फंड्स को पीछे छोड़ दिया। इस अवधि में करीब 3.5 अरब डॉलर का निवेश हुआ। एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2026 की पहली छमाही (एच1 2026) में भारत के प्राइवेट क्रेडिट बाजार में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू आर्थिक आधार और बेहतर बैंकिंग सेक्टर से प्रेरित था। इस दौरान कुल निवेश लगभग 3.5 अरब डॉलर रहा, जिसमें घरेलू फंड्स का दबदबा रहा। कुल डील वैल्यू में घरेलू खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 74 फीसदी रही, जबकि डील की संख्या में यह आंकड़ा 79 फीसदी रहा। सेक्टरवार विश्लेषण में रियल एस्टेट कुल प्राइवेट क्रेडिट डील वैल्यू के 35 फीसदी हिस्से के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद हेल्थकेयर (13 फीसदी) का स्थान रहा। एक महत्वपूर्ण बदलाव फूड एंड बेवरेज (एफएंडबी) सेक्टर में देखा गया, जिसकी हिस्सेदारी एच 2 2025 में मात्र 1 फीसदी से बढ़कर एच1 2026 में 12 फीसदी पर पहुंच गई। यह तेजी भारतीय बैंकिंग सेक्टर की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति से भी प्रेरित है। मार्च 2026 तक बैंकों का कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेश्यो 17.7 फीसदी और सीईटी1 अनुपात 15.3 फीसदी रहा। वित्तीय वर्ष 2026 में सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.8 फीसदी और शुद्ध एनपीए 0.4 फीसदी रह गया, जो एसेट क्वालिटी में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। सर्वे में शामिल 60 फीसदी प्रतिभागियों ने अगले 1-2 वर्षों के लिए भारतीय प्राइवेट क्रेडिट बाजार को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। हालांकि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा एक चिंता का विषय बनी हुई है। रियल एस्टेट, हालांकि सबसे सक्रिय सेक्टर है, इसे डिफॉल्ट के लिहाज से सबसे जोखिम भरा भी माना गया है। स्ट्रेस, कैपेक्स और विलय-अधिग्रहण फाइनेंसिंग इस बाजार की प्रमुख मांग बने हुए हैं।

## रुपया बढ़त के साथ बंद

**मुंबई।**

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया 5 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.69 पर बंद हुआ। आज सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया नौ पैसे बढ़क 95.65 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की चुनौती से भारत के लिए कमजोर डॉलर का असर कम हो रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.69 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में 95.65 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से नौ पैसे की बढ़त है। वहीं रुपया गुरुवार को शुरुआती बढ़त गंवाकर एक पैसे की गिरावट के साथ 95.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15 फीसदी टूटकर 98.74 पर आ गया।

## टाटा मोटर्स की गाड़ियां होंगी महंगी, 1 सितंबर से 25,000 तक बढ़ेंगे दाम

**कच्चे माल की बढ़ती लागत और वैश्विक चुनौतियों के कारण कंपनी ने लिया फैसला**

**नई दिल्ली।**

अगर आप टाटा मोटर्स की कोई नई कार या एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। कंपनी ने अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 1 सितंबर 2024 से 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यह कदम कच्चे माल की लगातार बढ़ती लागत और वैश्विक बाजार में बनी अनिश्चितता के चलते उठाया गया है, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि यह मूल्य वृद्धि उसके पूरे यात्री वाहन पोर्टफोलियो पर लागू होगी। हालांकि, किस मॉडल और वैरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका खुलासा कंपनी ने नहीं किया है। अधिकतम बढ़ोतरी 25,000 रुपये तक होगी। कंपनी ने बताया कि कच्चे माल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के कारण भी कंपनियों के खर्च पर भारी दबाव बना हुआ है। कंपनी अब तक बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही थी, लेकिन लगातार बढ़ते खर्चों के कारण अब इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना अनिवार्य हो गया है। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में रुकावट, महंगा कच्चा माल और बढ़ती परिचालन लागत वाहन कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर भी ऊर्जा और आपूर्ति से जुड़ी लागतों पर पड़ रहा है। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन पोर्टफोलियो में टियागो, टिगोर, पंच, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर और सफारी जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे खरीदारी से पहले अपने नजदीकी डीलर से नई कीमतों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। यह 2024 में टाटा मोटर्स की ओर से की जाने वाली तीसरी मूल्य वृद्धि होगी। इससे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल से पेट्रोल-डीजल वाले यात्री वाहनों की कीमतों में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 1 जुलाई से कंपनी ने अपने पूरे यात्री वाहन पोर्टफोलियो के दाम 1.5 फीसदी बढ़ाए थे। अब 1 सितंबर से एक बार फिर कीमतों में 25,000 रुपये तक की वृद्धि होने जा रही है, जो ग्राहकों के लिए चुनौती पेश कर सकती है।

## सेबी की बड़ी कार्रवाई, दो कंपनियों पर लगा प्रतिबंध

**गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे जब्त करने का निर्देश**

**मुंबई**

बाजार नियामक सेबी ने सेंसेक्स डेरिवेटिव्स अनुबंधों की साप्ताहिक अंतिम तिथि पर हुई कीमतों की असामान्य हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। एक विस्तृत जांच के बाद, सेबी ने जेपी मॉर्गन की मॉरीशस स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) कॉप्टॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग को बाजार में कीमतों की कृत्रिम छेड़छाड़ का दोषी पाया है। नियामक ने इन कंपनियों को शेयर बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उनसे गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को जब्त करने का आदेश दिया है। यह मामला 13 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) के दौरान सेंसेक्स में कुछ ही सेकंड में हुई कीमतों की अचानक उछाल से जुड़ा है। सेबी की अंतरिम जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस उछाल के पीछे कॉप्टॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट का हाथ था। कंपनी ने लगभग 98 रुपए करोड़ मूल्य के खरीद ऑर्डर दिए, जिनकी कीमत संदर्भ मूल्य से अधिकतम 3 फीसदी अधिक थी और कीमतों में बदलाव के साथ ही एक-तिहाई ऑर्डर रद्द कर दिए। सेबी का आरोप है कि कॉप्टॉल ने सेंसेक्स के सांकेतिक समान मूल्य (आईईपी) को बढ़ाकर बंद भाव में हेरफेर करने की कोशिश की, ताकि अपनी सिंथेटिक लॉन्ग एसेट पोजीशन से मुनाफा कमाया जा सके।

उसी दिन, मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग ने सेंसेक्स की आठ कंपनियों के शेयरों में संदर्भ मूल्य से लगभग 2.5 फीसदी कम पर बड़ी संख्या में बिक्री ऑर्डर दिए, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया। इससे सेंसेक्स का आईईपी चार से पांच मिनट तक नीचे आ गया, जिससे कंपनी को वायदा पोजीशन से लाभ मिलने की संभावना थी। नियामक ने स्पष्ट किया है कि दोनों संस्थाओं ने आपस में मिलकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से हेरफेर किया। सेबी के चेयरमैन ने बाजार में हेरफेर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन घटनाओं ने बाजार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ाई है और वे सीएएस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

## बंगाल का औद्योगिक सपना, दशकों का सफर और अनसुलझी तस्वीर

**कोलकाता की चमकीली शहरी छवि, औद्योगिक मोर्चे पर स्थायी बदलाव की चुनौती**

**नई दिल्ली।**

पश्चिम बंगाल ने पिछले तीन दशकों में अपनी औद्योगिक और आर्थिक छवि को बदलने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। 1994 में वाम मोर्चा सरकार द्वारा निजी निवेश के द्वार खोलने से लेकर आज तृणमूल कांग्रेस के आईटी हब के प्रयासों तक, राज्य ने निवेश आकर्षित करने और अपनी उग्र मजदूर संघों वाली छवि से उबरने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि, चमकदार शहरी विकास के बावजूद, राज्य की औद्योगिक तस्वीर अभी भी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। सितंबर 1994 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नेतृत्व में, निजी निवेश के लिए द्वार खोलते हुए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। लाइसेंस राज के ढहने के बाद, राज्य ने चुनिंदा क्षेत्रों में नई तकनीक और निवेश का स्वागत किया। हालांकि, अप्रैल 2000 में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन अनेक समझौता ज्ञापन (एमओयू) ठोस निवेश या रोजगार में तब्दील नहीं हो पाए। तब तक राज्य की पहचान उग्र मजदूर संघों और औद्योगिक अशांति वाले प्रदेश के रूप में स्थापित हो चुकी थी, जिससे निवेशक दूर भाग रहे थे। नवंबर 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। उनके अभी करो वाले दृष्टिकोण ने औद्योगीकरण को गति दी। कोलकाता में साल्ट लेक और राजारहाट जैसे क्षेत्रों में आईटी कंपनियों के परिसर, भव्य शॉपिंग मॉल और रेस्तरां तेजी से विकसित हुए। इन आधुनिक केंद्रों ने शहर के पुराने औपनिवेशिक स्वरूप से हटकर एक नई व्यावसायिक पहचान गढ़ी, जो कांच और इस्पात के टावरों से चमक उठी। पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में भी यह गति जारी रही, जिसमें बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब जैसी परियोजनाओं ने आईटी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। हालांकि, इनमें से अधिकांश परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं। नए दफ्तरों और फ्लाईओवर ने भले ही कोलकाता की भौतिक तस्वीर बदल दी हो, लेकिन राज्य की औद्योगिक छवि में आया बदलाव अस्थायी प्रतीत होता है।

# निजी क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियों में मामूली सुधार, सर्विस सेक्टर ने संभाली कमान

**अगस्त में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 54.6 हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई सुस्ती**

**नई दिल्ली।**

भारत के निजी क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियों में अगस्त में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। जुलाई में चार साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद यह सुधार सेवा क्षेत्र की मजबूत रफ्तार से संभव हुआ, जिसने विनिर्माण क्षेत्र की धीमी पड़ती गतिविधियों को काफी हद तक संतुलित किया। एक सर्वे के मुताबिक अगस्त में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 54.6 पर पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह 54.3 था। जारी सर्वे के अनुसार अगस्त में निजी क्षेत्र की गतिविधियों में विस्तार लगातार 61वें महीने बना रहा, हालांकि कंपोजिट पीएमआई मार्च 2022 के बाद दूसरा सबसे कमजोर आंकड़ा रहा। इस दौरान सेवा क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियां जुलाई के 53.3 से बढ़कर 54.5 हो गईं, जो वृद्धि को प्रमुख सहारा मिला। इसके विपरीत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ और धीमी पड़ गई। पीएमआई जुलाई के 53.5 से घटकर अगस्त में 52.9 रह गया। एक अर्थशास्त्री ने बताया कि विनिर्माण ग्रोथ पांच साल में सबसे धीमी रही। नए ऑर्डर में सुधार हुआ, लेकिन उसकी गति उम्मीद से कम रही।

कंपनियों की इनपुट लागत सात महीनों की सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी, फिर भी उन्होंने ग्राहकों से वसूले जाने वाले अंतिम बिक्री मूल्य में तेजी से बढ़ोतरी की। अगस्त में कुल रोजगार सृजन में सुधार हुआ, जिसका मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती थी। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ढाई साल में पहली बार कर्मचारियों की संख्या में कमी दर्ज की गई। कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े जुलाई की तुलना में कुछ राहत देते हैं, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र की लगातार कमजोर होती ग्रोथ और समग्र पीएमआई का अपेक्षाकृत निचला स्तर आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार पर दबाव बने रहने का संकेत देता है।

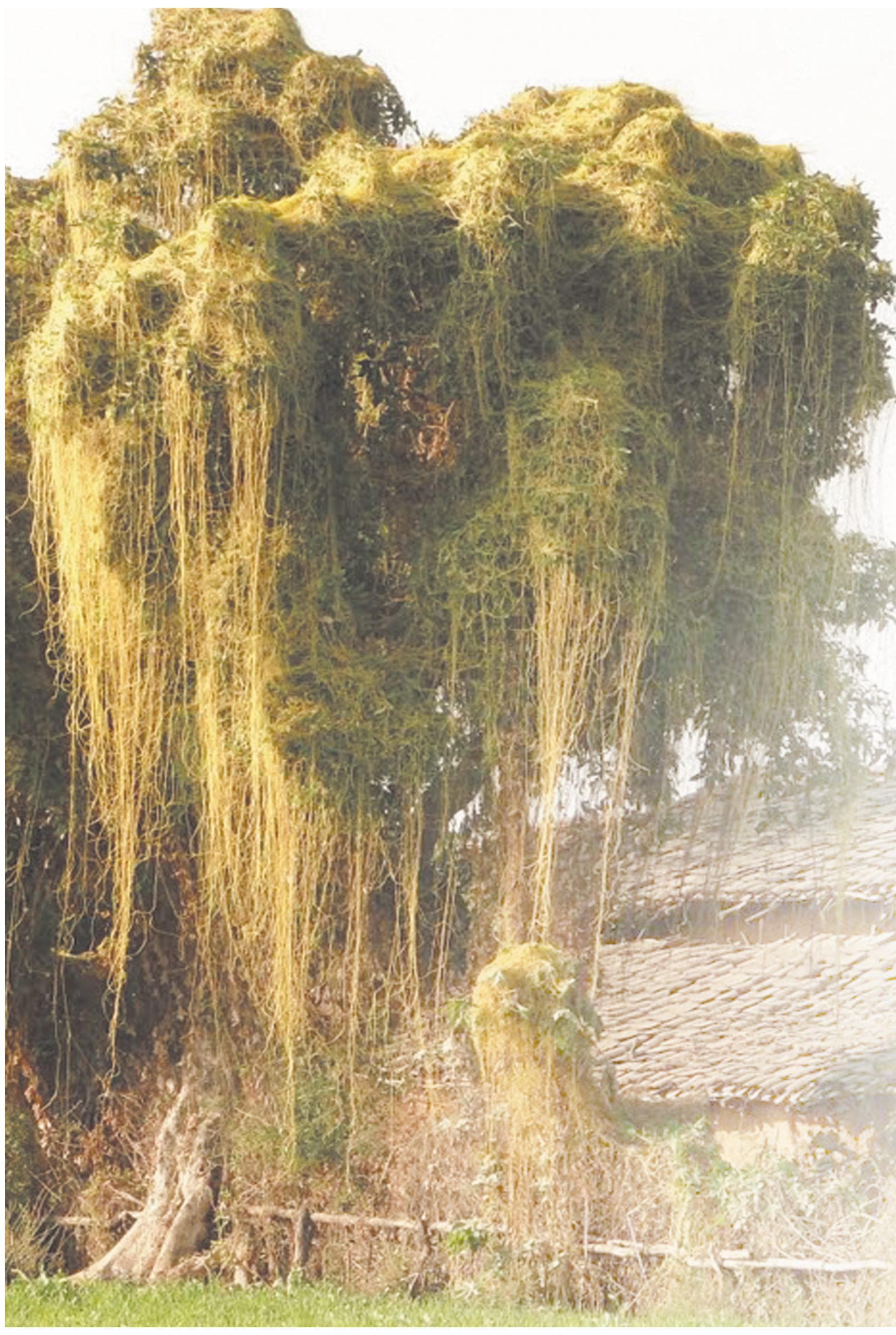

मोटे अनाजों में प्रमुख

# बाजरा

## भूमि का चुनाव

बाजरे की असिंचित फसल उन मिट्टियों में अच्छी उपज देती है, जिनकी जलधारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। रेतीली मटियार दोमट और मटियार दोमट भूमि में बाजरा की भरपूर पैदावार होती है।

## भूमि की तैयारी

बाजरा वर्षा आधारित फसल है। ऐसी फसल के लिए गर्मियों की जुताई अच्छी पाई गई है। इससे खरपतवारों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। वर्षा के शुरू होने पर हल या बखर चलाकर खेत को भुरभुरा बनायें तथा खरपतवार रहित करें।

## उन्नत किस्में

अ. संकर किस्में - आईसीएमएच-356, जवाहर बाजरा हायब्रिड-1, जवाहर बाजरा हायब्रिड-2, हरित बटल रोग निरोधक

ब. परागित किस्में - जवाहर बाजरा किस्म-2, जवाहर बाजरा किस्म-3, जवाहर बाजरा किस्म-4, राज-171

## बुआई

बाजरा की बुआई के लिए जुलाई का पहला पखवाड़ा ही उत्तम है। इस समय पर लगाए गए बाजरा पर रोगों का प्रकोप कम होता है तथा फूल आते समय सामान्य वर्षा होने पर प्रायः भूमि

में नमी का अभाव नहीं होता है।

## बीज की मात्रा और पौधों का घनत्व

बाजरा की संकर किस्मों की कतारों के बीच 45 सेमी की दूरी रखना जरूरी है, जिसमें पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेमी होना चाहिए। बीज 1 से 2.5 सेमी की गहराई पर बोना चाहिए। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर 1.8 लाख से 2 लाख तक उचित पौध संख्या के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त रहती है। बुआई के पूर्व बीजोपचार जरुरी है बीज का उपचार एप्रान-35 एसडी की 6 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, जिससे डाउनी मिल्डयू रोग के प्रारंभिक प्रकोप से बचा जा सके।

## उर्वरक की मात्रा एवं देने का तरीका

बुआई के पूर्व 87 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम और 33 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए।

## पौधों की छटाई

बाजरा के पौधें के पूर्ण विकास के लिए उपयुक्त स्थान मिलना आवश्यक है। अतः घने पौधों की छंटाई करके पौधों की आपसी दूरी उपयुक्त कर देनी चाहिए।

## जल प्रबंध

बाजरा का केवल 3.3 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। अतः जल का समुचित प्रबंध करना सफल खेती और उत्पादन स्थिरता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। वर्षा का केवल 5-15 प्रतिशत जल पौधों की बढ़वार के लिए उपलब्ध हो पाता है। इस प्रकार बाजरा उगाने वाले क्षेत्रों में जल का वैज्ञानिक प्रबंधन ही उनकी सफल खेती में सहायक हो सकता है। भूमि तल को समतल बना देने पर भूमि पर गिरने वाली वर्षा का समान वितरण होता है। तथा पानी भूमि में लम्बे समय तक भरे रहने के कारण इसका उत्तम संरक्षण करना संभव होता है। मेड़ बांधने की क्रिया जल संरक्षण में काफी सहायक पायी गयी है। वर्षा जल खेत में लम्बे समय तक खड़े रहने के कारण बहाव के माध्यम से बह जाने वाले जल की अधिक से अधिक मात्रा भूमि द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा यह मात्रा भूगत होने के कारण सुरक्षित रहती है। यह विश्वास किया जाता है कि भूमि की ऊपरी सतह को संहत करने पर बाजरा के पौधे की जड़े अधिक गहराई तक जाती है जिसके कारण उपलब्ध भूमि जल का अच्छा उपयोग होता है तथा जड़ों का जल ग्रहण क्षेत्र भी बढ़ जाता है। इस क्रिया को शायद इसी कारण से मूल प्रशिक्षण (रुट ट्रेनिंग) भी कहा जाता है। क्योंकि जड़ों के नीचे की ओर बढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानि कि ऐसी स्थिति बनायी जाती है कि इसकी बढ़वार नीचे की ओर अधिक हो।

## जल निकास

बाजरे की फसल यदि काफी देर तक पानी खड़ा रहे, तो इससे फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। इसलिए बुवाई से पूर्व खेत को समतल कर लेना चाहिए

# अमरबेल का नियंत्रण

## प्रसारण

- परजीवी के बीज एवं तने के भाग सिंचाई करने से जल द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं।
- खाद द्वारा भी बीज खेत में आ जाते हैं।
- तने के टुकड़ों का स्थानांतरण मनुष्यों एवं जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है।
- इसके बीज बरसीम, रिजका के बीजों के साथ जुड़े रह सकते हैं।

## हानि

अमरबेल के संक्रमण से मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार से हानि होती है-

- नींबू में 30-35 प्रतिशत
- मूंग में 70-90 प्रतिशत
- उड़द में 30-40 प्रतिशत
- रिजका, बरसीम में 60-70 प्रतिशत तक उपज में हानि होती है।

## नियंत्रण

इस परजीवी पादप के नियंत्रण हेतु समन्वित प्रबंध करना अति आवश्यक है-

## नियंत्रण के उपाय

- नमक के 10 प्रतिशत (1 लीटर पानी में 100 ग्राम) घोल में बीजोपचार करके फसल के बीजों की बुवाई करें।
- अमरबेल के बीज रहित फसल के बीज ही बुवाई के काम लें।
- कृषि यंत्रों व पशुओं को अमरबेल से संक्रमित खेतों से स्वच्छ खेतों में न आने दें।
- अमरबेल से ग्रसित फार्म से कम्पोस्ट खाद तैयार न करें।

## शस्य नियंत्रण

संक्रमित पौधों को परजीवी में बीज बनने से पहले उखाड़ कर जला दें।

- कम से कम पांच वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए।
- पाश फसलें जैसे ग्वार आदि उगाना चाहिए इसकी बढ़वार कम होगी।
- फसलों की सहनशील किस्में जैसे रिजके की एलएलसी 6 व एलएलसी 7, मूंग की एम-4 व उदड़ की टी-9 किस्में बोनी चाहिए।

## जैविक नियंत्रण

मैलेनाग्रोमाइजा करुक्यूटा व कालेटोट्राइकम ग्लोइयोस्पोरीयोडीस के द्वारा भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं।

- ल्यूबाओ-2 जो कि कोलेटोट्राइकम ग्लोइयोस्पोरीयोडिस करुक्यूटी रोगजनक का उत्पाद है, से भी जैविक नियंत्रण कर सकते हैं।

## रासायनिक नियंत्रण

- क्लोरोफॉम 6-7 किग्रा (सक्रिय तत्व) या डाइक्लोनेनील 2 किग्रा (सक्रिय तत्व) प्रति हेक्टेयर मिट्टी में प्रयुक्त करें।
- खड़ी फसल (रिजका व बरसीम) में कटाई के 5-10 दिन बाद डाइकव्ट 6-10 किग्रा प्रति हेक्टेयर आवश्यकतानुसार पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- पेड़ों तथा बहुवर्षीय बेलों पर पेराक्वाट के 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें। तथा उपचारित परपोषी पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- यदि अमरबेल पर छिड़काव के बाद कोई अवशेष बच जाये तो पुनः बताये शाकनाशियों का छिड़काव करें।

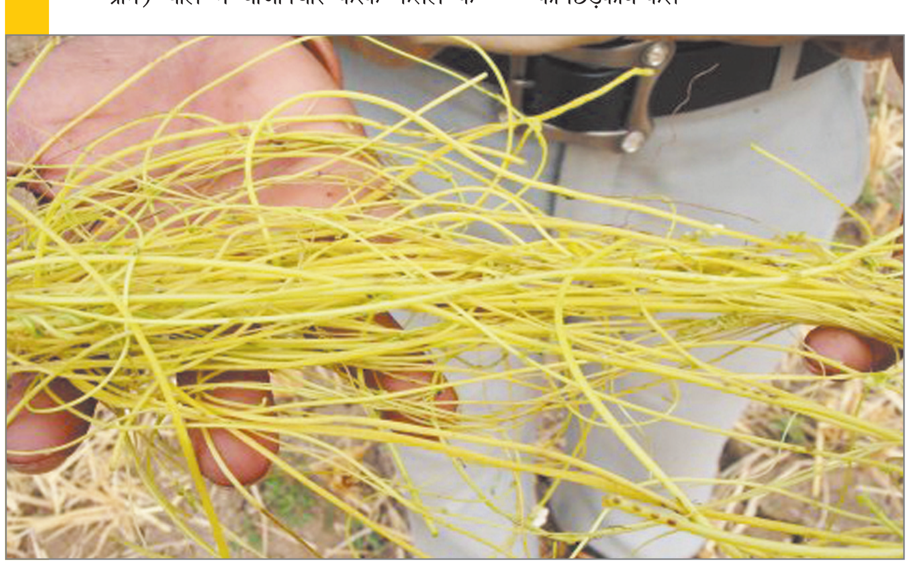

**इकाई क्षेत्र में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हेतु वर्ष 1983 में फादर हेनरी द्वारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेसीफिकेंशन का उद्भव मेडागास्कर में किया गया। इस पद्धति से 7-15 टन धान प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जा सकता है।**

# धान की मेडागास्कर खेती

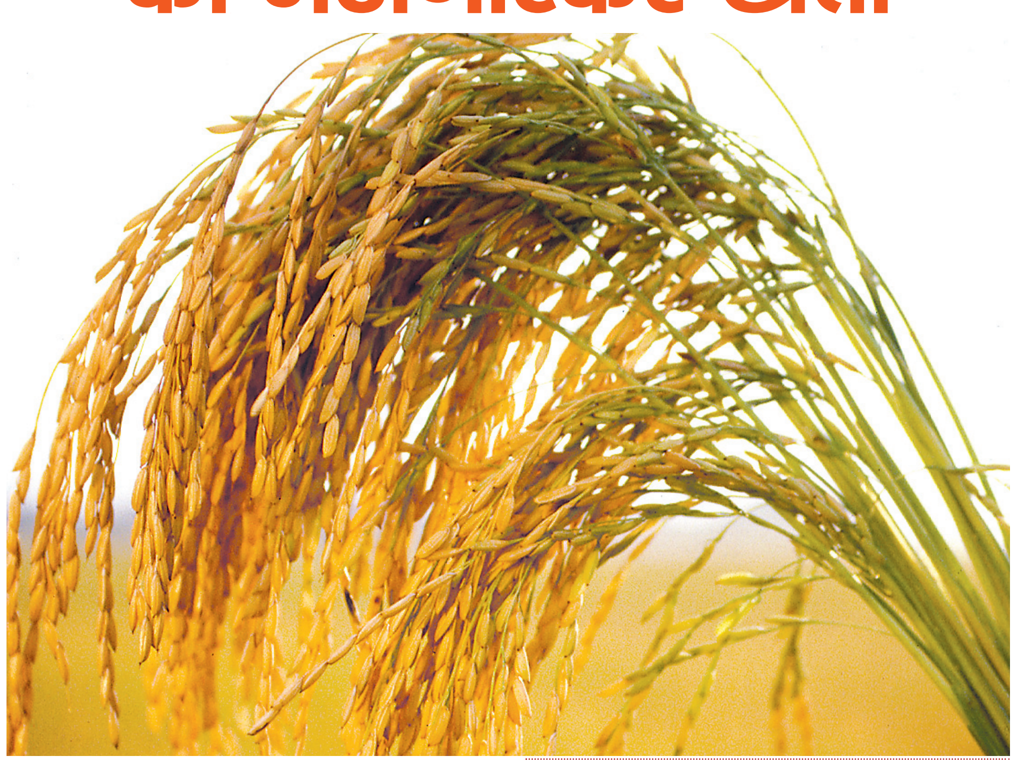

भारत में हरित क्रांति आने के बाद से लेकर अब तक विभिन्न आदानों की इकाई लागत में काफी वृद्धि हुई है इस वृद्धि के फलस्वरुप शुद्ध लाभ भी कम प्राप्त हो रहा है, इस हेतु यह आवश्यक हो गया है कि इकाई क्षेत्र में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाये। इकाई क्षेत्र में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हेतु वर्ष 1983 में फादर हेनरी द्वारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेसीफिकेंशन का उद्भव मेडागास्कर में किया गया इस पद्धति से 7-15 टन धान प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जा सकता है।

## मेडागास्कर विधि की कृषि कार्यमाला

खेत का चुनाव-मेडागास्कर विधि से धान की खेती करने हेतु उचित जल निकास वाली भूमि का चुनाव करना चाहिए तथा सिंचाई की भी व्यवस्था खेत पर होना चाहिए। बीज की मात्रा-इस विधि से धान की रोपाई करने के लिए 10-12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर पड़ती है।

## धान की उन्नत किस्में

कम अवधि में पकने वाली किस्में-तृप्ति, पूर्वा, जेआर 75

मध्यम समय में पकने वाली किस्में-जेआर 201,दीप्ति, जेआर 353

सामान्य अवधि में पकने वाली किस्में-आई.आर. 36, आई.आर. 64, माधुरी,पूसा सुगंधा

देर से पकने वाली किस्में :-स्वर्णा, श्यामला, महासुरी

संकर किस्में-एपीएचआर-1, एपीएचआर-2, एमजीआर-1, सीएनआर एच-1, पंत संकर धान

## नर्सरी हेतु खेत की तैयारी एवं बीज की बुवाई

खेत की अच्छी तरह आड़ी-तिरछी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए तत्पश्चात एक मीटर चौड़ी 10 मीटर लम्बी 15 सेमी ऊंचाई की क्यारी बना लें, क्यारी के दोनों ओर सिंचाई नाली बनाये क्यारी तैयार कर 50-60 किलोग्राम नाडेप कम्पोस्ट मिलाकर समतल कर दें तैयार क्यारी में उपचारित बीज को बिखेर दें तथा ऊपर से कम्पोस्ट खाद की पतली परत बिछाकर बीजों को ढ़क दे बीज का उपचार कर ही क्यारी डालना चाहिए। बीज उपचार हेतु स्युडोमोनास फ्लोरोसेंस 3 ग्राम प्रतिकिलो बीज की दर से उपयोग करना आवश्यक होता है। प्रति क्यारी 120 ग्राम बीज की मात्रा या 12 ग्राम प्रति वर्ग मीटर बीज की रोपणी डालने की आवश्यकता होती है। रोपणी की बोनी उपरांत प्रथम सिंचाई हजारे से की जाना चाहिए, शेष सिंचाई रोपणी के दोनों तरफ उपलब्ध सिंचाई नाली से करना चाहिए।

## रोपाई हेतु खेत की तैयारी

रोपाई किये जाने वाले खेत की अच्छी तरह जुताई कर भुरभुरा कर लें तथा खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए। तथा खेत में 8-10 टन नाडेप कम्पोस्ट/गोबर की पकी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। इस प्रकार रोपणी के लिए खेत तैयार हो जायेगा। सामान्यतः 10-15 दिन की पौध इस पद्धति में रोपाई हेतु उपयुक्त होती है। इन पौधों को जड़ सहित सावधानीपूर्वक उखाड़ कर 20 से 30 मिनट के अंदर खेत में रोप देना चाहिए। रोपाई एक से दो सेमी गहराई पर करें तथा पौध को खेत में सीधा रोपना चाहिए। रोपाई के समय खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए। एक स्थान पर एक ही पौधे की रोपाई करें तथा पौध से पौध की दूरी 25 सेमी एवं कतार से कतार की दूरी 23 सेमी रखना चाहिए, जिससे कंसे अधिक संख्या में निकलते हैं।

## खाद उर्वरक की मात्रा

खेत की मिट्टी का परीक्षण कराकर तत्वों की उपलब्धता जानने के बाद ही खाद की मात्रा निश्चित की जानी चाहिए, इस विधि में कार्बनिक खादों एवं रासायनिक खादों का उपयोग करना अनिवार्य है चयनित खेत में हरी खाद के लिए सनई/ढैंचा की बोनी कर 20-25 दिन बाद मचाई कर मिट्टी में मिला दें तथा 3-4 दिन के लिए छोड़ दें तत्पश्चात रोपाई करें। रासायनिक खाद में 80 किलोग्राम 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टर होती है। फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग आधार खाद के रुप में किया जाना चाहिए व नत्रजन का उपयोग तीन किश्तों में 20 प्रतिशत के एक सप्ताह बाद 50 प्रतिशत कंसे फूटने के समय एवं शेष 30 प्रतिशत गभोट के प्रारंभ काल में किया जाना चाहिए। वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने पर नत्रजन की मात्रा कम की जा सकती है।

## श्रीलंका ने कोलंबो टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम का किया ऐलान

**नई दिल्ली, एजेंसी।** श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने भारत के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है। 14 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर सहन अराचिगे और बल्लेबाज कामिल मिशारा को शामिल किया गया है। पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए दिनेश चांदीमल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनके रिप्लेसमेंट रहे पासिंदु सोरियाबंदारा को भी टीम से बाहर रखा गया है। दूसरे ओपनर निशान मदुश्का को जगह नहीं मिली, जबकि गेंदबाजी ऑलराउंडर रमेश मेंडिस और तेज गेंदबाज दिलशान मदुश्का भी टीम में जगह नहीं बना सके। अराचिगे को भारत ए के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। अराचिगे ने भारत ए के खिलाफ हाल ही में श्रीलंका ए क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी और बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अराचिगे ने पहले मैच में 72 और दूसरे मैच में 127 रन की पारी खेली थी। दो अनाधिकारिक मैचों की सीरीज में भारतीय साई सुदर्शन के बाद अराचिगे दूसरे श्रेष्ठ स्कोरर रहे थे। अराचिगे को टेस्ट डेब्यू का इंतजार है। मिशारा लंका प्रीमियर लीग 2026 में शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने हाल के सीजन में नौ पारियों में 411 रन बनाए थे। उन्होंने गॉल गैलेंट्स के खिलाफ शतक भी बनाया था। वे मेजर क्लब्स टी20 कॉम्पिटिशन में शानदार फॉर्म में थे और महज 72 गेंदों पर 145 रन की पारी खेली थी। श्रीलंका पहला टेस्ट मैच हार चुकी है। सीरीज बचाने के लिए श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। पहला टेस्ट टीम इंडिया ने 165 रन से जीता था।

**श्रीलंका टीम:**

लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, पासिंदू सोरियाबंदारा, कामिंडू मेंडिस (उपकप्तान), धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सहन अराचिगे, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, मिलन रत्नायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो।

## कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने टीम इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी की

**कोलंबो, एजेंसी।** श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंडिया हाउस में भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी की। भारतीय उच्चायुक्त झा ने गुरुवार रात भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ही श्रीलंकाई टीम की भी मेजबानी की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी दी है और इसे एक 'यादगार शाम' बताया है। बीसीसीआई ने अपने एक्स में लिखा, 'कोलंबो में एक यादगार शाम। श्रीलंका में इंडिया के उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले कोलंबो के इंडिया हाउस में भारतीय टीम की मेजबानी की।' झा ने दोनों टीमों की मेजबानी करके खुशी जाहिर की और कार्यक्रम की कुछ झलकियां एक्स पर साझा की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'टीम इंडिया के साथ चीयर कर रहा हूं। श्रीलंका में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचों के दौरान भारतीय और श्रीलंकाई पुरुष क्रिकेट टीमों की मेजबानी करके खुशी हो रही है। खेल के लिए एक जैसे जुनून से बंधा, क्रिकेट भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा रहने वाले रिश्तों को और मजबूत कर रहा है।' भारत ने गाले में पहले टेस्ट में 165 रन की बड़ी जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। गाले टेस्ट में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए थे। देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन बनाए थे। श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटकर 178 रनों से पिछड़ी थी। भारतीय टीम दूसरी पारी में 193 रन पर सिमटी और पहली पारी में मिले 178 रन की बढ़त के आधार पर श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। श्रीलंका दूसरी पारी में 206 रन पर सिमट गई और 165 रन से मैच हार गई। दूसरी पारी में भारत के लिए मानव सुथार ने 6 विकेट लिए थे।

सिनसिनाटी ओपन

# इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंची

### एलेना रयबाकिना इंजरी की वजह से बाहर

**सिनसिनाटी, एजेंसी।** एलेना रयबाकिना को सिनसिनाटी ओपन क्वार्टर फाइनल मैच से बाएं टखने में चोट के कारण बाहर होना पड़ा। इंजरी की वजह से जहां वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई, वहीं उनकी विपक्षी इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंच गई। मैच के दौरान स्वियाटेक 4-1 से आगे थीं और रयबाकिना 40-15 पर सर्व कर रही थीं। उसी समय रयबाकिना के लिए मुश्किल शुरू हुई। रयबाकिना नेट पर एक रैली खत्म नहीं कर सकीं। डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के अनुसार, अगले पॉइंट पर उन्हें अपनी पहली सर्व पर पुश करने में मुश्किल हुई, जो सिर्फ तीन शॉट तक चली, और गेम के बीच में मेडिकल जांच के बाद, रयबाकिना ने कुछ देर बाद मैच खत्म करने का फैसला किया। रायबाकिना ने कहा, 'मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सर्व से पुश भी नहीं कर पा रही थी। चलने में दर्द हो रहा है। एमआरआई के बाद समस्या के बारे में और पता चलेगा।' उन्होंने कहा, 'यह मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। कनाडा में बहुत सारे मैच खेलने और यहां लगातार दो मैच खेलने के बाद और मैच से पहले ठीक लग रहा था लेकिन बदकिस्मती से एक गलत मूवमेंट, एक लैंडिंग, और समस्या शुरू हो गई।' बुधवार को चौथे राउंड में सारा बेजलेक

सिनसिनाटी ओपन

## आर्थर फिल्स ने थियागो अगस्टिन टिरेंटे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

**सिनसिनाटी, एजेंसी।** आर्थर फिल्स ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फिल्स ने 64 मिनट तक चले मुकाबले में थियागो अगस्टिन टिरेंटे को 6-3, 6-2 से हराया। फिल्स ने इस सीजन के तीसरे एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 22 साल के फिल्स एक सीजन में तीन मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी बन गए। उनसे पहले गाइ फॉरगेट ने 1991 में यह उपलब्धि हासिल की थी। फरवरी में आठ महीने की चोट के बाद वापसी करते हुए फिल्स का शानदार सीजन रहा है। एटीपी जीत/हार इंडेक्स के मुताबिक, इस साल फ्रेंचमैन का टूर-लेवल रिकॉर्ड 30-10 रहा है, जिसमें बार्सिलोना में एक खिताब और मियामी और मैड्रिड में मास्टर्स 1000 इवेंट्स के सेमीफाइनल में पहुंचना शामिल है।

पहले सेट में 4-3 पर एक अहम ब्रेक हासिल करने के बाद, फिल्स ने लगातार जबरदस्त फोरहैंड लगाए, जिससे टिरांटे लगातार बैकफुट पर रहे। एटीपी के मुताबिक, 22 साल के खिलाड़ी ने दूसरे सेट में अर्जेंटीना के खिलाड़ी की सर्विस दो बार तोड़ी और पूरे मैच के दौरान उन्हें कभी भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। अब वह टाइटल मैच में जगह बनाने के लिए फ्लेवियो कोबोली से भिड़ेंगे, दोनों खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंचना चाहते हैं।

कोबोली ने घरेलू पसंदीदा टॉमी पॉल के खिलाफ 2-6, 6-3, 6-4 से जीत हासिल की और ओहियो में अपने पहले मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंच गए। 24 साल के खिलाड़ी अब जून में रोलैंड गैरोस चैंपियनशिप मैच में पहुंचने के बाद अपने पहले सेमीफाइनल की तैयारी करेंगे। वह 2024 और 2025 में जैनिक सिनर के बाद सिनसिनाटी में अंतिम चार में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे इटैलियन खिलाड़ी हैं। पॉल के खिलाफ जीत के साथ, कोबोली ने यह भी पक्का कर लिया कि वह सोमवार को एटीपी रैंकिंग में अपने करियर की नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वह अभी लाइव रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 6 पर हैं।

## जैकब मार्टिन को 22 साल पुराने में पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में बड़ी राहत दी है। 2004 के इस मामले में कोर्ट ने मार्टिन को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर पर फर्जी यूके आव्रजन स्टाम्प, यात्रा व्यवस्था और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा आरोप लगाया गया था, जिसे साबित नहीं किया जा सका। अदालत को वित्तीय लेनदेन या अजवा स्पोर्ट्स क्लब पर उनके स्वामित्व या नियंत्रण से जुड़ा कोई भी ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं मिला। कई गवाह भी इन आरोपों को साबित करने में विफल रहे। मीडिया से बात करते हुए मार्टिन ने बताया कि यह मामला 2004 में उनकी टीम के एक सदस्य द्वारा ब्रिटेन का वीजा समाप्त होने के बाद वहां रुकने और फर्जी आव्रजन स्टाम्प लगवाकर भारत लौटने के बाद शुरू हुआ था। मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था। बाद में उनका नाम मामले में जोड़ दिया गया। घटना के बारे में मार्टिन ने कहा, 2004 में टीम इंग्लैंड खेलने गई थी। जो टीम 2004 में इंग्लैंड गई थी, उसमें से एक लड़के को छोड़कर बाकी सब वापस आ गए। वीजा की वैधता छह महीने की थी, वह छह महीने तक रह सकता था। वह इससे अधिक समय तक रुका रहा। किसी के जरिए उसने वहां फर्जी स्टैंपिंग करवा ली। फर्जी स्टैंपिंग कराने के बाद जब वह भारत वापस आया, तो उसे ब्रिटेन से डिपोर्ट कर दिया गया था। उसे नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और फिर उससे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा, 'मेरा नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन जब जांच हुई, तो एक बड़ा नाम होने के नाते मुझे इस मामले में घसीटा गया।

## यूएस ओपन 2026: प्राइज मनी में भारी वृद्धि

**नई दिल्ली, एजेंसी।** ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खिलाड़ियों द्वारा प्राइज मनी बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। यूएस ओपन 2026 में खिलाड़ियों की ये मांग पूरी होने वाली है। यूएस ओपन में इस बार खिलाड़ियों के प्राइज मनी में इजाफा होने वाला है। यूएस ओपन की प्राइज मनी में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। खिलाड़ियों की कुल सैलरी बढ़कर 108 मिलियन डॉलर हो गई है। टूर्नामेंट से पहले, यूएसटीए (यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन) ने एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की। यूएसटीए के सीईओ क्रेग टिली ने कहा कि यह कदम खेल के आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो सकता है। यह एथलीटों में कई सालों के निवेश में एक अहम पहला कदम है क्योंकि यूएस ओपन खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा आर्थिक मौका और खिलाड़ियों, फैंस और पार्टनर्स के लिए टेनिस में सबसे कीमती प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एकल विजेता को 52.65 करोड़ मिलेंगे। वहीं, एकल फाइनल में हारने वाले खिलाड़ी को करीब 26.80 करोड़ रुपये (2.8 मिलियन) दिए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को लगभग 7.46 करोड़ रुपये (780,000) और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले प्लेयर्स को करीब 13.88 करोड़ रुपये (1.45 मिलियन) मिलेंगे। डबल्स मुकाबलों में पुरुष, महिला और मिक्स जीतने वाले प्लेयर्स को लगभग 9.57 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिन्हें वे आपस में बाटेंगी। वहीं उपविजेता टीमों को करीब 5,00,000 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। इसके अलावा, व्हीलचेयर सिंगल्स के चैंपियन्स को लगभग 99 लाख रुपये (1,04,000) की इनामी राशि मिलेगी। पहले ही मैच में हारकर बाहर होने वाले खिलाड़ी को भी लगभग भारतीय रुपये में 1.34 करोड़ रुपये (140,000) मिलेंगे। यूएस ओपन रोमांचक होने वाला है। पिछले 4 महीने से पेशेवर टेनिस से दूर रहे पूर्व चैंपियन कार्लोस अल्काराज अपना खिताब बचाने के लिए उतरेंगे। अल्काराज ने अप्रैल के बाद से एक भी मैच नहीं खेला है। उन्हें बार्सिलोना ओपन के दौरान कलाई में चोट लग गई थी। चोट की वजह से वह फ्रेंच ओपन, विंबलडन और कई दूसरे टूर्नामेंट से भी बाहर रहे। यूएस ओपन 2026 की शुरुआत 23 अगस्त से होगी और 13 सितंबर को पुरुषों के फाइनल के साथ खत्म होगा।

## डोपिंग को लेकर नाडा की बड़ी कार्रवाई, इस भारतीय भाला फेंक एथलीट पर लगाया 10 साल का प्रतिबंध

**नई दिल्ली, एजेंसी।** राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने डोपिंग को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। ओलंपियन भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह पर दूसरे डोपिंग अपराध के लिए 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्व एशियाई रजत पदक विजेता और ओलंपियन भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह पर दूसरे डोपिंग अपराध के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के अनुशासनात्मक पैनल ने 10 साल का प्रतिबंध लगाया है। शिवपाल प्रतिबंधित पदार्थ मेथाएंडिएनोन के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। 31 साल की उम्र में यह प्रतिबंध उनके खेल करियर का अंत कर सकता है। शिवपाल ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

### पहले लगा था चार साल का प्रतिबंध

नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने अगस्त 2022 में उन्हें डोपिंग उल्लघंन का दोषी मानते हुए 2021 से चार साल का प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 2025 तक चलना था, लेकिन शिवपाल ने नाडा के अपील पैनल के सामने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि उनकी डोप जांच में पॉजिटिव आने के पीछे दूषित सप्लीमेंट्स जिम्मेदार थे। जनवरी 2023 में अपील पैनल ने उनकी दलील स्वीकार करते हुए प्रतिबंध को चार साल से घटाकर सिर्फ एक साल कर दिया।

### एशियाई चैंपियनशिप में जीता था रजत

शिवपाल के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतना है। दोहा में उन्होंने 86.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यह पदक हासिल किया था। हालिया मामलों में कार्रवाई का सामना करने वाले शिवपाल अकेले भारतीय एथलीट नहीं हैं। धाविका एमवी जिल्ना को भी दूसरे डोपिंग उल्लघंन के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया गया और वह मेफेंटरमाइन के लिए पॉजिटिव मिलीं। इससे पहले 2021 में शिवपाल का डोप नमूना प्रतियोगिता से बाहर की गई जांच में एक स्टेरॉयड के लिए पॉजिटिव आया था।

## कट शॉट बना यशस्वी जायसवाल का 'दुश्मन', 27 गेंदों में 4 बार फंसे...कोलंबो टेस्ट से पहले की गंभीर तैयारी

**नईदिल्ली, एजेंसी।** भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो के एसएससी मैदान में 23 अगस्त (रविवार) से होना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले यशस्वी जायसवाल अपनी एक खास कमजोरी पर जोरदार मेहनत कर रहे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है. मुकाबले से दो दिन पहले यशस्वी जायसवाल ने नेट्स में अपनी उस कमजोरी पर खास तौर पर काम किया, जो गॉल टेस्ट में फिर सामने आई थी. ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंदबाजों की गेंद पर कट शॉट खेलने की उनकी आदत इन दिनों परेशानी बनती दिख रही है. भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल अब तक 30 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उन्होंने हर टेस्ट अलग-अलग मैदान पर खेला है. टेस्ट डेब्यू से लेकर अब तक उनका सफर कैरेबियाई देशों, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और अब श्रीलंका तक पहुंच चुका है. सिर्फ तीन साल के टेस्ट करियर में ही जायसवाल भारतीय बल्लेबाजी की अहम कड़ी बन चुके हैं. सफेद गेंद क्रिकेट वाली उनकी आक्रामकता

### नेट्स में शुरू हुआ सुधार का काम

जायसवाल के गलत शॉट खेलने का प्रतिशत भी बढ़ा है. पहले यह आंकड़ा 31.1 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 48.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है. यही वजह रही कि शुक्रवार को कोलंबो के स्स्ष्ट मैदान पर भारत के तेज गेंदबाजों ने नेट्स में उन्हें लगातार इस एरिया में परखने की कोशिश की.

### कट शॉट बना परेशानी की वजह?

गॉल टेस्ट में श्रीलंका के तेज गेंदबाज फर्नांडो ने जायसवाल को ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद पर फंसाया. जायसवाल गेंद को कट करने के लिए गए, लेकिन किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर डिकवाला के पास चली गई. आंकड़े बताते हैं कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलते हुए आउट होने का पैटर्न हाल के महीनों में बढ़ा है. पिछले साल अक्टूबर में भारतीय घरेलू टेस्ट सीजन शुरू होने के बाद से जायसवाल सिर्फ 27 गेंदों में तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलने के प्रयास में चार बार आउट हो चुके हैं. वहीं टेस्ट डेब्यू से लेकर पिछले साल इंग्लैंड दौरे तक, करीब दो साल के दौरान वह 190 गेंदों में सिर्फ चार बार इस शॉट पर आउट हुए थे. यानी हाल के समय में यह कमजोरी ज्यादा साफ होकर सामने आई है.

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप

## त्रिसा-गायत्री ने दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी को हराया, महिला डबल्स में मेडल पक्का

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी जी यिफान और झांग शुक्सियन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। त्रिसा-गायत्री की जीत ने देश के लिए मेडल पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने एक गेम पीछे रहने के बाद चीनी जोड़ी पर 16-21, 21-15, 21-13 से जीत दर्ज की और महिला डबल्स में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली दूसरी जोड़ी बन गई। इससे पहले महिला डबल्स में 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने कांस्य पदक जीता था। शुरुआत में भारतीय जोड़ी कमजोर दिखी क्योंकि जिया और झांग ने 6-2 की बढ़त बना ली और शुरुआती गेम तक अपनी बढ़त बनाए रखी। त्रिसा और गायत्री ने धीरे-धीरे अपनी आक्रामक रिदम पाई, अपने पावरफुल स्मैश और नेट के दम पर अंतर को 8-9 कर दिया। हालांकि, रिकवरी इतनी नहीं थी कि चीनी खिलाड़ी को 11-8 की बढ़त के साथ ब्रेक में जाने से रोका जा सके और आखिरकार शुरुआती गेम 21-16 से जीत लिया। दूसरे गेम भारतीयों ने अपने विरोधियों को वैसा नियंत्रण नहीं करने दिया, लंबी रैलियों में उनका मुकाबला किया और दबाव में डिफेंड करते हुए इंटरवल पर 11-10 की मामूली बढ़त हासिल की। वहां से, त्रिसा और गायत्री और ज्यादा आक्रामक हो गईं। उनके क्रॉस-कोर्ट अटैक ने बार-बार चीनी जोड़ी को कोर्ट के पार खींचा, जबकि उनके डिफेंस ने जिया और झांग के दबाव को झेला। इंडियन्स ने 17-14 की बढ़त के साथ शुरुआत की और फिर गेम 21-15 से खत्म करके निर्णायक बना दिया। निर्णायक गेम में 4-4 से बराबरी की शुरुआत के बाद, त्रिसा ने एक जोरदार स्मैश से ब्रेकथ्रू पाया, और भारतीय जोड़ी ने बढ़त बना ली। लगातार सात पॉइंट्स ने मैच का पासा पलट दिया, जिससे वे 4-4 से 9-4 पर आ गए। त्रिसा के अटैक ने चीनी जोड़ी को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। भारतीय जोड़ी ने 11-5 की बड़ी बढ़त के साथ इंटरवल में एंट्री की। साइड बदलने के बाद, जिया और झांग ने थोड़ी देर के लिए अपनी चुनौती को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने लगातार तीन पॉइंट्स जीतकर अपनी लय वापस पा ली। चीनी जोड़ी पर बढ़ते दबाव के साथ, उनके गेम में गलतियां होने लगीं। 18-9 पर, भारतीय बस बराबरी पर थे। झांग के शॉट को आउट दिए जाने के बाद एक समीक्षा से नतीजे में ज्यादा बदलाव नहीं आया। चीनी जोड़ी की दो और गलतियों ने त्रिसा और गायत्री को निर्णायक पाइंट दिला दिए। इस जीत के साथ भारतीय जोड़ी का पदक पक्का हो गया।

# ऋतिक-सबा के ब्रेकअप की खबरों ने पकड़ा जोर

अभिनेता ऋतिक रोशन कई साल से सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर साथ में पार्टी और इवेंट में देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे पर खूब प्यार लुटाते हैं। मगर, इन दिनों बी-टाउन में दोनों के ब्रेकअप की अटकलों ने जोर पकड़ा है। इसकी वजह ऋतिक रोशन की प्रोफाइल का कथित तौर पर एक डेटिंग एप पर देखा जाना है।
सुजैन खान से तलाक के बाद ऋतिक रोशन की जिंदगी में सबा आजाद की एंट्री हुई है। दोनों के बीच उम्र का काफी अंतर है। मगर, आपसी समझ काफी अच्छी है। अक्सर दोनों छुट्टियां मनाने जाते हैं। साथ में पार्टी करते हैं और बॉलीवुड के कई इवेंट्स में साथ में शिरकत करते हैं। मगर, इन दिनों ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों की राहें जुदा हो गई हैं।

### क्यों शुरू हुई अटकलें

सबा से ऋतिक के रिश्ते में दूरी की वजह, एक डेटिंग एप पर अभिनेता की प्रोफाइल का पाया जाना है। दरअसल, 'राया' नाम के एक डेटिंग एप पर ऋतिक रोशन की प्रोफाइल होने का दावा किया गया है। इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल स्क्रीनशॉट में ऋतिक के प्रोफाइल बायो में 'एक्टर/ प्रोड्यूसर/ एंटरप्रेन्योर' लिखा दिख रहा है। इस वायरल प्रोफाइल के बाद ही ऐसे सवाल आ रहे हैं कि क्या दोनों का ब्रेकअप हो गया है? हालांकि, रिलेशनशिप को लेकर चल रहीं अटकलों पर अभी तक ऋतिक रोशन और सबा आजाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

### उर्वशी रौतेला ने भी किया था दावा

रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में उर्वशी रौतेला ने भी एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने सेलिब्रिटी डेटिंग एप 'राया' पर ऋतिक रोशन और आदित्य रॉय कपूर के प्रोफाइल देखे थे। हालांकि, उर्वशी रौतेला ने सीधे-सीधे ऋतिक रोशन के रिलेशनशिप स्टेटस से जोड़कर कोई टिप्पणी नहीं की थी। मगर, उर्वशी के पुराने बयान और अब वायरल स्क्रीनशॉट को लेकर सबा और ऋतिक के रिश्ते में आई दूरी से जोड़कर देख रहे हैं। देखना होगा कि ऋतिक या सबा ऐसी अफवाहों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

# वीर पहाड़िया को बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करेगी 'प्रेम कीटाणु'

स्काई फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद वीर पहाड़िया लगातार बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करते जा रहे हैं और इसका सबूत है महेश भट्ट की नाम – टू लिव इज़ वॉर के बाद उनकी अगली थिएट्रिकल फिल्म प्रेम कीटाणु, जिसकी घोषणा उन्होंने हाल ही में की है। इस फिल्म में वीर पहाड़िया के साथ अपारशक्ति खुराना, आफिया सैयद, राकेश बेदी और निखिल विजय भी नजर आएंगे।
'प्रेम कीटाणु' का निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की ने किया है, जो 'सिर्फ एक बंदा काफी है' और चर्चित सीरीज 'एस्पिरेंट्स' के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म गौरव वर्मा के नए लॉन्च किए गए बैनर अवनिका फिल्म्स की पहली प्रोडक्शन है, जिसे फार्स फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी कहानी युवाओं की आकांक्षाओं, रिश्तों और रोजमर्रा की चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमती इस फिल्म की कहानी एक दिल छू लेने वाली और रिलेटेबल एंटरटेनर है। हास्य और भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में आधुनिक जीवन और प्यार को एक नए नजरिए से पेश करने की कोशिश भी की गई है। ऐसे में यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 'प्रेम कीटाणु' वीर पहाड़िया को उनके डेब्यू 'स्काई फोर्स' से बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करेगी। 'स्काई फोर्स' में उन्होंने भारतीय वायुसेना के अधिकारी टी. विजया का किरदार निभाया था। वीर अपने करियर के शुरुआती दौर में ही अलग-अलग तरह के किरदार और जॉनर तलाश रहे हैं। जैसा कि वीर की आगामी फिल्मों की लिस्ट में डार्क एक्शन थ्रिलर 'नाम – टू लिव इज़ वॉर' भी शामिल है।
महेश भट्ट द्वारा प्रस्तुत और सिद्धांत सचदेव द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वीर के साथ वरुण शर्मा नजर आएंगे, जो पहली बार नेगेटिव भूमिका में दिखाई देने की उम्मीद है। फिल्म का निर्माण रिद्धि चावड़ा और उत्सव उपाध्याय कर रहे हैं। 'प्रेम कीटाणु' और 'नाम – टू लिव इज़ वॉर' के जरिए वीर पहाड़िया दो बिल्कुल अलग सिनेमाई दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। एक ओर जहां 'प्रेम कीटाणु' रोमांस, हास्य और युवा भारत की रोजमर्रा की वास्तविकताओं को सामने लाएगी, वहीं 'नाम – टू लिव इज़ वॉर' में उनका एक इंटेंस और रग्ड एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। 'स्काई फोर्स' के बाद इन दोनों फिल्मों की घोषणा वीर पहाड़िया के करियर के अगले चरण की ओर इशारा करती है, जहां अभिनेता किसी एक इमेज तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग जॉनर और किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

# रुक्मिणी वसंत ने टॉक्सिक को बताया अब तक किए हर काम से बिल्कुल अलग

मुंबई में टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स के म्यूजिक लॉन्च पर रुक्मिणी वसंत ने फिल्म का हिस्सा बनने और मेलिसा की दुनिया में कदम रखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके अब तक के किए गए काम से बिल्कुल अलग है।
टॉक्सिक को अपने लिए खास बताते हुए रुक्मिणी ने कहा, टॉक्सिक मेरे लिए, और इस फिल्म का हिस्सा रहे हर इंसान के लिए बेहद स्पेशल फिल्म है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकती हूं। जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसका एक्सपैंसिव होना, फिल्म का स्केल... पहली बार जब मैंने इसके बारे में सुना था, तभी इसका स्केल मुझे बहुत इम्प्रेस कर गया था। हालांकि, रुक्मिणी ने बताया कि उन्हें फिल्म की तरफ सिर्फ इसका स्केल और ग्रैंड्योर ही नहीं खींच लाया, बल्कि इसके किरदारों की कॉम्प्लेक्सिटी ने भी उन्हें काफी एक्साइट किया। उन्होंने कहा, फिल्म के स्केल और इस दुनिया की ग्रैंड्योर के साथ-साथ, हर किरदार का ग्रे शेड भी बहुत शानदार है। हर किरदार इतना रॉ और इतना ह्यूमन है।
रुक्मिणी ने बताया कि वह यह जानने को लेकर काफी एक्साइटेड थीं कि टॉक्सिक की इस बड़ी दुनिया में मेलिसा की जगह क्या है और उसका बाकी किरदारों के साथ कनेक्शन कैसा है। उन्होंने कहा, मैं यह डिस्कवर करने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी कि मेलिसा इस दुनिया में कहां फिट होती है और बाकी किरदार एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यह सब किस तरह आपस में जुड़ा हुआ है, इसे लेकर मैं बहुत क्यूरियस थी। एक्टर ने यह भी माना कि यश के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलना उनके लिए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। रुक्मिणी ने कहा, यश सर की फैनगर्ल होना और फिर उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलना, मेरे लिए यह भी एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। जब रुक्मिणी से पूछा गया कि टॉक्सिक को उनके लिए इतना खास क्या बनाता है, खासकर तब जब ऑडियंस ने उन्हें इससे पहले ऐसी दुनिया या किरदार में नहीं देखा है, तो उन्होंने कहा, यह अब तक मैंने जो भी काम किया है, उससे बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि इसमें एक यूनिकनेस है और उनके किरदार में एक खास तरह का जे ने से क्वा है। गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी नजर आएंगे। फिल्म 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

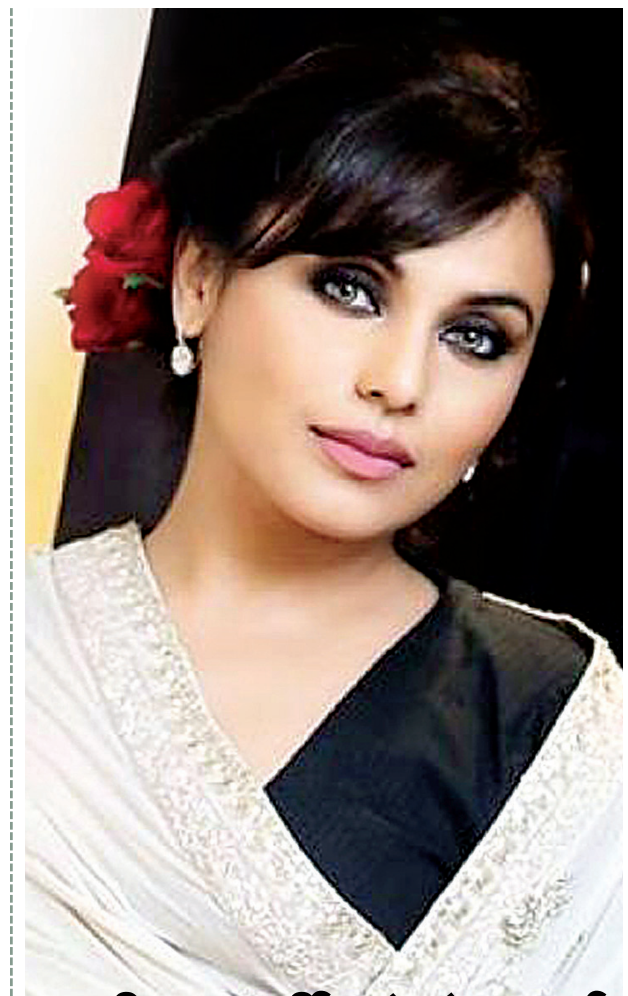

# रानी मुखर्जी को मेलबर्न में मिला खास सम्मान

**रानी मुखर्जी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक अलग-अलग किरदार निभाए हैं। उन्होंने कभी समाज की सोच को चुनौती देने वाली महिलाओं का किरदार निभाया, तो कभी मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाने वाली महिलाओं की कहानी पर्दे पर उतारी। अब इसी को देखते हुए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया है। तीन दशक से ज्यादा समय से अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली रानी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में खास सम्मान दिया गया है।**

उन्हें एक्टिंग में बेहतरीन योगदान के लिए स्पेशल सिटेशन से सम्मानित किया गया। रानी के इस सम्मान को भारतीय सिनेमा में उनके लंबे और शानदार सफर के लिए एक बड़ी पहचान माना जा रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें आज भी दर्शक याद करते हैं। उनके किरदारों और फिल्मों ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी लोगों के दिलों तक जगह बनाई है। 'ब्लैक', 'हम तुम', 'युवा', 'बंटी और बबली', 'नो वन किल्ड जेसिका', 'हिचकी', 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी और 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' जैसी फिल्मों में रानी की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। रानी ने हर फिल्म में अपने किरदार को पूरी ईमानदारी और भावनाओं के साथ निभाने की कोशिश की है। यही वजह है कि उनके कई किरदार आज भी दर्शकों के बीच खास जगह रखते हैं। इस सम्मान के बाद रानी मुखर्जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनकी आवाज घर से बहुत दूर तक पहुंची हैं। उनके लिए यह सफर बेहद खास रहा है। रानी का यह सम्मान सिर्फ उनकी एक्टिंग को पहचान नहीं देता, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय सिनेमा की कहानियां अब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दर्शकों तक पहुंच रही हैं।

# आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगी कल्याणी प्रियदर्शनी, रणवीर सिंह ने शुरू की शूटिंग

रणवीर सिंह ने अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में लीड रोल निभाने के साथ ही रणवीर इस फिल्म से बतौर निर्माता भी जुड़े हैं। 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सफलता के बाद रणवीर सिंह का यह पहला प्रोजेक्ट है। इस फिल्म को लेकर अभिनेता के फैंस बेहद एक्साइटेड हैं।

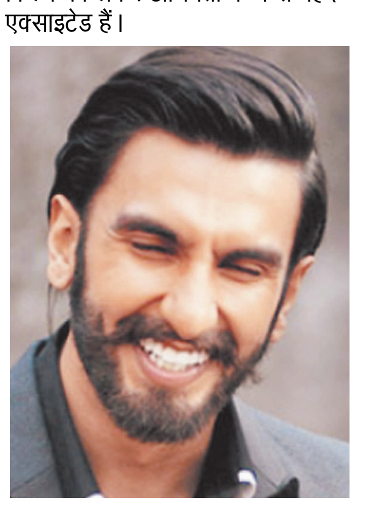

'प्रलय' को रणवीर के करियर का सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स बताया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है। इसे लाइव लोकेशन पर भी शूट किया जाएगा। रणवीर इस फिल्म में अभिनय करने के साथ ही इसका निर्माण भी कर रहे हैं। यह एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होगी। रणबीर के लिए यह महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। फिल्म में 'लोका' फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शनी भी अभिनय करती नजर आएंगी।

### बड़े पैमाने पर होगा काम

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'प्रलय' की कहानी काफी हद तक विजुअल इफेक्ट्स पर निर्भर करेगी। फिल्म में धुआंधार एक्शन सीन्स भी होंगे। रणवीर इस फिल्म के डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान क्रिएटिव चर्चाओं में भी एक्टिव रूप से शामिल हुए हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली 'प्रलय' रणवीर सिंह के करियर की सबसे महंगी स्टैंडअलोन फिल्म हो सकती है।

### फिल्म 'प्रलय' के बारे में

'प्रलय' में रणवीर सिंह मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वहीं कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका निभाएंगी। फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं। वहीं फिल्म का निर्माण अनन्या बिड़ला स्टूडियोज कर रहा है।

# '7 डॉग्स' की रिलीज को लेकर बेहद उत्साहित हूं

**अभिनेता संजय दत्त जल्द ही सलमान खान के साथ इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' में नजर आएंगे। यह फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है। एक्टर ने इस फिल्म में काम करने के अपने अनुभव को साझा किया।**

फिल्म '7 डॉग्स' एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने फिल्म का नया ट्रेलर लॉन्च किया था। अब इस फिल्म के बारे में संजू बाबा ने अपने अनुभव बताए। संजू ने कहा मैं '7 डॉग्स' के दर्शकों तक पहुंचने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। मुझे भारत में इसके रिलीज होने का बहुत इंतजार था। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ काम करने का काफी खास अनुभव रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका जिंदगी में बार -बार नहीं मिलता। यह फिल्म भारतीय दर्शकों को पसंद आएगी। उन्हें इसे देखकर खूब मजा आने वाला है। जब दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखेंगे तो उनके लिए यह अलग तरह का अनुभव होगा। अपनी बातचीत में आगे संजय दत्त ने कहा, 'मुझे लगता है भारतीय दर्शकों को इस फिल्म को खुले मन से देखना चाहिए और वे हैरान रह जाएंगे। यह एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म है, लेकिन इसकी भावनाएं दर्शकों के लिए आसानी से जुड़ने वाली हैं। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, दमदार किरदार हैं और फिल्म को बहुत बड़े स्तर पर बनाया गया है।'

## संक्षिप्त समाचार

### प्रिंस हैरी शाही भूमिकाओं के बिना ब्रिटेन लौटेंगे; भारतीय महिला को इस्राइल में अच्छी नागरिकता सम्मान

**लंदन, एजेंसी।** ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन ने यूनाइटेड किंगडम लौटने का फैसला किया है। हालांकि, वे शाही परिवार के कामकाजी सदस्यों के रूप में अपनी भूमिकाएं फिर से शुरू नहीं करेंगे। किंग चार्ल्स को रविवार को इस निर्णय के बारे में सूचित किया गया। हालांकि, पिछले महीने दंपती की यूके यात्रा के दौरान उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया था। डेली टेलीग्राफ ने यह खबर सबसे पहले प्रकाशित की है। अखबार के अनुसार, हैरी और मेघन के बच्चे, प्रिंस आर्ची (7) और प्रिंसेस लिलिबेट (5), ब्रिटिश स्कूलों में पहले ही दाखिला ले चुके हैं। वे सितंबर में अपनी कक्षाएं शुरू करेंगे। यह निर्णय दंपती द्वारा अपनी शाही जिम्मेदारियां छोड़ने के छह साल से अधिक समय बाद आया है। उन्होंने आकर्षक मीडिया अनुबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया का रुख किया था। ब्रिटेन लौटने से किंग चार्ल्स को अपने पोते-पोतियों से अधिक मिलने का अवसर मिलेगा। किंग चार्ल्स एक अज्ञात प्रकार के कैंसर का इलाज करा रहे हैं। दंपती ने छह साल से अधिक समय पहले अपने शाही कर्तव्यों को त्याग दिया था। वे कैलिफोर्निया में बस गए थे। इस वापसी से परिवार के संबंधों में मजबूती आ सकती है।

### इस्राइल में देखभाल करने वाली भारतीय महिला को अच्छी नागरिकता का सम्मान

**यरुशलम, एजेंसी।** इस्राइल पुलिस ने एक भारतीय महिला को अच्छी नागरिकता के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया है। देखभाल करने वाली इस महिला ने कार्मेल क्षेत्र में 95 वर्षीय होलोकॉस्ट पीड़ित को ठगी के प्रयास से बचाया था। बुधवार को तटीय जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में हाइफा पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं ने हीरा (हीराबेन) को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हीराबेन उस बुजुर्ग महिला की नर्सिंग देखभालकर्ता यानी कैयरगिवर के रूप में काम कर रही हैं। इजरायल में कुछ ही महीने रहने के बावजूद, हीराबेन ने सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उन्होंने महिला को एक कथित धोखेबाज से बचाया, जो क्लैलिट हेल्थ सर्विसेज की नर्स बनकर उनके अपार्टमेंट में आया था। देखभालकर्ता ने शांत रहते हुए घटना को दर्ज किया, संदिग्ध को बुजुर्ग महिला के पास जाने से रोका और पुलिस को सूचित किया। इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और संदिग्ध की हिरासत दो दिन पहले कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक बढ़ा दी गई थी। जांचकर्ता नोफर पाज़ ने बुजुर्ग महिला और उनके परिवार की उपस्थिति में हीराबेन को धन्यवाद दिया।

### सफारी के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, पांच अमेरिकी समेत सात लोगों की मौत

**नैरोबी, एजेंसी।** केन्या के उत्तरी हिस्से में बुधवार सुबह सफारी के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, मृतकों में पांच अमेरिकी नागरिक शामिल थे। हेलीकॉप्टर सुबह 9:13 बजे लॉइसाबा कंजरवेंसी से साम्बुरु काउंटी के इवासो न्यिरो इलाके की ओर जा रहा था। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, हेलीकॉप्टर में कुल सात लोग सवार थे। इनमें छह यात्री और एक पायलट था। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। साम्बुरु के पुलिस कमांडर डेविड नकोरोई ने बुधवार देर शाम पुष्टि की कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि मृतकों में पांच अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और पीड़ितों से जुड़े लोगों को जरूरी कांसुलर सहायता उपलब्ध करा रहा है। मृतकों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एक स्थानीय टीवी स्टेशन ने बताया कि मृतकों में जोस सुआरेज भी शामिल थे, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी और वह टेलीमुंडो के फ्लोरिडा स्थित कई स्टेशनों के अध्यक्ष और महाप्रबंधक थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हेलीकॉप्टर माउंट ओलोलोक्वे की तलहटी में स्थित एक दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ इलाके में गिरा। यह स्थान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। हेलीकॉप्टर स्थानीय कंपनी लेडी लॉरी हेलीकॉप्टर्स का था और चार्टर उड़ान के तहत यात्रियों को ले जा रहा था। सफारी कंपनी एंडबियॉन्ड के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए यह उड़ान संचालित की गई थी। ट्रॉपिक एयर केन्या ने तलाश और बचाव अभियान में मदद के लिए अपने दो हेलीकॉप्टर भेजे। केन्या रेड क्रॉस की आपातकालीन टीमें भी बहु-एजेंसी राहत अभियान में शामिल हुईं।

# गंगा जल पर फिर तनातनी: गारंटी प्रावधान मांगने की तैयारी में बांग्लादेश, क्या भारत से बिगड़ेंगे रिश्ते

**ढाका, एजेंसी।** बांग्लादेश ने भारत के साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। पड़ोसी मुल्क अब नई संधि में 'गारंटी प्रावधान' शामिल करने की मांग करेगा। साथ ही उसने संकेत दिया है कि पानी के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय मंचों का रुख भी किया जा सकता है। जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने मंगलवार को ढाका में आयोजित एक संगोष्ठी में यह बात कही। संगोष्ठी का विषय था- 'गंगा जल संधि- पुनर्विचार के मुद्दे'। इसका आयोजन बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने किया था। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने इसकी जानकारी दी।

**दिसंबर में समाप्त होने वाली है गंगा जल संधि :** भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि दिसंबर में समाप्त होने वाली है। यह संधि सूखे मौसम में गंगा के पानी के बंटवारे की व्यवस्था करती है। अनी ने कहा कि बांग्लादेश संधि पर दोबारा बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले महीने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश का पक्ष मजबूती से रखेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को संधि चाहिए। उनके मुताबिक, बिना संधि के आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है और यह बांग्लादेश का अधिकार है।

**क्या 1977 वाला गारंटी प्रावधान फिर लौटेगा :** अनी ने

भविष्य की जल-बंटवारा संधियों में सूचना के अधिकार से जुड़ा प्रावधान शामिल करने की जरूरत बताई। उन्होंने 1977 की गंगा संधि में मौजूद 'गारंटी प्रावधान' को फिर शामिल करने की मांग की। यह प्रावधान 1996 की संधि में नहीं रखा गया था। गारंटी प्रावधान का मतलब है कि निचले हिस्से वाले देश को पानी की न्यूनतम मात्रा मिलने की गारंटी हो। इसका उद्देश्य सूखे मौसम या नदी का जलस्तर अचानक घटने पर पानी की आपूर्ति को सुरक्षित रखना है।

बांग्लादेश का कहना है कि मौजूदा संधि सबसे सूखे मौसम में पर्याप्त पानी की गारंटी नहीं देती। उसकी आपत्ति यह भी है कि पानी बांटने का मौजूदा तरीका पुराने जलवैज्ञानिक हालात पर आधारित है। सूखे मौसम में नदी का प्रवाह अब ज्यादा अनिश्चित हो गया है। बांग्लादेश पर्यावरण से जुड़े प्रावधानों को भी अपर्याप्त मानता है। वह ऊपरी हिस्से में पानी की निकासी, नदी के स्वास्थ्य, बढ़ती लवणता और पारिस्थितिक प्रवाह को भी चर्चा में शामिल करना चाहता है।

**क्या फरक्का बैराज फिर बनेगा विवाद का केंद्र :** भारत-बांग्लादेश जल संबंधों में फरक्का बैराज लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत द्वारा बनाए गए इस बैराज का उद्देश्य गंगा के पानी के एक हिस्से को हुगली नदी तंत्र की ओर मोड़ना है। बांग्लादेश में इसे लेकर लंबे समय से चिंता रही है कि इससे सूखे मौसम में नीचे की ओर पानी का प्रवाह कम होता है। अनी ने कहा कि बांग्लादेशी लोग लंबे समय से फरक्का बैराज को 'मौत का जाल' मानते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि फरक्का के बाद भारत ने गंगा पर बैराज और करीब 900 तटबंध बनाए, जिससे दोनों देशों के संबंधों पर दबाव पड़ा।

**भारत का रुख क्या :** भारत का कहना है कि फरक्का बैराज बांध नहीं, बल्कि पानी को मोड़ने वाली संरचना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इसके द्वारों की व्यवस्था के जरिए गंगा के करीब 40,000 क्यूसेक पानी को फरक्का नहर में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी पानी बांग्लादेश की ओर बहता रहता है। भारत यह भी कहता है कि समझौते के तहत जल प्रवाह का आंकड़ा संयुक्त नदी आयोग के जरिए बांग्लादेश के साथ नियमित रूप से साझा किया जाता है। बांग्लादेश और भारत के बीच 54 प्रमुख नदियां साझा हैं। गंगा दोनों देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा-पार नदियों में से एक है। जल बंटवारे और नदी से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश संयुक्त नदी आयोग के जरिए बातचीत करते हैं।

**क्या भारत जल्द शुरू करेगा नई संधि पर बातचीत :** जुलाई में भारत की विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर बिना और देरी के बातचीत शुरू करने को कहा था। समिति ने सिफारिश की थी कि बातचीत में नए जलवैज्ञानिक आंकड़ों, जलवायु अनुमानों और पश्चिम बंगाल तथा बिहार की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। भारत सरकार ने फरवरी में संसद को बताया था कि संधि के नवीनीकरण को लेकर बांग्लादेश के साथ बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। सरकार ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार सहित संबंधित पक्षों से मिले सुझावों को भारत का रुख तय करते समय ध्यान में रखा गया है। अनी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब इससे दो दिन पहले उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश तीस्ता नदी के लंबे समय से लंबित जल-बंटवारा समझौते को लेकर भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने भारत से अपने हितों के साथ बांग्लादेश के हितों को भी ध्यान में रखने की अपील की थी।

# नताली हार्प बनीं ट्रंप की सबसे भरोसेमंद साथी, कैमरे से दूर रहकर कैसे बढ़ा व्हाइट हाउस में असर

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कई ताकतवर लोग हैं, लेकिन 35 वर्षीय नताली हार्प की भूमिका अलग नजर आती है। वह कैमरे के सामने बोलने वाली अधिकारी नहीं हैं, फिर भी ट्रंप के आसपास लगातार दिखाई देती हैं। ओवल ऑफिस से लेकर मरीन वन तक वह राष्ट्रपति के साथ रहती हैं। खास तौर पर प्रेस सचिव रहीं केरोलिन लेविट की विदाई के बाद व्हाइट हाउस में हार्प की अहमियत और बढ़ने की बात सामने आई है।

**नताली हार्प को ह्यूमन प्रिंटर क्यों कहा जाता है :** हार्प ट्रंप के लिए लगातार जानकारी जुटाने, विश्व नेताओं से संदेशों के आदान-प्रदान और सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करने में मदद करती हैं। वह देर रात तक राष्ट्रपति के साथ काम करती हैं और रविवार को भी छुट्टी नहीं लेने की बात सामने आई है। उनके पास एक पोर्टेबल प्रिंटर भी रहता है। इसी वजह से व्हाइट हाउस में उन्हें 'ह्यूमन प्रिंटर' कहा जाता है। वह ट्रंप तक सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया की जानकारी तुरंत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं।

**ट्रंप के साथ खतरनाक सफर में भी क्यों रहीं :** नताली की भूमिका उस समय भी चर्चा में आई जब वह एक बेहद गुप्त अभियान का हिस्सा बनीं। इस अभियान में हमले के खतरे के बीच ट्रंप और कुछ चुनिंदा लोगों को तुर्किये से सुरक्षित

निकालने की कोशिश की गई थी। इसके लिए विमान के कैटरिंग कंटेनर का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद हार्प की भूमिका ज्यादा लोगों की नजर में आई। ट्रंप के करीबी सहयोगियों के अनुसार, राष्ट्रपति के प्रति उनकी निष्ठा बेहद मजबूत है।

**ट्रंप से नताली का रिश्ता इतना खास कैसे बना :** हार्प की ट्रंप से नजदीकी का एक निजी कारण भी बताया जाता है। वह कैंसर से जूझ चुकी हैं। उनके अनुसार, ट्रंप की ओर से समर्थित 'राइट टू ट्राई' कानून ने उन्हें प्रयोगात्मक इलाज तक पहुंच दिलाने में मदद की और इससे उनकी जिंदगी बचाने में मदद मिली। ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि दूसरे कर्मचारी भविष्य में उनका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन नताली ऐसा नहीं करेंगी। यही निजी अनुभव दोनों के बीच भरोसे की एक वजह माना जाता है। हाल ही में सामने आए पत्रों में नताली ने ट्रंप के प्रति अपनी बेहद गहरी निष्ठा जाहिर की थी।

# यूएनएससी में भारत की दो टूक: विकासशील देशों को मिले अधिक प्रतिनिधित्व, आतंकवाद पर राजनीति को लेकर क्या कहा

**संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी।** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के काम करने के तरीकों पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में भारत की राजदूत योजना पटेल ने देश का पक्ष रखा।उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में सार्थक योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को दस्तावेजों तक पहुंच के मामले में एक जैसे अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

**राजदूत योजना पटेल ने क्या कहा :** योजना पटेल ने कहा कि जो देश सीधे तौर पर किसी मुद्दे से जुड़े हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद के फैसले लेने की व्यवस्था में भी शामिल किया जाना चाहिए। खासकर शांति स्थापना से जुड़े सभी बड़े सवालों में उनकी भूमिका होनी चाहिए। इनमें मिशन का काम क्या होगा और उसके लिए कितने संसाधन दिए जाएंगे जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज संख्या- 507 में उचित बदलाव किया जाना चाहिए। इसमें सुरक्षा परिषद की सहायक संस्थाओं के अध्यक्षों के नाम तय करने के लिए स्पष्ट और अंतिम समय-सीमा होनी चाहिए। यह समय-सीमा ऐसी होनी चाहिए, जिस पर कोई समझौता न हो सके।

**आतंकवाद पर राजनीति को लेकर क्या कहा :** भारत ने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद को छोटे और सीमित राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का मंच नहीं बनना चाहिए। योजना पटेल ने कहा कि सुरक्षा परिषद में किसी देश की मौजूदगी का इस्तेमाल आतंकवादियों को वैध ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक कारणों के आधार पर आतंकियों को आतंकवादी सूची से हटाने या दूसरी संस्थाओं को आतंकवादी संगठन घोषित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसके लिए निष्पक्ष मापदंड और समर्थन करने वाले दस्तावेज होना जरूरी है।

# अमेरिका में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, भागवत के यूएस दौरे पर यूएससीआईआरएफ सख्त; बोला- संघ नेताओं को न मिले सम्मान

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली सलाहकार संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान न दे और न ही उनके साथ किसी तरह की हाई-लेवल मीटिंग करे। यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से पहले आया है। वहीं, भारत पहले ही यूएससीआईआरएफ की रिपोर्टों को पक्षपातपूर्ण और वैचारिक पूर्वाग्रह पर आधारित बताते हुए खारिज कर चुका है। आरएसएस नेताओं से दूरी बनाने की अपील यूएससीआईआरएफ के चेयरमैन

आसिफ महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। उन्होंने आरएसएस को एक %अंब्रेला ऑर्गनाइजेशन यानी ऐसा मुख्य संगठन बताया, जिसके सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। महमूद की ये टिप्पणियां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ हफ्ते पहले सामने आई हैं। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग की ओर से आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन (एकता का उत्सव) में शामिल होने वाले हैं। आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध की मांग यूएससीआईआरएफ कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा कि आरएसएस नेताओं को, भले ही वे भारत सरकार से जुड़े हों, हाई-लेवल मीटिंग या राजनयिक सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, अमेरिकी सरकार को उन आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ यानी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। यूएससीआईआरएफ ने आसिफ महमूद और जीन मिल्स की इन टिप्पणियों को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। महमूद ने आरएसएस को लेकर क्या कहा महमूद ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। यह भारत का एक मुख्य संगठन है, जिसके सहयोगी समूहों ने ईसाइयों और मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। अब आरएसएस नेता मोहन भागवत अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी उठाए सवाल एडवोकेसी ग्रुप हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि मोहन भागवत के दौरे को मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आरएसएस नेटवर्क से जुड़े हिंसा के आरोपों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

# विदेशों का नया ट्रेंड भारत की पुरानी जीवनशैली है ब्रिटेन-अमेरिका के जेन-जी अपना रहे भारतीय साइलेंट वॉक

**लंदन, एजेंसी।** अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों में जेन-जी के बीच इन दिनों साइलेंट वॉकिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसमें युवा मोबाइल फोन को दूर रखकर, ईयरफोन उतारकर और बिना संगीत या पॉडकास्ट सुने चुपचाप टहलते हैं। सोशल मीडिया पर इसे तनाव कम करने और मानसिक सुकून पाने के तरीके के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि भारतीयों के लिए यह तरीका उतना नया नहीं है, क्योंकि यहां मौन और एकांत में टहलने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है।

**क्या है साइलेंट वॉकिंग और युवा इसे क्यों अपना रहे हैं :** साइलेंट वॉकिंग का मतलब बिना किसी डिजिटल गतिविधि के पैदल चलना है। इस दौरान मोबाइल, संगीत, पॉडकास्ट, ऑडियोबुक और सोशल मीडिया से दूरी बनाई जाती है। व्यक्ति केवल अपने कदमों, विचारों और

आसपास के वातावरण पर ध्यान देता है। लगातार फोन और इंटरनेट से जुड़े रहने वाली युवा पीढ़ी के लिए यह तरीका कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनाने का अवसर देता है। इसे तनाव कम करने और मन को शांत करने के एक आसान तरीके के रूप में देखा जा रहा है। क्या भारत में यह परंपरा पहले से मौजूद है भारत में मौन और एकांत को मानसिक शांति से जोड़ने की परंपरा सदियों पुरानी है। मंदिरों की परिक्रमा, मौन व्रत और विपश्यना जैसे अभ्यासों में बाहरी शोर से दूरी बनाकर आत्मचिंतन पर जोर दिया जाता है। मंदिर परिसरों और पार्कों में चुपचाप टहलना भी भारतीय जीवनशैली का हिस्सा रहा है। इसलिए पश्चिमी देशों में साइलेंट वॉकिंग का बढ़ता चलन भारतीय नजरिए से किसी बिल्कुल नई चीज के बजाय पुरानी परंपरा के आधुनिक रूप जैसा दिखाई देता है।

**क्या भारतीय युवा भी इसे अपना रहे हैं :** भारत में भी युवा बिना ईयरफोन और मोबाइल में व्यस्त हुए सार्वजनिक जगहों पर टहलते नजर आ रहे हैं। दिल्ली का लोधी गार्डन, बंगलूरू का कब्बन पार्क और मुंबई का मरीन ड्राइव ऐसे स्थान हैं, जहां लोग चहलकदमी करते हैं। हालांकि भारत में इसे हमेशा साइलेंट वॉकिंग के नाम से नहीं जाना जाता। पश्चिम में इसके लिए एक नया नाम और सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है, जबकि भारत में इसके पीछे की आदत और विचार लंबे समय से मौजूद हैं।

**2023 में सोशल मीडिया पर कैसे लोकप्रिय हुआ यह नाम :** साइलेंट वॉकिंग की अवधारणा पुरानी है, लेकिन इसका नाम 2023 में सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुआ। टिकटॉक क्रिएटर मैडी माओ ने बिना फोन, संगीत और पॉडकास्ट के 30 मिनट टहलने का अपना अनुभव साझा किया था। इसके बाद यह तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। धीरे-धीरे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और बेल्जियम समेत कई पश्चिमी देशों के युवाओं ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। साइलेंट वॉकिंग के बढ़ते चलन में डिजिटल दुनिया से थोड़ी देर दूरी बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है।

# ईरान पर होगी सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई: ट्रंप ने दी धमकी, मदद करने वाले देशों को चेताया; क्या बढ़ेगा तनाव

**वाशिंगटन डीसी, एजेंसी।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का सबसे बड़ा मौका दिया गया था। लेकिन उसने इसे गंवा दिया।

ट्रंप ने कहा, इस्लामी गणराज्य ईरान को किसी समझौते के लिए मुझसे ज्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया। दुख की बात है कि उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उसकी वायु सेना नष्ट हो गई है। उसकी सैन्य फैक्टरियां मलबे में बदल गई हैं। ईरान की मुद्रा बेकार हो गई है और देश बेहद कमजोर स्थिति में है।

**ईरान की मदद करने वाले देशों पर भी कार्रवाई :** ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगा, उसे भी बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसमें वित्तीय संस्थान, कारोबार, हवाई अड्डे और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, नकद लेनदेन, एक्सचेंज हाउस, जहाजों के पंजीकरण और ईरान की मदद करने वाली छिपी हुई (शेल) कंपनियों को तुरंत रोकने की बात कही।

**सहयोगी देशों से अमेरिका के साथ आने की अपील :** ट्रंप ने इसे ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक हमले का दिन बताया। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों से ईरान को अलग-थलग करने और उसके खतरे को खत्म करने में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है।

उन्होंने दावा किया कि ये ऐतिहासिक कदम ईरान को और दुनियाभर में आतंक फैलाने की उसकी क्षमता को बुरी तरह कमजोर कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा।

**अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया :** अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के पिछले हफ्ते इसी तरह बयान दिया था। बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिशें बढ़ाएगा। इस रणनीति में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय %ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी% नाम से प्रतिबंध अभियान भी चला रहा है। इसका मकसद लक्षित कार्रवाई के जरिये ईरान के पैसे जुटाने के स्रोतों को बंद करना है। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमलों के साथ हुई। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने ईरान को सैन्य उपकरण और ड्रोन से जुड़ी तकनीक दी है। वहीं, चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है। चीन ने ईरान के साथ कारोबारी रिश्ते बनाए रखे हैं और उसे कूटनीतिक समर्थन भी दिया है।

# कौन हैं अमेरिका की एफडीए प्रमुख बनने जा रहीं हेड़डी ओवरटन, ट्रंप ने किया नामित, विवादों से भी रहा है नाता

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ अधिकारी डॉ. हेइडी ओवरटन को खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए का अगला आयुक्त बनाने के लिए नामित किया है। अगर अमेरिकी सीनेट उनकी नियुक्ति को मंजूरी देती है, तो वह इस बेहद महत्वपूर्ण संस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी। एफडीएअमेरिका में दवाओं, वैक्सीन, चिकित्सा उपकरणों और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और नियमन से जुड़े बड़े फैसले करता है। ओवरटन फिलहाल व्हाइट हाउस के घरेलू नीति परिषद में उपनिदेशक के पद पर हैं और ट्रंप प्रशासन की स्वास्थ्य नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं।

**ओवरटन की पढ़ाई और करियर कितना मजबूत :** हेइडी ओवरटन मेडिकल डॉक्टर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से मेडिकल की पढ़ाई की। इसके बाद जॉन्स हॉपकिन्स में जनरल सर्जरी का प्रशिक्षण लिया और क्लिनिकल जांच से जुड़ी उच्च शिक्षा भी हासिल की। ट्रंप प्रशासन में आने से पहले वह कंजर्वेटिव थिंक टैंक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में मुख्य नीति अधिकारी के रूप में काम कर चुकी हैं। यानी उनका अनुभव केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य नीति और राजनीतिक प्रशासन से भी जुड़ा रहा है।

**ट्रंप के भरोसेमंद लोगों में कैसे शामिल हुईं :** दूसरे कार्यकाल में ओवरटन ट्रंप की कई स्वास्थ्य योजनाओं में उनके साथ दिखाई दी हैं। दवा की कीमत कम करने, नई दवाओं को तेजी से मंजूरी देने और स्वास्थ्य नीति में बदलाव से जुड़े कई कार्यक्रमों में उन्होंने भूमिका निभाई है। ट्रंप ने उनके नाम की घोषणा करते हुए उन्हें बेहद सक्षम और भरोसेमंद अधिकारी बताया तथा तेज इलाज, चिकित्सा नवाचार और दवाओं की कम कीमत जैसे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने भी ओवरटन के फैसले लेने की क्षमता और प्रशासनिक अनुशासन की तारीफ की है।

**वैक्सीन नीति को लेकर क्यों उठे सवाल :** ओवरटन की नियुक्ति का

सबसे विवादित पक्ष उनकी वैक्सीन नीति से जुड़ी भूमिका है। हाल में वह उस कार्यक्रम में ट्रंप के साथ खड़ी थीं, जिसमें बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की गई थी। इसमें खसरा, कण्ठमाला और रूबेला यानी एमएमआर वैक्सीन को अलग-अलग टीकों में बांटने की योजना भी शामिल थी। चिकित्सा जगत के कई लोगों ने इस नीति पर सवाल उठाए हैं। इसी वजह से ओवरटन की एफडीएमें संभावित भूमिका को लेकर वैज्ञानिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहस तेज हो गई है।

**गर्भपात की दवाओं पर क्या है ओवरटन का रुख :** ओवरटन गर्भपात की दवाओं को लेकर भी सख्त रुख रखती हैं। वह ऐसी दवाओं की उपलब्धता और ऑनलाइन इस्तेमाल से जुड़ी मौजूदा व्यवस्था की आलोचना कर चुकी हैं। अगर सीनेट से उनकी नियुक्ति मंजूर होती है, तो स्नष्ठ के सामने गर्भपात की दवाओं से जुड़े नियमों की समीक्षा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अमेरिका में गर्भपात को लेकर पहले से ही राजनीतिक और कानूनी विवाद चल रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर ओवरटन के फैसलों पर खास नजर रहेगी।

**एफडीएको संभालते ही किन बड़ी चुनौतियों का सामना होगा :** ओवरटन ऐसे समय एफडीए की कमान संभाल सकती हैं, जब संस्था पहले ही नेतृत्व और कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है। पूर्व आयुक्त डॉ. मार्टी मकारी ने मई में पद छोड़ दिया था। उनके कार्यकाल में ई-सिगरेट, गर्भपात की दवाओं और नई दवाओं की मंजूरी जैसे मुद्दों पर विवाद रहे। एफडीए में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के जाने से भी संस्था पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में नई प्रमुख से प्रशासनिक स्थिरता और जनता का भरोसा बहाल करने की उम्मीद होगी।

**क्या दवाओं की मंजूरी का तरीका भी बदल सकता है :** एफडीए की एक बड़ी जिम्मेदारी नई दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की जांच तथा मंजूरी देना है। ट्रंप प्रशासन तेज मंजूरी और चिकित्सा नवाचार को बढ़ावा देने की बात करता रहा है। दूसरी ओर, एफडीए से जुड़े वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुरक्षा मानकों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देते हैं। ओवरटन को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। खासकर दुर्लभ बीमारियों की दवाओं, जैव-तकनीकी उत्पादों और नई चिकित्सा तकनीकों से जुड़े फैसले उनके सामने महत्वपूर्ण चुनौती होंगे। एफडीए केवल दवाओं और वैक्सीन तक सीमित नहीं है। खाद्य सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने अल्ट्राप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं।

Printed, Published and Owned by SARABJIT MAKAN and Printed by ILEVAN HASMUKHRAI THAKAR Printed at Jay Graphics & Printers, C/15, Vikram Chambers, Ashram Road, Ahmedabad - 380009. and published from F/1 first floor, rajas apartment, near old railway crossing, maninagar east maninagar, Ahmedabad, Gujarat-380008. Editor SARABJIT MAKAN, Mo.: 9638877700, 9662420070.